धनबाद
शुक्रवार 13.03.2026
मूल्य- ₹ 2.50
वर्ष-32 अंक-20 पृष्ठ- 12
चैत्र कृष्ण पक्ष-10
संवत 2082

झारखण्ड से प्रकाशित सर्वाधिक लोकप्रिय दैनिक
बिहार ऑब्जर्वर

संपादकीय

भारत खोज रहा नए ऊर्जा विकल्प

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध में एक ओर इजराइल-अमेरिका की तरफ से हमले में ईरान के तेल उत्पादन केंद्रों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर ईरान के जवाब की जद में भी कतर, बहरीन और सऊदी अरब जैसे खाड़ी के कई तेल उत्पादक देश आ रहे हैं। इसके अलावा, ईरान ने होर्मुज समुद्री मार्ग को जिस तरह बाधित कर दिया है, उसका मुख्य असर तेल की आपूर्ति पर पड़ना शुरू हो चुका है।

हमलों की तीव्रता अगर बनी रही, तो केवल भारत नहीं, समूचे एशिया में तेल और गैस की कीमतें काफी बढ़ सकती हैं। एशिया के कई विकासशील देश शायद इसका बोझ नहीं उठा पाएंगे और नतीजतन उन्हें अपने यहां तेल और गैस की मांग को घटाने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में भारत के सामने भी अपने तेल और गैस की जरूरत भर आपूर्ति को बनाए रखने की बहुस्तरीय चुनौती आ खड़ी हुई है। तेल खरीद के मोर्चे पर भारत जिन नई परिस्थितियों से दो-चार है, उसमें अब स्वाभाविक ही नए विकल्प तैयार करना वक्त का तकाजा है।

दरअसल, व्यापार समझौते में अमेरिका ने जिस तरह भारत के सामने रूस से तेल नहीं खरीदने की शर्त लगाई, उससे स्थितियां ज्यादा जटिल हुई। मगर युद्ध की वजह से पैदा हुई नई परिस्थिति में इस संदर्भ में फैसला लेने के लिए भारत स्वाभाविक ही अपनी जरूरतों के मुताबिक कदम बढ़ा रहा है। शायद यही वजह है कि होर्मुज जलडमरूमध्य का रास्ता रोके जाने के बाद पैदा होने वाली स्थिति के मद्देनजर भारत को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रूस या अन्य विकल्प की ओर देखने को लेकर अमेरिका ने नरम रुख

अख्तियार किया है।

गौरतलब है कि भारत में एलएनजी यानी तरल प्राकृतिक गैस का पचास फीसद खाड़ी देशों से आता है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन और खाद बनाने में किया जाता है। इसी तरह एलपीजी का साठ फीसद इन्हीं देशों से आता है। मगर जब से ईरान ने होर्मुज समुद्री मार्ग को बाधित किया है, तब से तेल और गैस की सहज आपूर्ति पर इसका व्यापक असर पड़ा है। हमले के कई दिनों बाद भी दोनों पक्षों की ओर से युद्ध विराम के लिए किसी तरह की पहल करने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में दुनिया के एक बड़े हिस्से में तेल और गैस का संकट खड़ा हो सकता है।

हालांकि भारत के पास अगले करीब दो महीने के लिए अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त भंडार है, लेकिन अभी जिस तरह युद्ध के लंबा खिंचने की आशंका दिख रही है, उसके मद्देनजर पूर्व तैयारी की जरूरत है। इसी वजह से भारत ने अब अपनी ऊर्जा खरीद की रणनीति में काफी बदलाव किया है, ताकि किसी एक रास्ते के बाधित होने पर आपातकालीन आपूर्ति भी बाधित होने की स्थिति न पैदा हो।

फिलहाल भारत ने जहां रूस से तेल खरीदने का रास्ता खुला रखा है, वहीं अब इसके सामने पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका, मध्य एशिया और कई अन्य देशों से आपूर्ति को सहज बनाए रखने का विकल्प है।

इसके अलावा, आस्ट्रेलिया और कनाडा सहित कई अन्य देशों ने भी गैस आपूर्ति की पेशकश की है और मौजूदा संकट को देखते हुए भारत अपनी ऊर्जा साझेदारी के दायरे में विस्तार कर रहा है। जाहिर है, मुश्किल वक्त में भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के नए रास्ते तैयार किए हैं और उम्मीद है कि युद्ध की वजह से उपजे संकट की मार आम लोगों पर नहीं पड़ेगी।

बालेंद्र शाह की जीत से असली बदलाव की उम्मीद

नेपाल में हुए चुनाव के नतीजे आने के बाद देश की राजनीतिक तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। नई पीढ़ी के अगुआ बने बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने कई दिग्गजों और पुरानी पार्टियों को भारी शिकस्त दी है। अगर सब कुछ उम्मीद के अनुरूप हुआ और बालेंद्र शाह को ही नेता चुना गया, तो नेपाल के संसदीय इतिहास में वे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे। अब तक वहां जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, वे कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। माना जा रहा है कि दो-तिहाई सीटों पर जीत के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल कर चुकी आरएसपी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। देश में पिछले दिनों हुए चुनावों में नागरिकों और विशेषकर युवा वर्ग ने इस पार्टी पर जिस तरह भरोसा किया है, उसके मद्देनजर नेपाल में भावी सरकार के सामने जन आकांक्षाओं को पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। वहीं नई सरकार को घेरलू समस्याओं से निपटने के साथ देश के आर्थिक विकास में आए ठहराव को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसे पड़ोसी देशों खासकर इंडिया से संबंध बेहतर बनाने के भी प्रयास करने होंगे। पुरानी सरकार के कामकाज के जिस तरीके के खिलाफ वहां युवा वर्ग के भीतर व्यापक आक्रोश पैदा हुआ, उसे बदलना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। नेपाल के लोगों का मानना है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेंद्र शाह के भीतर देश की राजनीति और नीतियों को बदल सकने की क्षमता है। दरअसल, शाह को महापौर के अपने कार्यकाल में जमीनी स्तर पर सुधार के कई कार्यों के लिए जाना जाता है। चुनावी नतीजों के बाद अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने के साथ व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव करेंगे। नई सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती रोजगार सृजन की भी होगी। नेपाल में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और बड़ी संख्या में वहां के युवा वर्षों से काम के लिए पलायन करते रहे हैं। बहरहाल, नेपाल में छह महीने पहले व्यवस्था में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर नई पीढ़ी के व्यापक आंदोलन से उभरे बालेंद्र शाह और उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सबकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे, देश को किस तरह की वैकल्पिक राजनीति देंगे, यह देखने की बात होगी।

आज का कार्टून

नीतिश कुमार ने शुरू की समृद्धि यात्रा...

एआइ की दौड़ में कौन जीतेगा शक्ति की बाजी...

> एआइ के विकास ने बड़ी तकनीकी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली भूमिका प्रदान की है। उनके मंच, क्लाउड नेटवर्क और उन्नत एआइ माडल करोड़ों उपयोगकर्ताओं, वित्तीय लेन-देन और सूचना प्रवाह को संचालित करते हैं। इस कारण उनकी नीतियां और तकनीकी निर्णय अनेक देशों की अर्थव्यवस्था, मीडिया संरचना और यहां तक कि सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं। मगर यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि ये कंपनियां पूर्णतः स्वायत्त इकाइयां नहीं हैं। वे राष्ट्रीय कानूनों, डेटा संरक्षण नियमों, प्रतिस्पर्धा आयोगों और निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं से बंधी रहती हैं। अमेरिका और चीन के बीच चल रही तकनीकी प्रतिस्पर्धा इसका स्पष्ट उदाहरण है। उन्नत एआइ चिप और सेमीकंडक्टर उपकरणों के निर्यात पर लगाए गए नियंत्रण यह दर्शाते हैं कि अंतिम नियामक शक्ति अभी भी राष्ट्र-राज्य के पास है।

धीरज यादव

चौथी औद्योगिक क्रांति के इस दौर में कृत्रिम मेधा (एआइ) केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं रह गई है, बल्कि यह उत्पादन, शासन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की केंद्रीय शक्ति बनती जा रही है। स्वचालन, मशीन लर्निंग और डेटा विश्लेषण पर आधारित प्रणालियां विनिर्माण से लेकर सेवा क्षेत्र तक उत्पादकता की प्रकृति बदल रही हैं। सैन्य क्षेत्र में स्वायत्त प्रणालियां, खुफिया विश्लेषण और निगरानी तकनीक रणनीतिक क्षमता को प्रभावित कर रही हैं। साइबर सुरक्षा में हमलों की पहचान और रोकथाम के लिए एआइ आधारित तंत्र अनिवार्य होते जा रहे हैं।

इन सभी आयामों का मूल तत्त्व है डेटा और उसे संसाधित करने की क्षमता। कृत्रिम मेधा को अब केवल साफ्टवेयर के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह ऊर्जा, तेल या सेमीकंडक्टर की तरह एक रणनीतिक संसाधन का रूप ले चुकी है। जिस इकाई के पास उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग अवसंरचना, विशाल डेटा भंडार और उन्नत 'एल्गोरिद्म' क्षमता है, वह आर्थिक और सामरिक निर्णयों पर प्रभाव डाल सकती है। इस बदलते परिदृश्य में शक्ति का पारंपरिक संतुलन केवल सैन्य या भौगोलिक कारकों से निर्धारित नहीं होगा, बल्कि तकनीकी दक्षता और डिजिटल अवसंरचना भी उसकी दिशा तय करेगी।

अब कृत्रिम मेधा का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। विनिर्माण, साजो-सामान, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में एआइ आधारित स्वचालन तथा विश्लेषण से उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की रपटें यह बताती हैं कि डेटा विश्लेषण एवं मशीन 'लर्निंग' से निर्णय प्रक्रिया तेज होती है और संसाधनों का उपयोग अधिक कुशल बनता है। इससे पूंजी निर्माण की प्रकृति भी बदल रही है। पारंपरिक भौतिक संपत्तियों की तुलना में अब डेटा, एल्गोरिद्म और कंप्यूटिंग क्षमता नई पूंजी के रूप में उभर रहे हैं।

इस परिवर्तन का एक महत्त्वपूर्ण आयाम सेमीकंडक्टर उद्योग और 'क्लाउड' अवसंरचना है। उन्नत चिप निर्माण और उच्च क्षमता वाले डेटा सेंटर एआइ विकास की आधारशिला हैं। जिन देशों और कंपनियों के पास अत्याधुनिक चिप डिजाइन, विनिर्माण क्षमता और वैश्विक क्लाउड नेटवर्क हैं, वे तकनीकी मूल्य शृंखला के ऊपरी हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था में कुछ बड़े वैश्विक मंचों का केंद्रीकरण यह दर्शाता है कि डेटा और नेटवर्क प्रभाव से बाजार संरचना सिमट सकती है।

जाहिर है, जिनके पास उन्नत एआइ माडल, व्यापक डेटा संसाधन और उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग अवसंरचना है, वही वैश्विक मूल्य शृंखला के निर्णायक बिंदुओं पर प्रभाव रखते हैं। इससे आर्थिक शक्ति की पारंपरिक परिभाषा का विस्तार हुआ है, जिसमें तकनीकी क्षमता और डिजिटल नियंत्रण केंद्रीय तत्त्व बनते जा रहे हैं। इस आर्थिक संरचना ने तकनीकी कंपनियों की भूमिका को भी असाधारण रूप से विस्तारित किया है।

एआइ के विकास ने बड़ी तकनीकी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली भूमिका प्रदान की है। उनके मंच, क्लाउड नेटवर्क और उन्नत एआइ माडल करोड़ों उपयोगकर्ताओं, वित्तीय लेन-देन और सूचना प्रवाह को संचालित करते हैं। इस कारण उनकी नीतियां और

तकनीकी निर्णय अनेक देशों की अर्थव्यवस्था, मीडिया संरचना और यहां तक कि सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं। मगर यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि ये कंपनियां पूर्णतः स्वायत्त इकाइयां नहीं हैं। वे राष्ट्रीय कानूनों, डेटा संरक्षण नियमों, प्रतिस्पर्धा आयोगों और निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं से बंधी रहती हैं।

अमेरिका और चीन के बीच चल रही तकनीकी प्रतिस्पर्धा इसका स्पष्ट उदाहरण है। उन्नत एआइ चिप और सेमीकंडक्टर उपकरणों के निर्यात पर लगाए गए नियंत्रण यह दर्शाते हैं कि अंतिम नियामक शक्ति अभी भी राष्ट्र-राज्य के पास है। इसी प्रकार यूरोप में डिजिटल बाजार कानून और डेटा संरक्षण विनियम तकनीकी कंपनियों के संचालन पर प्रभाव डालते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि निगमित शक्ति और राज्य शक्ति के बीच सीधा प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि एक जटिल अंतर-संबंध विकसित हो रहा है।

वर्तमान परिदृश्य में यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि निगमित और राज्य के बीच शक्ति संतुलन का नया समीकरण बन रहा है। तकनीकी नवाचार और पूंजी निगमित संरचनाओं में केंद्रित हैं, जबकि वैधानिक अधिकार और सामरिक नीति निर्माण राष्ट्र या राज्य के हाथ में है। भविष्य की कृत्रिम मेधा इसी अंतःक्रिया से आकार ले सकती है, जहां तकनीकी क्षमता और राजनीतिक संप्रभुता एक-दूसरे को प्रभावित करती रहेंगी।

एआइ का सैन्य और रणनीतिक आयाम इस विमर्श को और गंभीर बनाता है। अनेक देश स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त हथियार प्रणालियों पर शोध कर रहे हैं, जिनमें लक्ष्य पहचानने, निगरानी और निर्णय में सहायता के लिए मशीन लर्निंग आधारित प्रणालियां प्रयोग में लाई जा रही हैं। रक्षा विश्लेषण और खुफिया जांच में एआइ आधारित डेटा प्रोसेसिंग से विशाल सूचना का त्वरित आकलन संभव हुआ है। इससे युद्ध क्षेत्र की समझ और प्रतिक्रिया समय, दोनों प्रभावित होते हैं।

जटिल साइबर हमलों की पहचान, नेटवर्क असमानताओं का विश्लेषण और स्वचालित रक्षा तंत्र अब एल्गोरिद्मिक प्रणालियों पर आधारित हैं। दूसरी ओर, आक्रामक साइबर क्षमताओं में भी स्वचालित उपकरणों का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे डिजिटल अवसंरचना रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गई है।

इसके साथ ही निगरानी प्रणालियों और डेटा विश्लेषण के माध्यम से राज्य अपनी आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक गतिविधियों पर अधिक व्यापक नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। चेहरा पहचान तकनीक, व्यवहार विश्लेषण और संचार निगरानी जैसी व्यवस्थाएं सार्वजनिक नीति और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन का प्रश्न उठाती हैं। इस प्रकार कृत्रिम मेधा केवल आर्थिक शक्ति का साधन नहीं, बल्कि सैन्य और सामरिक संरचना का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, जो वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा को प्रभावित कर सकता है।

वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत की स्थिति विशिष्ट है। पिछले एक दशक में देश ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का एक ऐसा माडल विकसित किया है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित हुआ है। आधार, यूपीआइ और डिजिटल पहचान तंत्र ने सेवा वितरण, वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता में संरचनात्मक बदलाव किया है।

यह ढांचा एआइ अनुप्रयोगों के लिए एक आधार प्रदान करता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर डिजिटल लेन-देन और डेटा प्रवाह नवाचार की संभावनाएं खोलते हैं। इसके साथ ही डेटा संप्रभुता का प्रश्न गंभीर होता जा रहा है। यदि भारतीय नागरिकों और संस्थानों से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण और मूल्य सृजन किसी विदेशी मंच पर केंद्रित रहता है, तो आर्थिक लाभ और रणनीतिक नियंत्रण दोनों सीमित हो सकते हैं। इसलिए यह बहस केवल गोपनीयता की नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक हित से भी जुड़ी हुई है।

समकालीन विश्व व्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां शक्ति की परिभाषा विस्तार ले रही है। पारंपरिक रूप से सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव को शक्ति का प्रमुख आधार माना जाता रहा है, मगर अब डेटा, एल्गोरिद्म और उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग अवसंरचना भी उसी श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने चुनौती यह है कि वे एआइ को केवल बाजार शक्ति या सीमित निगमित हित का साधन बनने से कैसे रोकें।

पारदर्शिता, नियमन, प्रतिस्पर्धा नीति और सार्वजनिक निवेश के माध्यम से एआइ को व्यापक सामाजिक हित में रूपांतरित किया जा सकता है। यदि ऐसा संतुलन स्थापित होता है, तो तकनीकी प्रगति लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ कर सकती है। अन्यथा शक्ति का केंद्रीकरण नई असमानताओं को जन्म दे सकता है।

मोजतबा खामेनेई के हाथ आई ईरान की कमान

> ईरान की राजनीति में बड़ा और विवादास्पद मोड़ आ गया है। देश की शक्तिशाली धर्मगुरु परिषद विशेषज्ञ सभा ने आधिकारिक घोषणा करते हुए 56 वर्षीय मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब उनके पिता अली खामेनेई की हाल ही में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य अभियान में मौत हो गई थी। इस घटनाक्रम ने पहले ही पूरे पश्चिम एशिया को संकट में डाल दिया था और अब मोजतबा खामेनेई के सत्ता में आने से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

नीरज कुमार दुबे

हम आपको बता दें कि ईरान में सर्वोच्च नेता का पद देश की सबसे शक्तिशाली संवैधानिक और धार्मिक सत्ता माना जाता है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से यह पद ईरान की राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र रहा है। सर्वोच्च नेता न केवल राज्य का सर्वोच्च मार्गदर्शक होता है बल्कि सेना और सुरक्षा तंत्र पर भी उसका सीधा नियंत्रण होता है। अली खामेनेई लगभग 37 वर्षों तक इस पद पर बने रहे और अब उनके बेटे ने उनकी जगह ले ली है।

हालांकि मोजतबा खामेनेई का नाम वर्षों से ईरान की सत्ता के पीछे सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता रहा है, लेकिन वह सार्वजनिक जीवन में बहुत कम दिखाई देते थे। अपने 55 से अधिक वर्षों के जीवन में उन्होंने अपेक्षाकृत शांत और पर्दे के पीछे रहकर काम करने की रणनीति अपनाई। इसी दौरान उन्होंने ईरान के सुरक्षा तंत्र, धर्मगुरुओं और धनी कारोबारी वर्ग के साथ मजबूत संबंधों का एक विशाल नेटवर्क तैयार कर लिया। साथ ही मोजतबा खामेनेई की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरान पहले से ही युद्ध और अंदरूनी असंतोष से जूझ रहा है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद शुरू हुए संघर्ष ने देश को अस्थिर कर दिया है। दूसरी ओर जनता का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से शासन के खिलाफ नाराज है। हम आपको याद दिला दें कि हाल के समय में कई बड़े विरोध प्रदर्शन हुए जिनमें हजारों लोग सड़कों पर उतरे। जनवरी में महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों ने जल्दी ही सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया था। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार इन प्रदर्शनों में कम से कम सात हजार नागरिक मारे गए।

इसके अलावा, मोजतबा खामेनेई की छवि भी विवादों से घिरी रही है। कई आलोचक उन्हें उस व्यवस्था का प्रतीक मानते हैं जिसके खिलाफ ईरान में जनता का एक वर्ग लगातार आवाज उठा रहा है। उनके पिता के शासनकाल में राजनीतिक विरोधियों और आम नागरिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई तथा आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ईरान में अमीर राजनीतिक परिवारों के बच्चों के लिए प्रचलित शब्द आगाजादे का इस्तेमाल भी अक्सर मोजतबा के संदर्भ में किया जाता है।

मोजतबा खामेनेई की संपत्ति को लेकर भी लगातार चर्चा होती रही है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार उनके पास अरबों डॉलर की संपत्ति है और उन्होंने दुनिया के कई देशों में महंगी संपत्तियों का विशाल जाल खड़ा किया है। हालांकि उनकी वास्तविक कुल संपत्ति का सटीक अनुमान सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन जांच रिपोर्टों में कहा गया है कि उनके नियंत्रण में लक्जरी घरों और होटलों का

बड़ा अंतरराष्ट्रीय पोर्टफोलियो है।

बताया जाता है कि तेहरान से लेकर दुबई और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट तक उनकी संपत्तियां फैली हुई हैं। लंदन के बेहद महंगे इलाके बिशप्स एवेन्यू में भी उनके कई आलीशान घरों का जिक्र सामने आया है। इस इलाके को अक्सर अरबपतियों की लाइन कहा जाता है जहां एक एक घर की कीमत करोड़ों यूरो तक होती है। इसके अलावा यूरोप के कई देशों में पांच सितारा होटलों और उच्च श्रेणी की इमारतों में उनके निवेश की खबरें भी सामने आई हैं। रिपोर्टों के अनुसार मोजतबा खामेनेई आम तौर पर अपनी संपत्तियां सीधे अपने नाम पर नहीं रखते बल्कि कंपनियों और वित्तीय मध्यस्थों के जटिल नेटवर्क के माध्यम से निवेश करते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में तो उनके स्विट्जरलैंड के बैंकों में खाते और ब्रिटेन में करीब 138 मिलियन डॉलर से अधिक कीमत की संपत्ति होने की भी बात कही गई है। कई संपत्तियां ईरानी कारोबारी अली असारी के नाम पर खरीदी गई बताई जाती हैं। ब्रिटेन की सरकार ने अली असारी को ईरान की इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड को आर्थिक समर्थन देने के आरोप में प्रतिबंधित भी किया था।हम आपको यह भी बता दें कि मोजतबा खामेनेई का जन्म सितंबर 1969 में ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ था। उन्होंने अपने शुरुआती युवा वर्ष कुम शहर के धार्मिक शिक्षण केंद्रों में बिताए। ईरान इराक युद्ध के दौरान उन्होंने मोर्चे पर भी समय बिताया और उसी दौर में सुरक्षा प्रतिष्ठान तथा खुफिया तंत्र के कई प्रभावशाली अधिकारियों से उनके संबंध बने। कहा जाता है कि उन्हीं संबंधों ने बाद में उन्हें सत्ता के केंद्र तक पहुंचने में मदद की। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, विशेषज्ञ सभा का यह फैसला ईरान की सत्ता व्यवस्था में एक नए प्रकार की वंशानुगत परंपरा की शुरुआत भी माना जा रहा है। इस्लामी गणराज्य को स्थापना राजशाही के विरोध में हुई थी, इसलिए किसी नेता के बेटे को सर्वोच्च पद मिलना कई धर्मगुरुओं और राजनीतिक वर्ग के भीतर विवाद का कारण बना हुआ है। बताया जाता है कि इस फैसले से पहले सत्ता के शीर्ष नेतृत्व में भी गहरे मतभेद थे और कुछ गुट अंतरिम नेतृत्व परिषद को बनाए रखना चाहते थे।उधर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही मोजतबा खामेनेई के सर्वोच्च नेता बनने का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि खामेनेई का बेटा उन्हें स्वीकार नहीं है और ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो देश में शांति और सामंजस्य ला सके। ट्रंप ने यहां तक कहा कि वह चाहते हैं कि ईरान के अगले नेता के चयन में उनकी भी भूमिका हो। दूसरी ओर, मोजतबा खामेनेई के सत्ता में आने से यह संकेत भी मिला है कि ईरान अपनी कठोर विदेश नीति से पीछे हटने वाला नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि वह अपने पिता की नीति को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका विरोधी रुख और इस्लामी विचारधारा को प्राथमिकता देंगे। साथ ही यह भी आशंका है कि वह अपने पिता, मां और पत्नी की मौत का बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं जो हालिया हवाई हमलों में मारे गए थे। बहरहाल, अब जब मोजतबा खामेनेई ईरान की सत्ता के शिखर पर पहुंच चुके हैं तो पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति पर इसके दूरगामी प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है। एक ओर युद्ध का खतरा बना हुआ है तो दूसरी ओर ईरान के भीतर राजनीतिक असंतोष भी बढ़ सकता है। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि नया सर्वोच्च नेता देश को किस दिशा में ले जाता है।

धनबाद
शुक्रवार 13.03.2026
मूल्य- ₹ 2.50
वर्ष-32 अंक-20 पृष्ठ- 12
चैत्र कृष्ण पक्ष-10
संवत 2082

झारखण्ड से प्रकाशित सर्वाधिक लोकप्रिय दैनिक

बिहार ऑब्जर्वर

झारखंड में कृषि व पशुपालन को मिलेगा बढ़ावा बेकन फैक्ट्री के खुलने से किसानों का होगा विकास

कृषि और पशुपालन क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

रांची (एजेंसी): रांची में कृषि और पशुपालन क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित समारोह में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि ये दोनों समझौते झारखंड के किसानों के सर्वांगीण विकास में दूरगामी और सकारात्मक परिणाम देने वाले साबित होंगे।

मीट प्रोसेसिंग सेक्टर का विकास

पहला एमओयू इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत आईसीएआर-नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद और झारखंड के पशुपालन निदेशालय के बीच हुआ। इस समझौते के तहत रांची के कांके स्थित बेकन फैक्ट्री के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण का रास्ता साफ हुआ है। इसके साथ ही राज्य में मीट प्रोसेसिंग सेक्टर के विकास के लिए तकनीकी सहयोग, आधुनिक प्रसंस्करण तकनीक, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का पालन और स्थानीय उद्यमियों व श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

प्रधान वैज्ञानिक एम मुथुकुमार ने कहा कि यह पहल आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रथाओं के माध्यम से झारखंड के मीट क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगी। पशुपालन निदेशक आदित्य कुमार आनंद ने भी इसे राज्य में मीट उद्योग के व्यापक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

किसानों की आय में होगी वृद्धि

दूसरा एमओयू झारखंड के उद्यान निदेशालय और इंडियन इंस्टीट्यू आफ हार्टिकल्चरल रिसर्च बेंगलुरु के बीच हुआ।

इस समझौते का उद्देश्य राज्य में फल, सब्जी, सजावटी पौधे, औषधीय पौधे और मशरूम जैसी फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है।

कृषि मंत्री ने कहा कि इन पहल से प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने भी इन समझौतों को राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब राज्य से बाहर की तकनीकी छात्राओं को भी मिलेगा

झारखंड कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्ताव पारित

रांची (एजेंसी): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल ४० प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है।

मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब झारखंड के बाहर की तकनीकी महाविद्यालय की छात्राओं को भी मिलेगा। पहले इस योजना का लाभ केवल झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय की छात्राओं को ही मिलता था।

रांची वूमेन'स कॉलेज परिसर में छात्राओं के लिए ५२८ बेड का छात्रावास अब मोराबादी स्थित कल्याण परिषद में बनाया जाएगा।

पलामू जिले के डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब मेदिनीनगर होगा. केंद्र सरकार से सहमति मिलने के बाद राज सरकार ने नाम परिवर्तन संबंधित प्रस्ताव पर आज स्वीकृति दे दी।

राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक एवं पूर्व विधायकों को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की तरह चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी इस व्यवस्था के तहत माननीय की चिकित्सा पर खर्च होने वाली पूरी राशि का भुगतान प्रतिपूर्ति के रूप में सरकार करेगी.

राज्य कर्मियों की सेवा और सेवा निवृत्ति संबंधी विवादों के समाधान के लिए नियमावली का गठन किया गया है। इसमें किसी भी विवाद या समस्या के समाधान के लिए समय सीमा और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। निचले स्तर पर किए गए समाधान से संतुष्ट न होने पर अपीलीय प्राधिकारी का भी गठन किया गया है। इस पर अधिकार में संबंधित कर्मी अपनी बात रख सकेंगे।

राज्य की महिला कर्मियों को शिशु देखभाल के लिए अब पहले साल १०० फीसदी और दूसरे साल ८० फीसदी वेतन मिलेगा।

देवघर छोड़ राज्य के २३ जिलों में ८०० सीटों की क्षमता वाले पुस्तकालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। रांची के एसएस मेमोरियल कॉलेज के लिए ४८ करोड़, चक्रधरपुर कॉलेज के लिए ८८ करोड़, गोड्डा के महिला कॉलेज के लिए ६९ करोड़ एवं गोड्डा के ही बोआरीजोर में डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण के लिए दी गयी ४० करोड़ की स्वीकृति

किसानों के खाते में आज आएंगे 2000

नई दिल्ली (ईएमएस): केंद्र सरकार १३ मार्च को देशभर के करोड़ों किसानों को सौगात देने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम की राजधानी गुवाहाटी से किसान सम्मान निधि योजना की २२वीं किस्त जारी करेगी। देशभर के ९ करोड़ २३ लाख से अधिक किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए २-२ हजार रुपये भेजे जाएंगे। पीएम किसान योजना की २२वीं किस्त में कुल १८६४० करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजे जाएंगे। पीएम किसान योजना की २२वीं किस्त का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर सही और अपडेटेड है। जिसमें ई-केवायसी, बैंक डिटेल्स एवं जमीन के कागज अपडेट होने जरूरी हैं। ऐसे में किसानों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम एवं स्टेटस चेक कर लेना चाहिए।

एलपीजी संकट पर पीएम मोदी ने लोगों से की अपील, शांति बनाए रखें और पैनिक न करें

कोरोना महामारी के दौर का उदाहरण देकर कहा कि इस संकट से उबर जाएंगे

नई दिल्ली (ईएमएस): देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर फैली अफवाहों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से शांति बनाए रखने और पैनिक न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण ऊर्जा की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, लेकिन हमारी सरकार संकट से निपटने में सक्षम है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में एनडीए की मीटिंग के दौरान सभी से सही जानकारी साझा करने और बिना पुष्टि के अफवाहें न फैलाने का आग्रह किया।

वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एलपीजी सप्लाई पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाए हैं। मंत्रालय का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पहले की तरह जारी है और पैनिक खरीद से स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों में जिला प्रशासन लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दे रहा है। केंद्र सरकार ने पहले ही एस्मा लागू किया है, इसके तहत घरेलू गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाती है और बीते छह महीनों के औसत के अनुसार सप्लाई बनाए रखने का निर्देश है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ मिलकर फैक्ट चेक करने और सही सूचना देने का काम शुरु कर दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था और अफवाहों से उत्पन्न हालात को संभालने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं।

वहीं पीएम मोदी ने कोरोना महामारी ▶▶ 8

सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए विपक्ष लामबंद

200 से अधिक सांसदों ने नोटिस पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली (ईएमएस): मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए २०० से अधिक सांसदों ने एक नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे शुक्रवार को संसद के किसी एक सदन को सौंपा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी नेताओं ने कुमार पर सात आरोप लगाए गए हैं। नियम के मुताबिक, सीईसी को पद से हटाने के लिए लोकसभा के कम से कम १०० सांसदों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। वहीं, राज्यसभा के ५० सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं।

सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा के १३० और राज्यसभा के ६३ सांसदों ने एक नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की गई है। इस नोटिस को शुक्रवार को किसी एक सदन में जमा किया जा सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि किस सदन में सौंपा जाएगा। इस बीच, विपक्ष के एक नेता ने कहा कि सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर करने में काफी उत्साह दिखाया है। आवश्यक संख्या पहले ही पूरी हो जाने के बावजूद गुरुवार को कई सांसद इस नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे आए। सूत्र ने बताया कि नोटिस पर इंडिया ब्लॉक के राजनीतिक दलों के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। एक अन्य सूत्र ने कहा, आम आदमी पार्टी (आप) के सांसदों ने भी इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि आप अब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है।

सीईसी के खिलाफ लगाए गए ये आरोप

यह पहली बार है, जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। एक उच्च पदस्थ सूत्र के मुताबिक, ▶▶ 8

बुजुर्ग बना हैवान, हथौड़े से पीट-पीटकर अपनी पत्नी, बहू और पोती को मार डाला

देवगढ़ (ईएमएस): ओडिशा के देवगढ़ में एक बुजुर्ग ने हथौड़े से पीट-पीटकर अपनी ही पत्नी, बहू और पोती को मार डाला। सभी की हत्या करने के बाद बुजुर्ग भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। हत्या की वजह पारिवारिक झगड़ा बताया जा रहा है। आरोपी के बेटे ने इस मामले में पुलिस में केस दर्ज कराया है। यह घटना देवगढ़ के गरियापोली गांव का है। जानकारी के मुताबिक, रात करीब ११:३० बजे आरोपी का अपनी पत्नी से किसी बात पर बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने अपनी पत्नी पर हथौड़े से हमला कर दिया। खुद को बचाने के लिए पत्नी मदद के लिए अपनी बहू के पास गई। ▶▶ 8

मूसेवाला की हत्या के आरोपियों को जमानत

नई दिल्ली (ईएमएस): सुप्रीम कोर्ट ने २०२२ में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े मामले में दो आरोपियों पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को जमानत दे दी है। अदालत के आदेश के अनुसार दोनों आरोपी मुकदमे की सुनवाई जारी रहने के दौरान हिरासत से रिहा हो सकेंगे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। पवन बिश्नोई पर आरोप है कि वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जुड़ा था और उसने हत्या की साजिश में इस्तेमाल किए गए वाहन की व्यवस्था कर अपराध को अंजाम देने में लॉजिस्टिक मदद दी थी।

लोकसभा में एलपीजी गैस मामले को लेकर जोरदार हंगामा, राहुल गांधी और पेट्रोलियम मंत्री आमने-सामने

स्पीकर ने विषय से भटकने पर रोका; हरदीप पुरी बोले- देश में गैस की कमी नहीं

नई दिल्ली.(ईएमएस): लोकसभा में गुरुवार को एलपीजी संकट को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश में गैस सिलेंडर की कथित कमी और ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने राहुल गांधी को नोटिस में दिए गए विषय तक सीमित रहने को कहा।

सदन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, कि देश में एलपीजी संकट की स्थिति बनती दिख रही है। उन्होंने कहा, अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है। कई रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, सड़क किनारे के विक्रेता प्रभावित हो रहे हैं और एलपीजी को लेकर लोगों में घबराहट है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी देश की मजबूत नींव उसकी ऊर्जा सुरक्षा होती है और इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यदि अमेरिका यह तय ▶▶ 8

ग्रामीण इलाकों में अब 45 दिन के बाद ही एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग हो सकेगी

नई दिल्ली (ईएमएस): केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को संसद में बताया कि ग्रामीण इलाकों में अब ४५ दिन के बाद ही एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग हो सकेगी। इसके अलावा वन टाइम कोड के बिना सिलेंडर की डिलीवरी और कमर्शल एलपीजी के नियम भी बदले गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रसोई गैस की डिमांड को संतुलित रखने के लिए शहरी इलाकों में गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच कम से कम २५ दिन का अंतर रखना होगा, जबकि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के लिए ४५ दिन का अंतराल निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल स्तर पर गैस सिलेंडर जमा करने और घबराहट में ज्यादा बुकिंग करने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। हालांकि यह स्थिति सप्लाई की कमी के कारण नहीं बल्कि लोगों की चिंता के कारण पैदा हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक का औसत समय अभी भी ढाई दिन है।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बताया आगे कहा कि सरकार डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) प्रणाली का विस्तार कर रही है। अभी यह करीब ५० प्रतिशत उपभोक्ताओं के लिए लागू है, जिसे बढ़ाकर ९० प्रतिशत तक किया जा रहा है। इस सिस्टम में सिलेंडर की डिलीवरी तभी दर्ज होगी, जब ▶▶ 8

राहुल गांधी को राहत, कोर्ट ने बंद किया मानहानि केस

मुंबई (ईएमएस): कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर पर २०२२ में की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि मामले को नासिक की एक आपराधिक अदालत ने बंद कर दिया है। यह टिप्पणी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई थी। मामला देवेंद्र भूटाडा, नासिक स्थित निर्भया फाउंडेशन के अध्यक्ष, ने दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि गांधी ने १५ और १६ जून २०२२ को हिंगोली और अकोले में रैलियों में की गई टिप्पणियां मानानि और अपमानजनक थे।

फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग सुरक्षाकर्मियों ने बचाया

हमलावर बोला- उन्हें 20 साल से मारना चाहता था

जम्मू (ईएमएस): नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार रात एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी। अधिकारियों के मुताबिक फारूक जम्मू में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी थे।

घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि ७० साल के हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से आकर फारूक के सिर पर रिवॉल्वर तान दी। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हमलावर का हाथ हटाया जिससे फायर हवा में हो गया। आरोपी को पकड़ लिया गया है और हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हमलावर कमल ने पुलिस को बताया- 'मैं पिछले २० सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। यही मेरा मकसद था।'

हमलावर के पास कई साल से लाइसेंसी हथियार

पुलिस के मुताबिक, हमलावर पिछले कई सालों से लाइसेंसी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला, सुरिंदर चौधरी और दूसरे बड़े नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता सुरजीत सिंह के बेटे की शादी में शामिल हुए थे। हमलावर सुरजीत सिंह का कजिन है। वह बिजनेसमैन है और उसकी पुराने शहर में कुछ दुकानें हैं।

ओबीसी क्रीमी लेयर के निर्धारण मामले में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ की अहम टिप्पणी

केवल माता-पिता की सैलरी ओबीसी क्रीमी लेयर का आधार नहीं

नई दिल्ली (ईएमएस): सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के क्रीमी लेयर से जुड़े मुकदमे में अहम टिप्पणी की। दो जजों की खंडपीठ ने आज अपने फैसले में कहा कि आरक्षण के इस मामले में अभ्यर्थी के क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल माता-पिता या अभिभावकों की सैलरी के आधार पर नहीं किया जा सका। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में सरकार की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि क्रीमी लेयर दर्जा का निर्धारण करते समय माता-पिता या अभिभावकों के पदों और स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बेंच ने केंद्र सरकार की उन अपीलों को खारिज कर दिया, जो हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ थीं। कोर्ट ने उन यूपीएससी उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद नौकरी नहीं दी गई थी। सरकार ने उनके माता-पिता की सैलरी को आधार मानकर उन्हें गलत तरीके से क्रीमी लेयर की श्रेणी में डाल दिया था। अदालत ने साफ किया कि अधिकारियों ने उम्मीदवारों को आरक्षण से बाहर करने के लिए गलत पैमाना अपनाया। जस्टिस महादेवन ने फैसले में लिखा कि कोई उम्मीदवार क्रीमी लेयर में आता है या नहीं, इसका फैसला केवल आय के आधार पर नहीं हो सकता।

यूपीएससी उम्मीदवारों को बड़ी राहत

यह पूरा विवाद उन उम्मीदवारों से जुड़ा था जिनके माता-पिता सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू), बैंकों या इसी तरह के संस्थानों में काम करते थे। सरकार ने २००४ के एक स्पष्टीकरण पत्र का सहारा लेकर उनकी सैलरी को आय में जोड़ दिया था। इस वजह से वे आरक्षण के लाभ से वंचित हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने १९९३ के सरकारी आदेश का हवाला दिया। यह आदेश इंदिरा साहनी मामले के बाद बना था। इसमें स्पष्ट है कि क्रीमी लेयर तय करने के लिए माता-पिता का पद (जैसे ग्रुप ए या ग्रुप बी अधिकारी) मुख्य आधार है। इस नियम के तहत सैलरी और खेती से होने वाली कमाई को आय/संपत्ति टेस्ट में शामिल नहीं किया जाता। कोर्ट ने कहा कि २००४ का एक पत्र मुख्य नीति को नहीं बदल सकता। अदालत ने यह भी पाया कि सरकारी कर्मचारियों और पीएसयू कर्मचारियों के बीच भेदभाव करना गलत है। अगर सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पद के आधार पर छूट मिलती है, तो पीएसयू कर्मचारियों के बच्चों को केवल सैलरी के आधार पर आरक्षण से बाहर करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह ६ महीने के भीतर इन उम्मीदवारों के दावों पर फिर से विचार करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जरूरी हो तो इन उम्मीदवारों को नौकरी देने के लिए अलग से पद बनाए जाएं।

बुंदेला बस से 14 सौ किलो नकली पनीर व 90 किलो नकली घी बरामद

धनबाद (कासं) : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए जिला प्रशासन बेहद सजग एवं सख्त है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने अहले सुबह बस स्टैंड पर मिलावट खोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। जिसमें उन्होंने बिहार से आने वाली बुंदेला बस से १४ सौ किलो नकली पनीर तथा ९० किलो नकली घी बरामद किया। इसकी जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अहले सुबह बिहार से आने वाली बुंदेला नाम की बस, बी.आर. २१ पी ३६३२ से १४ सौ किलो नकली पनीर एवं ९० किलो नकली घी (६ टीन) और अन्य खाद्य सामग्रियां जब्त की। साथ ही बुंदेला बस के ड्राइवर एवं खलासी और बस को धनबाद थाना को सौप दिया। इसके अलावा बिहार से आने वाली सभी बसों में सघन जांच अभियान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि सभी पनीर पटना से धनबाद जिले में लगन के समय एवं त्योहारों के अवसर पर खपाने हेतु लाया जा रहा था। इतनी बड़ी मात्रा में धनबाद में पहली बार मिलावटी पनीर का पकड़ा गया है। मिलावट खोरों के विरुद्ध ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा।

डॉग स्कायड व मेटल डिटेक्टर लेकर कोर्ट पहुंची पुलिस, कोनेकोने की ली तलाशी

धनबाद (कासं) : धनबाद सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। एहतियात के तौर पर एक बार फिर धनबाद सिविल कोर्ट परिसर में डॉग स्कॉड टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया।

जांच के दौरान डॉग स्कॉड टीम ने कोर्ट परिसर के हर कोने की बारीकी से तलाशी ली। साथ ही परिसर में खड़ी सभी वाहनों की भी जांच की गई, ताकि किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री की मौजूदगी की संभावना को पूरी तरह खारिज किया जा सके। इस दौरान मौके पर डीएसपी डी.एन. बंका, धनबाद थाना प्रभारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है और कोर्ट परिसर में आनेजाने वाले लोगों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले धनबाद सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिसके बाद से पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसी के मद्देनजर समयसमय पर डॉग स्कॉड और सुरक्षा बलों की मदद से जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके।

डीएसपी डी.एन. बंका ने बताया कि वरीय अधिकारी के निर्देश पर यह जांच अभियान चलाया जा रहा है। यह जांच दो खोजी कुत्ते और मेटल डिटेक्टर के सहारे चल रही है। आगे भी सुरक्षा के मद्देनजर जांच और निगरानी जारी रहेगी।

ग्रामीण उत्पाद प्रदर्शनी में हिस्सा लेने धनबाद से महिलाएं रांची रवाना

धनबाद (कासं) : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर १३ से १५ तक रांची के खेल गांव में ग्रामीण उत्पाद प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए गोविंदपुर खरनी के कृषक उत्पादक संगठन गोविन्दपुर किसान साथी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एफपीओ) से २५ महिलाएं रांची रवाना हुई। प्रदर्शनी में महिलाएं अन्नपूर्णीका - कोयलांचल की पौष्टिक मिठास, ब्रांड के तहत गाय के शुद्ध घी से बने रागी लकू का स्टॉल लगाएंगी।

रांची रवाना होने से पहले उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने समाहरणालय के सभागार में सभी को शुभकामनाएं दी। उपायुक्त ने उत्पाद का ट्रेडमार्क करा लेने का सुझाव दिया। साथ में उत्पाद बिक्री के लिए धनबाद अंचल कार्यालय सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर स्थान उपलब्ध कराने को कहा। उत्पाद को और बेहतर बनाने के लिए उपायुक्त ने ग्रेष्ठ क्वालिटी के मशीन व अन्य सामान देने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया। उपायुक्त ने कहा जिला प्रशासन की यह पहल ग्रामीण महिलाओं को न सिर्फ रोजगार दे रही है, बल्कि उनकी आय भी बढ़ा रही है और उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही है। ये पौष्टिक रागी लड्डू आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुँचकर समाज के बेहतर पोषण में भी योगदान देंगे। यह सैकड़ों किसानों और महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रहा है।

वहीं डीएमएफटी पीएमयू के परियोजना प्रबंधक आजीविका और कौशल विकास अमर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रागी लड्डू, रागी का आटा, शुद्ध घी, गुड़ और सूखे मेवे मिलाकर बड़े प्यार और मेहनत से बनाए जाते हैं। लड्डुओं में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, परंपरा और गाँव की मेहनत की मिठास भी घुल जाती है। ग्रामीण उत्पाद प्रदर्शनी में हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला खरसावां, गोड्डा, रामगढ़, गुमला, खूंटी, देवघर, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम सहित अन्य जिलों के स्टॉल लगेंगे।

मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन, जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक मिश्रा, डीएमएफटी पीएमयू के अमर कुमार श्रीवास्तव, एफपीओ के सीईओ अब्दुल कयूम अंसारी, निदेशक अनुपम मोदी, अंजना देवी, अंजलि देवी के अलावा अन्य सदस्य मौजूद थे।

असर्फी अस्पताल प्रबंधन ने बकाया रुपयों के लिए शव को बनाया बंधक, मेयर संजीव ने चुकाया बिल

धनबाद (कासं) : धनबाद के प्रतिष्ठित असर्फी अस्पताल से एक ऐसी खबर सामने आया है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की मौत के बाद, अस्पताल प्रबंधन ने महज २० हजार के लिए शव को बंधक बना लिया। इस संवेदनशील मामले में नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह ने खुद अस्पताल पहुंचकर न सिर्फ बिल चुकाया, बल्कि अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी कड़े सवाल खड़े किए हैं।

झरिया निवासी ५४ वर्षीय संजीत सिंह के सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज के लिए असर्फी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। दुख की इस घड़ी में परिजनों पर तब और पहाड़ टूट पड़ा जब अस्पताल प्रबंधन ने बकाया २०,८६४ रुपये न चुकाने की सूरत में शव सौंपने

से इनकार कर दिया।

जैसे ही इसकी सूचना धनबाद के नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह को मिली, वे तुरंत हरकत में आए। अपने पैर में चोट होने के बावजूद, मेयर लंगड़ाते हुए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अपने निजी कोष से बकाया राशि का भुगतान किया, जिसके बाद अस्पताल ने मृतक का शव परिजनों को सौंपा। इस दौरान अस्पताल परिसर में घंटों अफरातफरी और तनाव का माहौल बना रहा। मेयर के साथ पहुंचे जनता मजदूर संघ' के संगठन सचिव अमित गुप्ता ने इस दौरान अस्पताल प्रबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि असर्फी अस्पताल का यह पुराना ढर्रा रहा है कि वे मृत शरीर को सिर्फ पैसों की उगाही के लिए रोकते है।

उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन का रवैया बेहद चिंताजनक है। किसी भी अस्पताल को मृत शरीर को बंधक बनाने का कानूनी अधिकार नहीं है। ये लोग न विधायक की सुनते हैं न मेयर की। अक्सर देखा गया है कि वेंटिलेटर के नाम पर ये सिर्फ रुपयों की उगाही करते हैं। लेकिन इस बार इन्हें समझ आ जाएगा कि इन्होंने किसके साथ गलत किया है। सिंह मेंशन हर दुखियारी परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है।

19 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक गिरफ्तार

धनबाद (कासं) : आरपीएफ धनबाद ने ऑपरेशन सतर्क के तहत १९ बोतल अंग्रेजी शराब के साथ १ तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शिव कुमार प्रसाद (५५), पिता स्व. अम्बिका प्रसाद, फतुहा खुशरूपुर, जिला पटना, बिहार निवासी है आगे पूछताछ मे शिव कुमार ने बताया कि अंग्रेजी शराब जिसे वह आसनसोल से खरीद कर धनबाद आया था और धनबाद से गंगा दामोदर एक्सप्रेस से पटना जाकर अधिक दामों पर बेचता किन्तु पहले ही पकडा गया आरपीएफ ने मौके पर समस्त विधिक कारवाई करते हुए पकड़े गए व्यक्ति के पास से बरामद प्रतिबंधित अंग्रेजी शराब को जब्ती सूची बनाकर उत्पाद विभाग के हवाले कर दिया।

युवकों के दो गुटों के बीच जमकर चली लाठियां, कई घायल

धनबाद (कासं) : युवकों के दो गुटों के बीच सरेराह खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के बेकारबांध इलाके में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब दर्जनों युवकों ने लाठीडंडों से एकदूसरे पर हमला बोल दिया। इस हिंसक झड़प में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आननफानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पूरा मामला आपसी रंजिश और कल हुई एक मारपीट का बदला लेने से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, बेकारबांध निवासी धर्मेंद्र कुमार बीते कल जियोमार्ट में काम के सिलसिले में गया था। वहां मौजूद वेंडरों ने उसका विरोध किया और बात बढ़ने पर करण नाम के एक वेंडर ने धर्मेंद्र की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। कल की इसी टीस को लेकर जब धर्मेंद्र ने बेकारबांध के समीप करण को रोककर पुरानी मारपीट के बारे में पूछताछ की, तो दोनों के बीच तीखी कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि करण ने फोन कर अपने २० से २५ साथियों को मौके पर बुला लिया।

जियोमार्ट में काम करने वाले ये युवक लाठीडंडों से लैस होकर पहुंचे और धर्मेंद्र पर टूट पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सरेआम सड़क पर लाठियां बरसती रहीं और लोग दहशत में इधरउधर भागने लगे। इस हमले में धर्मेंद्र कुमार का भाई गौतम कुमार और करण गुट का एक अन्य युवक बुरी तरह घायल हो गया है। दोनों के सिर पर

गहरी चोटें आई हैं और खून से लथपथ हालत में उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है।

घटना की सूचना मिलते ही धनबाद सदर थाना की एएसआई सीमा किंडो दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने उग्र युवकों को खदेड़ा और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस के अनुसार, यह विवाद पिछले दिन हुई एक मारपीट की घटना का परिणाम है। घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। धनबाद थाना की पुलिस वर्तमान में मामले की गहनता से जांच कर रही है और घटना स्थल के आसपास के साक्ष्यों को एकत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि आवेदन दिया जाएगा तो पुलिस उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी।

जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग को ले नारेबाजी

बलियापुर (ससे) : प्रधानखंता पहाड़घार बेदिया टोला में झारखंड बांम्ला भाषा उन्नयन समिति की बैठक जितेंद्र बेदिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बेदिया जाति के लोगों को प्रखंड कार्यालय द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा किया गया।

बांम्ला भाषा उन्नयन समिति के संस्थापक बेंगू ठाकुर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बेदिया जाति के छात्रछात्राओं का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने से इस जाति के बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए काफी दिक्कतें हो रही है। लोग सरकारी लाभ पाने से वंचित हो रहे है। उन्होंने कहा कि पूर्व में बेदिया

जाति के लोगों द्वारा इस मुद्दे पर कई बार धरना, प्रदर्शन आयोजित किया गया। जिसमें बलियापुर बीडीओ एवं सीओ द्वारा बेदिया जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक इस जाति के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा। जिससे आक्रोशित लोगों ने बैठक में सरकार एवं प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारे लगाए। लोगों ने बेदिया जाति के लोगों को जल्द जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग सरकार एवं प्रशासन से की गई। बैठक में सागर बेदिया, सुनीता कुमारी, मनीषा कुमारी, परमिता कुमारी, चंद्रशेखर बेदिया, श्रीकांत बेदिया, राजेश बेदिया, तपन बेदिया समेत काफी संख्या में लोग थे।

विधायक चंद्रदेव ने की फिसफील्ड मिल स्थापित करने की मांग

बलियापुर (ससे) : सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य में मत्स्य उत्पादन, रोजगार सृजन एवं आय वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए फीसफील्ड मिल की स्थापना की मांग की है। विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि राज्य में पर्याप्त संख्या में

फिशफीड मिल की स्थापना नहीं की गई है। जिसके कारण राज्य के हजारों मत्स्य पालक महंगी निजी कंपनियों पर निर्भर होने को मजबूर है। विधायक ने यह भी कहा कि धनबाद, हजरीबाग, गिरिडीह, बोकारो, संथाल परगना एवं कोल्हान क्षेत्र में तालाब जलाशय एवं प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद फिश फीड मिल की कोई ठोस योजना धरातल पर नहीं है। उन्होंने राज्य के मत्स्य पालक एवं किसानों के रोजगार सृजन एवं आयवृद्धि हेतु फिशफीड मिल की स्थापना की मांग की है। दूसरी ओर विधायक ने सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत अधिकांश पंचायत अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति बाहुल्य होने के बावजूद छात्रछात्राओं को छात्रावास जैसी मूलभूत शैक्षणिक सुविधा से वंचित रखा गया है। उन्होंने गोविंदपुर क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रछात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।

लोदना क्षेत्र में राजभाषा कार्यशाला का आयोजन

जोड़ापोखर (ससे) : भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लोदना क्षेत्र के अंतर्गत नवचयनित लिपिकों एवं महिला कर्मियों के लिए राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारम्भ महाप्रबंधक, लोदना क्षेत्र के द्वारा किया गया। महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा का स्वागत क्षेत्रीय प्रबंधक (मानव संसाधन), दीपक कुमार सिंह ने पुस्तक और पुष्प गुच्छ देकर किए साथ ही मुख्यालय से आये बीसीसीएल के हिंदी अनुवादक अनिरुद्ध कुमार नोनिया एवं बंदना का स्वागत राजभाषा नोडल अधिकारी, सौरभ सिंह के द्वारा पुष्प गुच्छ एवं पुस्तक देकर किया गया। तदोपरांत महाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक (मानव संसाधन), नोडल अधिकारी (राजभाषा) एवं मुख्यालय के हिंदी अनुवादक ने दीप प्रज्वलित कर एवं कवियत्री महादेवी वर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित किए इसके बाद राष्ट्र गान एवं कोल इंडिया गीत बजाया गया इसके सम्मान मे उपस्थित सभी प्रतिभागी खड़े हुए। कार्यशाला का संचालन रौशन कुमार शर्मा, अनुवादक (राजभाषा) एवं सह संचालन राकेश कुमार, लिपिक (राजभाषा) ने किया। महाप्रबंधक, अनिल कुमार सिन्हा ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों से अधिक से अधिक हिंदी में कार्य करने की सलाह डी गई।

मुख्यालय के हिंदी अनुवादक अनिरुध कुमार नोनिया एवं श्रीमती बन्दना ने राजभाषा नीति नियम के बारे मे विस्तार से बताये साथ ही साथ शब्दावली अंग्रेजी से हिंदी, मानक हिंदी एवं अन्य कार्यालीन कार्य हिंदी में करने के बारे में बताएं, तत्पश्चात, बीसीसीएल मुख्यालय की राजभाषा टीम द्वारा गुरूवार को राजभाषा हिंदी के संबेधानिक उपबंधों के अनुरूप किए जा रहे कार्यों का जायजा लेने के लिए हिंदी दस्तावेजो की निरीक्षण किया गया। इस कार्यशाला का सफल आयोजन के लिए किशोर कुमार, देवेन्द्र कुमार साव, लालटू रजवार, हीरु सहिस, सुमित कुमार ने योगदान दिए। इस कार्यक्रम में कुल ३० अधिकारी/कर्मचारी प्रतिभागी उपस्थित हुए।

बरटांड़ बस स्टैंड को ले विधायक रागिनी ने विस में उठाया मुद्दा

धनबाद (कासं) : धनबाद के बरटांड़ स्थित बस स्टैंड को कतरास के लिलोरी स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रस्तावित योजना को लेकर झारखंड विधानसभा में प्रस्तावित योजना को खारिज कर दिया गया। बजट सत्र के दौरान झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने इस मुद्दे पर सूचना के माध्यम से सदन में सरकार पर वोट डाला।

विधायक रागिनी ने कहा कि वर्तमान में बरटांड़ बस स्टैंड पर कतरास के लिलोरी स्थान ले जाने की योजना बनाई जा रही है, जो कि धनबाद रेलवे स्टेशन से लगभग १५ किमी दूर है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आम यात्रियों की सुविधा के विपरीत है और इससे विशेष रूप से श्रमिकों, छात्रों, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों और छोटे

व्यवसायियों को भारी संकट उठाना पड़ेगा।

उन्होंने सदन में कहा कि बरटांड बस स्टैंड परिसर में ही लगभग २१ एकड़ जमीन उपलब्ध है, जिसे नगर निगम द्वारा सफाई कार्य के लिए एक निजी एजेंसी दी गई है। जब शहर के अंदर इतनी बड़ी जमीन मौजूद है तो फिर बस स्टैंड को शहर से दूर ले जाने की योजना क्यों बनाई जा रही है। विधायक रागिनी सिंह ने सरकार से तीखे शब्दों में सवाल करते हुए कहा कि क्या सरकार यात्रियों की सुविधा के बजाय उन्हें और अधिक परेशानी में डालने का निर्णय ले रही है ? उन्होंने कहा कि धनबाद जैसे व्यस्त और औद्योगिक शहर में बस स्टैंड को शहर से १५ किलोमीटर दूर ले जाना न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि इससे यात्रियों को रेलवे स्टेशन और शहर तक आनेजाने में अतिरिक्त समय और पैसा भी खर्च करना पड़ेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि बस स्टैंड के स्थानांतरण से स्थानीय व्यापार और शहर की यातायात व्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। धनबाद कोयलांचल क्षेत्र का प्रमुख व्यावसायिक और परिवहन केंद्र है। यहां से रोजाना हजारों यात्री विभिन्न जिलों और राज्यों के लिए बस से यात्रा करते हैं। ऐसे में बस स्टैंड को शहर से दूर ले जाने का निर्णय यात्रियों के लिए नई परेशानियां खड़ी कर सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बस स्टैंड शहर के बाहर बनाया जाता है, तो यात्रियों को पहले शहर तक पहुंचने और फिर बस स्टैंड तक जाने के लिए अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ेंगे। विधायक रागिनी ने सरकार से मांग की कि यात्रियों की सुविधा और शहर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बस स्टैंड को कतरास के लिलोरी स्थान पर स्थानांतरित करने के बजाय धनबाद शहर में ही उपलब्ध जमीन पर आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाए।

हवाई फायरिंग मामले में पुलिस ने एक को भेजा जेल

कैंदुआ (ससे) : गोंदूडीह ओपी क्षेत्र के खरिकाबाद में सड़क हादसे के बाद हवाई फायरिंग की घटना के बाद तनाव बढ़ने के बाद गोंडूडीह ओपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देर रात तक अन्य थाना के सहयोग से छापेमारी किया। इस दौरान पुलिस ने दो लोगो को पूछताछ के लिए पकड़ा।

पुलिस ने एक को पूछताछ के बाद छोड़ दिया जबकि दूसरे व्यक्ति पवन दास को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कांड संख्या २१/२६ दर्ज कर बसेरिया निवासी संजीत कुमार, राजू यादव, शिवकुमार यादव, विजय यादव, योगेन्द्र यादव, नुनु यादव, अमित यादव, पंकज यादव, आकाश यादव, मोनू रवानी, राहुल रवानी, पवन दास आदि को नामजद आरोपी बनाया है। एएसआई विलियम पन्ना के फद बयान पर मामला दर्ज किया गया है। नामजद आरोपियों ने अपने को निर्दोष बताते हुए घटना की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जाँच की मांग किया है।

डी.बी. पब्लिकेशन्स प्रा. लि. के लिए जोड़ाफाटक रोड, धनबाद से राजेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा मुद्रित एवं अंजना अग्रवाल द्वारा प्रकाशित. संपादक -नागेश मिश्रा. फोन -9431726337
e-mail : biharobserver@gmail.com RNI No- 58991/95. * पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए नागेश मिश्रा जिम्मेवार होंगे एवं समस्त विवाद धनबाद न्यायालय के अधीन होंगे

कई थानेदारों का तबादला, प्रवीण कुमार बने कतरास थाना प्रभारी

धनबाद (कासं) : धनबाद के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। दर्जन भर अधिकारियों को बदल दिया गया है। पिछले कई दिनों से इसके कयास लगाए जा रहे थे। पुलिस अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा हो रही थी। सूत्रों के अनुसार एक दर्जन पुलिस इंस्पेक्टरो को बदलकर उन्हें नई जगह दी गई है। सभी को तत्काल प्रभाव से योगदान का निर्देश भी जारी कर दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार प्रवीण कुमार को बैंक मोड़ थाना प्रभारी से कतरास थाना प्रभारी, असीत कुमार सिंह को कतरास थाना प्रभारी से बैंक मोड़ थाना प्रभारी, अजीत भारती को तोपचांची थाना प्रभारी से निरसा थाना प्रभारी, अनिल शर्मा को निरसा थाना प्रभारी से जोड़ापोखर सर्किल इंस्पेक्टर, आशुतोष कुमार को जोड़ापोखर सर्किल इंस्पेक्टर से चिरकुंडा थाना प्रभारी, रामजी राय को चिरकुंडा थाना प्रभारी से साइबर पुलिस स्टेशन, लव कुमार को ट्रैफिक थाना प्रभारी से तोपचांची थाना प्रभारी, संजय कुमार को सिंदरी थाना प्रभारी से कोर्ट सिक्योरिटी, राजेश कुमार को अभियोजन कोषांग से सिंदरी थाना प्रभारी, मो. रूस्तम को कोर्ट सिक्योरिटी से कतरास पुलिस अंचल, मुकेश कुमार को कतरास पुलिस अंचल से अभियोजन कोषांग, जय प्रकाश को साइबर थाना से ट्रैफिक थाना प्रभारी बनाया गया है।

गैरेज में खड़ी कार में लगी आग, जलकर राख

पुटकी (ससे) : पुटकी थाना क्षेत्र के पुटकी बीटाइप कॉलोनी में गुरुवार शाम करीब सात बजे गैरेज में खड़ी बीसीसीएल कर्मी मुनेश्वर प्रसाद की होंडई आई-२० कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पुटकी पुलिस व धनबाद की दमकल टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कार मालिक मुनेश्वर प्रसाद ने बताया कि अचानक गाड़ी में आग लग गई। जब तक कुछ समझ पाते और आग बुझाने की कोशिश करते, तब तक कार पूरी तरह जल गई है।

सनातन केवल धर्म नहीं, जीवन जीने की शाश्वत पद्धति है : सुरेंद्र हरिदास जी

गोविंदपुर (ससे) : गोविंदपुर के कुम्हारडीह रोड में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के भागवत मर्मज्ञ सुरेंद्र हरिदास जी महाराज ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की अलौकिक महिमा का बखान किया। भक्तों ने प्रभु की भक्ति में रंगों का प्रयोग करते हुए प्रेम और आनंद का अद्भुत संगम अनुभव किया।

सुरेंद्र हरिदास ने कहा कि आज का समय मोह, माया, लालच और दिखावे में हमें उलझा देता है। हम बाहर की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि भीतर बसे भगवान को भूलने लगते हैं। सच तो यह है कि यदि हम माया से थोड़ा दूर रहकर मन को शांत कर भगवान की भक्ति में ध्यान लगाएं तो यह कलयुग भी हमारे लिए साधना का श्रेष्ठ अवसर बन सकता है। श्री हरिदास ने कहा कि सनातन केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक शाश्वत पद्धति है, जो हमें सत्य, करुणा, सेवा और धैर्य का मार्ग दिखाती है। सनातन को जानना मतलब उसके मूल सिद्धांतों, शास्त्रों और परंपराओं को समझना। सनातन को पहचानना, मतलब उसके मूल्यों को अपने आचरण में उतारना। और सनातन का सम्मान करना, मतलब हर जीव में ईश्वर को देखना। कथा को सफल बनाने में विमल चन्द्र दे, पद्दा दे, संजय अग्रवाल, अनिता अग्रवाल, प्रदीप बंसल, कांता बंसल, पिंकू सिंह, रिंकी सिंह, जगन्नाथ दे, पुष्पा देवी, अशोक कुमार दे, ललिता देवी, अरूण चन्द्र दे, पुतुल देवी आदि सक्रिय हैं। शुक्रवार को गोवर्धन पूजा एवं छप्पन भोग का आयोजन होगा।

पाइप फटने से बह रहा है पानी

गोविंदपुर (ससे) : एक ओर गोविंदपुर की जनता पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रही है, दूसरी और मैथन जलापूर्ति योजना का पानी जगहजगह व्यर्थ बह रहा है। मैथन से भेलाटांड़ जा रही पानी का पाइप रतनपुर में जीटी रोड किनारे अनूप ऑटोमोबाइल्स के पास फट गया है और वहां पिछले एक माह से लगातार पानी बह रहा है। इसी तरह और कई स्थानों पर मैथन जलापूर्ति योजना का पानी बेकार बह रहा है। बागसुमा तथा अमलाटांड़ इलाके में भी जलापूर्ति योजना का पानी व्यर्थ बह रहा है । पूर्व मुखिया मिहिर मंडल ने बताया कि रतनपुर में पानी के व्यर्थ बहने की सूचना पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कनीय अभियंता को दी जा चुकी है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गोविंदपुर के जल उपभोक्ताओं ने बताया कि यहां प्रतिदिन २५० एमएलडी पानी की आवश्यकता है परंतु मात्र १२५ एमएलडी जलापूर्ति की जा रही है। इसी के कारण बारी-बारी से क्षेत्र में जलापूर्ति की जा रही है । प्रत्येक इलाके में प्रत्येक २ दिन पर पानी की आपूर्ति की जाती है। यही कारण है कि गोविंदपुर में सालों भर पानी के लिए हायतौबा मची रहती है। उपभोक्ताओं ने कहा कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी में भीषण जल संकट उत्पन्न हो जाता है। उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि मैथन जलापूर्ति योजना के व्यर्थ बह रहे पानी का बचाव कर लिया जाए तो जल संकट का बहुत हद तक निष्पादन हो जाएगा।

यूपी के पूर्व सांसद व भाजपा प्रवक्ता ने मेयर संजीव को दी बधाई

धनबाद (कासं) : महापौर संजीव सिंह से पूर्व सांसद अतुल राय व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुधीर सिंह ने शिष्टाचार की। अतुल राय एवं सुधीर सिंह ने धनबाद के नवनिर्वाचित महापौर संजीव सिंह से उनके धनबाद स्थित आवास सिंह मेंशन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने महापौर संजीव सिंह को उनके चुनावी विजय पर बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। मुलाकात के दौरान पारिवारिक, सामाजिक एवं समसामयिक राजनीतिक विषयों पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई।

नेताओं ने धनबाद शहर के विकास, स्वच्छता व्यवस्था तथा जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी विचारविमर्श किया। साथ ही महापौर संजीव सिंह के नेतृत्व में धनबाद नगर निगम द्वारा शहर के विकास और जनसेवा के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

जनता श्रमिक संघ का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

पुटकी (ससे) : गोपालीचक कोलियरी अंतर्गत संचालित एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ ११ सूत्री मांगों को लेकर जनता श्रमिक संघ पीबी क्षेत्र के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरनाप्रदर्शन किया गया। धरना के कारण कोयला उत्खनन व परिवहन का कार्य पूरी तरह ठप हो गया। आंदोलन की अध्यक्षता धर्मेंद्र पासवान ने किया। संघ के पीबी क्षेत्र के उपाध्यक्ष मुकेश पासवान ने बताया कि ११ सूत्री मांगों को लेकर प्रबंधन को कई बार आवेदन देकर वार्ता का आग्रह किया गया था, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई। इसके विरोध में बाध्य होकर मजदूरों को हड़ताल करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती है।

अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। संघ की मांगों में आउटसोर्सिंग कंपनी में फेंसिंग की व्यवस्था, खदान में बाउंड्री, बेंच, हॉल रोड व एप्रोच रोड को माइनिंग नियमों के अनुरूप दुरुस्त करना, ओबी डंप को मानक के अनुसार बनाना, ब्लास्टिंग के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन, बिजली पोल की ऊंचाई मानक के अनुसार करना, घनी आबादी के बीच कोयला डंपिंग बंद करना तथा धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव आदि शामिल है। इसके अलावा बिना नोटिस के बैठाए गए आठ श्रमिकों को काम पर रखने, कोयला चोरी पर रोक लगाने, कटे पेड़ों के बदले पौधारोपण करने और बीसीसीएल आवास व ग्रामीणों के लिए पीट वाटर की आपूर्ति बहाल करने की मांग की गई है। धरना में रुपेश पासवान, विशाल वर्णवाल, मनोज राम, नीतू रजवार, अजय रवानी, पंकज सिंह, गीता देवी, मनिया देवी, लक्ष्मिया देवी सहित दर्जनों मजदूर शामिल थे।

कोयला भवन में निदेशक ने की समीक्षा बैठक

धनबाद (कासं) : भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मानव संसाधन निदेशालय द्वारा आज कोयला भवन मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता निदेशक (मानव संसाधन) ने की। बैठक में मुख्य रूप से मानव संसाधन निदेशालय के नियंत्राधिन सभी महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधक (मा.सं.) और हाल ही में संस्थान से जुड़े नवनियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

बैठक के दौरान संस्थान की कार्यक्षमता और कर्मचारी सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचारविमर्श किया गया।

दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से स्वीकृत राशि के लंबित मामलों की समीक्षा की गई और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए।

पिछले तीन वर्षों में क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता प्राप्त करने हेतु दी गई अनुमतियों के विवरण का अवलोकन किया गया।

संस्थान के डेटा प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु प्रणाली में 'की पोजीशन' के अपडेशन और नियमित आवास आवंटन के रिकॉर्ड को पारदर्शी तरीके से अपडेट करने पर बल दिया गया। दरों में संशोधन के अनुरूप आवास किराया वसूली और वर्तमान में जारी ऑडिट की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अवसर पर निदेशक (मा.सं.) ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें ताकि कर्मचारियों के कल्याण और कंपनी के डेटा प्रबंधन में पारदर्शिता बनी रहे। नवनियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए यह बैठक कंपनी की कार्यप्रणाली को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर रही।

पतलाबाड़ी रोड में ब्रेकर लगाने की मांग

बलियापुर (ससे) : पतलाबाड़ी रोड पर दुधिया के पास बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए पंचायत के मुखिया उत्तम चौबे ने उक्त सड़क पर चिन्हित स्थानों पर प्लास्टिक स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग उपायुक्त धनबाद से किया है। मुखिया श्री चौबे ने उपायुक्त को इस संबंध में आवेदन देकर उक्त सड़क पर स्थित दुधिया मोड़, सहिस टोला, डीजे मोड, रंजीत मोहली के घर के पास, भुखल सहीस चौक एवं राधा कृष्ण मंदिर के पास सड़क पर प्लास्टिक स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग किया है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके।

स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

मधुबा (ससे) : भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की तरफ से क्षेत्रीय अस्पताल पश्चिमी झरिया क्षेत्र मुनीडीह के द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन मुरलीडीह २०/२१ पिट्स कोलियरी में चिकित्साधिकारी डॉक्टर प्रणय प्रतीक घोष के नेतृत्व में लगाया गया। शिविर में एरिया मैनेजर एनवायरनमेंट विकास कुमार, संजय कुमार सिंह, देवाशीष उरांव, भोला कुमार धर्मेंद्र कुमार सुशांत और अरविंद सहयोग के रूप में उपस्थित थे।

इस अवसर पर महुदा ग्रुप प्रबंधक विभूति कुमार मिश्रा यूनियन प्रतिनिधि बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के क्षेत्रीय सचिव पी एन तिवारी, कोयला इस्पात मजदूर पंचायत संघ के सचिव बदरुद्दीन अंसारी, मुरलीडीह २०/२१ पिट्स अस्पताल के बोधी राम, निलम भुईन, रीना कुमारी, डालो देवी, पार्वती देवी, कृष्णा रजक, केदार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, दुखन महतो के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग ७३ लोगों का मुफ्त में स्वस्थ्य जांच कर दवा वितरण किया गया।

अनिल अम्बानी की 581.65 करोड़ रुपये की 31 अचल संपत्ति को अटैच

नई दिल्ली (ईएमएस) : प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ५८१.६५ करोड़ रुपये की ३१ अचल संपत्ति को अटैच किया है. यह कार्रवाई ११ मार्च को की गई. ईडी के अनुसार संपत्तियां देश के कई राज्यों में स्थित हैं, जिनमें गोवा, केरल, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में स्थित जमीनें शामिल हैं।

ईडी ने बताया कि इससे पहले भी आरएचएफएल, आरसीएफएल और रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के मामलों में १५,७२९ करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां शामिल की गई हैं. ताजा कार्रवाई के बाद रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी कुल संपत्ति का आंकड़ा करीब १६,३१० करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

नागा समुदाय के सभी 21 नागरिकों को बातचीत के बाद छोड़ दिया गया

इंफाल (ईएमएस) : मणिपुर के उखरुल जिले में कुकी समुदाय के ग्रामीणों और सशस्त्र लोगों द्वारा हिरासत में लिए गए नागा समुदाय के सभी २१ नागरिकों को बातचीत के बाद छोड़ दिया गया। इंफाल पुलिस अधिकारी ने बताया कि उखरुलइम्फाल मार्ग पर तीन वाहनों में यात्रा कर रहे तंगखुल नागा समुदाय के नागरिकों को शांगकाई में कुकी गांव वालों और हथियारबंद लोगों ने बंधक बनाया था। राज्य सरकार के अधिकारियों और नागा एवं कुकी समुदायों के नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के नेताओं के बीच गहन बातचीत और विचारविमर्श के बाद सुबह बंधकों को रिहा किया गया। रिहाई के बाद नागरिकों को लिटान पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बाद में उन्हें उनके परिवारों से मिला दिया गया।

२१ लोगों को बंधक बनाने के कारण तंगखुल नागा बहुल उखरुल जिले में विशेष रूप से कुकी बहुल कांगपोकपी जिले से सटे इलाकों में तनाव बना रहा। सुरक्षा बलों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तलाशी और क्षेत्र नियंत्रण अभियान चलाए। इसके पहले मणिपुर में तंगखुल नागाओं की सर्वोच्च संस्था, तंगखुल नागा लोंग (कार्यकारी समिति) ने उखरुल जिले के कुकीबहुल गांव शांगकाई में हिरासत में लिए गए २० से अधिक नागा नागरिकों की सुरक्षित रिहाई की मांग करते हुए दो घंटे का अल्टीमेटम जारी किया था। तंगखुल मणिपुर की सबसे बड़ी नागा जनजाति है और मुख्य रूप से राज्य के पांच से छह जिलों में पाई जाती है।

मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने उखरुलइम्फाल सड़क पर उत्पन्न भयावह स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सिंह ने जिम्मेदार लोगों से मानवता के सर्वोच्च मूल्यों का पालन करने और सभी नागरिकों की सुरक्षित और बिना शर्त रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की है।

एंटी क्राइम चेकिंग अभियान, 1327 वाहनों की सघन जांच

धनबाद (कासं) : वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देश पर जिले भर में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस की टीमों ने प्रमुख चौकचौराहों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष जांच अभियान चलाया।

इस दौरान कुल १३२७ वाहनों की सघन जांच की गई। पुलिस द्वारा वाहनों के कागजातों का सत्यापन किया गया तथा वाहन चालकों से आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। जिन वाहनों के कागजात सही नहीं पाए गए उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए गए और चालान भी काटा गया। इसके साथ ही चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई और उनकी पहचान का सत्यापन किया गया। एसएसपी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य अपराध पर नियंत्रण रखना, असामाजिक तत्वों पर नजर रखना और आम लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है।

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे जांच के दौरान पुलिस का सहयोग करें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के एंटी क्राइम चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

नेताजी की अस्थियों को लाने की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली (ईएमएस) : सुप्रीम कोर्ट ने जापान की राजधानी टोक्यो के रेनकोजी मंदिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को भारत लाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार किया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन नेताजी के वारिस खुद सुप्रीम कोर्ट में आकर याचिका दायर करें। सीजेआई ने कहा कि नेताजी देश के सबसे महान नेताओं में से एक थे, लेकिन कोर्ट इन याचिकाओं के पीछे के मकसद और उसके समय को अच्छी तरह समझता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वारिस के कोर्ट आने पर इस तरह का फैसला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वारिस को याचिका दायर करने दीजिए, हम उस पर सुनवाई करने को तैयार है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील ए.एम.सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नेताजी का केवल एक ही जीवित वारिस है, उनकी बेटी अनीता बोस फाफ। फिलहाल याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया गया है।

इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि केंद्र टोक्यो के रेनकोजी मंदिर से नेताजी की अस्थियां वापस लाने में नाकाम रही है, इसकारण उनकी बेटी अनीता बोस भारत में उनका सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं कर पा रही हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट मामले में हस्तक्षेप कर मोदी सरकार को निर्देश दे कि अस्थियों को भारत लाया जाए।

रेनकोजी मंदिर में रखी अस्थियां १८ सितंबर १९४५ से सुरक्षित हैं, जो नेताजी की मृत्यु के बाद वहां रखी गई थीं। नेताजी की मौत १८ अगस्त १९४५ को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में होने की आधिकारिक रिपोर्ट है, लेकिन इस पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मुखर्जी आयोग सहित कई जांचों में अलगअलग निष्कर्ष आए हैं और अस्थियों की डीएनए जांच की मांग भी समयसमय पर उठती रही है। नेताजी के परिवार के कुछ सदस्यों ने पहले भी अस्थियों को भारत लाने और उनका अंतिम संस्कार करने की अपील की है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा विपक्ष

नई दिल्ली (ईएमएस) : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। दोनों सदनों के विपक्षी सांसद इस मामले में एकजुट हैं। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के करीब १२० सांसद और राज्यसभा के ६० सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। बताया जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी अभियान की अगुवाई तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक सांसद कर रहे हैं।

दरअसल पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके पहले राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सीएम ममता बनर्जी चुनाव आयुक्त कुमार के खिलाफ मुखर भी है। विपक्ष एक के नेता ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि नोटिस की दो अलगअलग कॉपी शुक्रवार तक लोकसभा और राज्यसभा में जमा होगी। विपक्षी पार्टियां कुमार के खिलाफ सात खास आरोप लिस्ट तैयार करेंगी, जिसमें भेदभावपूर्ण व्यवहार, इलेक्शन फ्रॉड की जांच में जानबूझकर रुकावट डालना और एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को वोट डालने के अधिकार से वंचित करना शामिल है।

बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना संविधान के आर्टिकल ३२४ के तहत आता है, जिसमें कहा गया है, ...मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही और उन्हीं वजहों से हटाया जाएगा। कानून के मुताबिक, जिस सदन में नोटिस दिया जाता है, उस सदन के कम से कम सौ सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, वहीं अगर राज्यसभा में नोटिस दिया जाता है, तब राज्यसभा के करीब ५० मेंबर्स का समर्थन होना चाहिए।

विश्व किडनी दिवस पर जागरूकता शिविर का आयोजन

बोकारो (ससे): बोकारो इस्पात संयंत्र के बोकारो जनरल अस्पताल (बीजीएच) में आज दिनांक १२ मार्च २०२६ को 'विश्व किडनी दिवस' के उपलक्ष्य में एक विशेष स्वास्थ्य जाँच शिविर एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ) डॉ. आनंद कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ) डॉ. अनिंदा मंडल एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ) डॉ. इंद्रनील चौधरी द्वारा परम्परागत तरीके से दीप प्रज्वलित कर किया गया.विश्व किडनी दिवस २०२६ की थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल: केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्ट द प्लैनेट के अंतर्गत

आयोजित यह कार्यक्रम अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. सिमाल माडीं के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ. शिविर के दौरान बीएसएल कर्मियों, उनके परिजनों एवं आम नागरिकों के लिए ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिनरी प्रोटीन एवं शुगर की निःशुल्क जाँच की गई तथा विशेषज्ञों द्वारा परामर्श प्रदान किया गया.

शिविर में उपस्थित चिकित्सकों एवं आहार विशेषज्ञों ने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए नियमित जाँच, संतुलित आहार और मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण को अनिवार्य बताया. इस अवसर पर आयोजित एक तकनीकी संगोष्ठी में डॉ. प्रत्युष रोशन ने 'ए.बी.ओ. असंगति' किडनी प्रत्यारोपण की आधुनिक पद्धति पर विस्तृत प्रकाश डाला.

उन्होंने बताया कि यह उपचार उन मरीजों के लिए एक नया जीवन है जिन्हें उपयुक्त डोनर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं. डॉ. पी के बेहरा ने इस वर्ष की थीम और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में किडनी रोगों की रोकथाम पर अपनी प्रस्तुति दी.

कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. साकेत मिश्रा, वरीय चिकित्सा अधिकारी डॉ. आकाश कांत, डॉ. विकास, डॉ. सुहासिनी, डॉ. अन्नेसा तथा स्कूल ऑफ नर्सिंग की प्रशिक्षुओं एवं परिचारिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय देते हुए सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. साकेत मिश्रा ने इस अवसर पर स्वेच्छा से रक्तदान भी किया.बोकारो जनरल अस्पताल द्वारा आयोजित यह स्वास्थ्य पहल नागरिकों को निवारक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है.

किडनी रोगों के प्रति समय पर सजगता और आधुनिक उपचार पद्धतियों की जानकारी न केवल जीवन रक्षा में सहायक है, बल्कि यह स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण के प्रति बोकारो इस्पात संयंत्र की अटूट प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है.

नवादा में युवक की गला रेतकर हत्या

नवादा (एजेंसी): बिहार के नवादा जिले से अपराधियों द्वारा एक युवक का गुरुवार को गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है. यह घटना नरहट थाना क्षेत्र के बनिया बीघा के बादलपुर गांव का बताया जा रहा है। लगभग मृतक की पहचान अनुज यादव के रूप में हुई है जिसकी उम्र ३० वर्ष बतायी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, अनुज यादव का शव गेहूं के खेत से बरामद हुआ है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सुचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।पुलिस द्वारा पूछताछ में मृतक की पत्नी अंशु कुमारी ने बताया कि उनके पति बुधवार की रात करीब ८ बजे खेत में काम करने के लिए घर से निकले थे। वह अक्सर खेत में ही सो जाते थे। उस रात भी सब यही सोचते रहे कि वो घर लौटकर आएंगे, लेकिन जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटे, तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की।

जन्मदिन पर उपायुक्त ने दिव्यांग बच्चों-बुजुर्गों के साथ बिताया समय

बोकारो (ससे): उपायुक्त अजय नाथ झा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर-०५ स्थित मानव सेवा आश्रम में दिव्यांग बच्चों के साथ कुछ समय बिताया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उनका कुशल-क्षेम जाना और बच्चों का मुंह मीठा कराया। उपायुक्त ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उन्हें प्रोत्साहित किया।

मानव सेवा आश्रम में उपायुक्त ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत संचालित मरम्मति कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्रम में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ताकि दिव्यांग बच्चों की देखभाल और शिक्षा में सुधार किया जा सके।

इसके बाद उपायुक्त ने सोलागडीह स्थित बाबा

वैद्यनाथ जन सेवा समिति वृद्ध आश्रम पहुंचे। उन्होंने बुजुर्गों का हालचाल जाना, उनके स्वास्थ्य और दैनिक जीवन से जुड़ी आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा बुजुर्गों का मुंह मीठा कराया।

वृद्ध आश्रम के समीप दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्मृति में स्थापित गुरूजी वाटिका का भी निरीक्षण करते हुए उपायुक्त ने परिसर की सफाई, रखरखाव और सौंदर्यीकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त के इस पहल से बच्चों और बुजुर्गों में प्रसन्नता देखी गई। उपस्थित लोगों ने इसे समाज में सकारात्मक संदेश देने वाला कदम बताया।

BEFORE : THE EXECUTIVE MAGISTRATE AT DHANBAD

AFFIDAVIT

I, ARJUN MAHATO S/O Udi Mahato, Date of Birth : 1.1.1962 by faith Hindu, by occupation Labour resident of Phatehpur Balu Gadda Jharia, P.O. & PS: Jharia, Dist. Dhanbad do hereby solemnly affirm on oath and declare as under :-

1. That, In my Aadhar Card No. 7257 5343 3426 and in my PAN Card No. EPCPM8612D in which my name has mentioned as ARJUN MAHATO.
2. That In my L.I.C. Policy my name has been mentioned as ARJUN RAUT. Policy No. 54393442 8.
3. That, ARJUN MAHATO & ARJUN RAUT is the name of same and one person i.e my self name.
4. That, I am affixing my photograph for my proper indentification.
5. That, I amswearing this affidavit for submit it befor the authority concerned for needful purpose.

Sl. No 4779 dt. 4/11/25

लिंग चयन एवं भ्रूण लिंग जांच करना कानूनन अपराध है : उपाधीक्षक सदर अस्पताल

बोकारो (ससे): बोकारो सदर अस्पताल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में जानकारी देना तथा समाज में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के संदेश को सशक्त बनाना था। मौके पर उपाधीक्षक सदर अस्पताल डॉ एनपी सिंह, डॉ राज कुमार दास, पवन कुमार श्रीवास्तव, डीपीएम हीना गौरव बरवाल सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान भ्रूण लिंग जांच एवं भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम, समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, महिला सशक्तिकरण तथा बेटियों के सम्मान और अधिकारों के विषय में उपाधीक्षक सदर अस्पताल डॉ एनपी सिंह के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि लिंग चयन एवं भ्रूण लिंग जांच करना कानूनन अपराध है और इसके लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया।

लोक कला राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन

बोकारो (ससे): मैथिलानियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था सखी बहिनपा मैथिलानी समूह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची में दो दिवसीय लोक कला राष्ट्रीय महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस महोत्सव में सखी बहिनपा मैथिलानी समूह की बोकरो इकाई ने भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बोकरो इकाई की प्रभारी अमिता झा व महासचिव उषा झा के मार्गदर्शन में बोकरो इकाई से सांस्कृतिक प्रभारी जयंती पाठक, कोषाध्यक्ष सुजाता झा, मीडिया प्रभारी संगीता मुक्तेश, सदस्या कल्याणी मिश्रा, बीना झा, पूनम झा, आशा पाठक, इंदिरा झा, नीलू झा, मधु ठाकुर, रेखा झा, पूनम, वंदना झा शामिल हुईं। बोकरो इकाई ने समूह गीत चंद्रमुखी सन गौरी हमर छथि सूर्य सन करैतीं जमाई... की सुमधुर प्रस्तुति से सबकी प्रशंसा पाई।

रांची के मोराबादी स्थित द लंक्वेवी रिजार्ट में आयोजित इस राष्ट्रीय महोत्सव में दिल्ली, कोलकाता, दुबई, बेंगलुरु, पटना, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर, गोड्डा, धनबाद, कोडरमा, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी आदि शहरों से २०० से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेकर अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व महाकवि विद्यापति रचित भगवती वंदना जय-जय भैरवि असुर भयाउनि... की सुमधुर प्रस्तुति से हुई। कार्यक्रम में रांची की मेयर श्रीमती रौशनी खलको सहित कई गणमान्य अतिथियों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। रैंप वाक सखी बहिनपा दरभंगा इकाई, गीत दिल्ली इकाई, नाटक कोडरमा इकाई, जोगीरा मधुबनी इकाई, नृत्य धनबाद एवं गोड्डा इकाई व समूह गीत सखी बहिनपा बोकारो इकाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। अतिथियों व आयोजन में शामिल सभी प्रतिभागियों को सखी बहिनपा की ओर से सम्मानित किया गया। आयोजन की सफलता में सखी बहिनपा समूह की संस्थापिका आरती झा, रांची इकाई की प्रभारी बबिता झा, मनोरमा झा, अनिता झा, सांत्वना मिश्रा, प्रतिभा मिश्रा, पूनम मिश्र, मधु आदि का प्रशंसनीय योगदान रहा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रस्तावित दौरे को लेकर डीसी ने की बैठक

बोकारो (ससे): जिले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के १३-१४ मार्च को प्रस्तावित दौरे को लेकर उपायुक्त अजय नाथ झा ने गोपनीय कक्ष में संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्नावली प्रारूप के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यान्वित संवैधानिक संरक्षोपाय, कल्याण एवं विकास योजनाओं से संबंधित सूचनाओं के संकलन एवं तैयारी की विस्तृत समीक्षा की गई। आयोग की अध्यक्ष डा. आशा लकड़ा व टीम का बोकारो दौरा निर्धारित है। इस दौरान जिले में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों तथा संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा* की जाएगी।

उन्होंने आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रश्नावली प्रारूप के आधार पर तैयार उत्तरों की क्रमवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार कर अंतिम प्रतिवेदन तैयार करने तथा उसे शाम तक आयोग को भेजने का निर्देश दिया।

बैठक में अपर समाहर्ता (एसी) मो. मुमताज अंसारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालखो, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, डीएसडब्ल्यूओ डॉ. सुमन गुप्ता, कार्यपालक अभियंता चास श्री एस. तिवारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी त्रिवुताज, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राम प्रवेश राम, डीडीएमओ शक्ति कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, डीपीओ यूआइडी शैलेंद्र मिश्रा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ को दिया जा रहा प्रशिक्षण

बोकारो (ससे): विशेष गहन पुनरीक्षण २०२६ के तहत मतदाता सूची को अधिक शुद्ध एवं अद्यतन बनाने के उद्देश्य से उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रेमचंद सिन्हा द्वारा बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को ३७-चन्दनकियारी (अजा) विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी चास से संबंधित बीएलओ को प्रखंड समागार, चास में प्रशिक्षण दिया गया।प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन, निर्धारित प्रारूप के अनुसार घरों पर स्टीकर चिपकाने तथा हाउस नंबर अंकित करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

उन्हें बताया गया कि स्टीकर को घर के मुख्य द्वार या ऐसी जगह पर चिपकाया जाए, जहाँ वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे और सुरक्षित रहे। इसके साथ ही हाउस नंबर अंकित करने की प्रक्रिया भी विस्तार से समझाई गई, ताकि प्रत्येक घर की पहचान स्पष्ट रूप से हो सके और भविष्य में मतदाता सूची से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। सभी बीएलओ को निर्देश दिया गया कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सही ढंग से हाउस नंबर अंकित करें तथा संबंधित जानकारी को समय पर पोर्टल/ऐप में अपडेट करना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि, बुधवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया था कि सभी बीएलओ को हाउस नंबर देने तथा स्टीकर लगाने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ही दिया जाएगा। इसी क्रम में आज पहले एईआरओ से संबंधित बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। जिले में कुल १३ एईआरओ एवं लगभग १६०० बीएलओ हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से संबंधित क्षेत्रों में जाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण २०२६ के कार्यों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभावी ढंग से संपादित किया जा सके।

गरगा डैम में नहाने के दौरान किशोर की डूबने से मौत

बोकारो (ससे): गरगा डैम में नहाने के दौरान १७ वर्षीय किशोर गोलू की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद गुरुवार को एनडीआरएफ टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी खोजबीन के बाद शव को बाहर निकाला गया। घटना पर उपायुक्त अजय नाथ झा ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य देने की प्रार्थना की है। उपायुक्त ने शव को खोज निकालने के लिए चलाए गए अभियान में जुटे डीडीएमओ शक्ति कुमार, एनडीआरएफ टीम और स्थानीय गोताखोरों के प्रयासों की सराहना की।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह (जिला भू-अर्जन शाखा)

ई-मेल:-dlao-giridih@jharkhandmail.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

गिरिडीह जिले में NH-100 के कि0मी0 0 से कि0मी0 4 (गिरिडीह) तक भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) परियोजना अंतर्गत मौजा-जरमुर्ण का निम्नांकित अवार्ड अज्ञात घोषित है :-

क्र0	अंचल का नाम	मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट नं0	अवार्ड सं0	किस्म	रकबा (एकड़ में)	राशि
1	बगोदर	जरमुने	186	5818/1	44	टांड दो	0.0040	217936.31

उक्त अज्ञात अवार्ड पर जिलो साव वो जोधो नायक पिता स्वा धनश्याम तेली, ग्राम-जरमुने के द्वारा खतियान के आधार पर दावा किया गया है। अपने दावा के समर्थन में आवेदक ने खतियान एवं लगान रसीद समर्पित किया है।

स्थलीय जाँच के आधार पर कार्यालय अगीन एवं कानूनगो के द्वारा आवेदक को मुआवजा नोटिस निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रस्तगत अर्जित भूमि के संदर्भ में यदि कोई रैयत चाहें तो संबंधित राजस्व कागजात के साथ इस प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर अपना लिखित आपत्ति/दावा जिला भू-अर्जन कार्यालय, गिरिडीह में समर्पित कर सकते हैं।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
गिरिडीह।

PR.NO.374924 Land Reforms(25-26):D

रजीस्ट्री सं.डी. एल .- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.डी.एल.ए 10022026.269988
CG-DL-E-10022026-269988
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 06, 2026/माघ 17, 1947
No. 566] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 06, 2026/MAGHA 17, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना
नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 596(अ).– केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3111(E) तारीख 11/07/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखण्ड राज्य के जामतारा जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 419 के कि.मी. 39.700 से कि.मी. 41.500 तक उच्च स्तरीय गोलपहाड़ी पुल का निर्माण हेतु अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 27.07.2025" को "दैनिक जागरण" और "हिन्दुस्तान" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3–ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य के जामतारा जिला में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 419 के कि.मी. 39.700 से कि.मी. 41.500 तक उच्च स्तरीय गोलपहाड़ी पुल का निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नामः झारखण्ड				जिले का नामः बोकारो	
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी /हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नामः जामतारा सदर					
गाँव का नामः गोलपहाड़ी					
1	2121	निजी (निजी)	धानी दोयम	0.101983	चितु हाड़ी आरटीए वंशजः- विशाल हाड़ी पिता स्वा उदय हाड़ी वो गणेश हाड़ी वो अनाथ हाड़ी पिता स्वा बकगी हाड़ी वो चुड़ामन हाड़ी वो लखन हाड़ी वो सुशील हाड़ी वो महेन्द्र हाड़ी पिता स्वा महावीर हाड़ी वो दुर्योधन मुखियार पिता स्वा कैलाश मुखियार ।
गाँव का नामः भण्डारो					
2	286	निजी (निजी)	धानी सेम	0.0283286	फोट दसरथ मराण्डी आरटीए वंशजः-जितान मराण्डी पिता स्वा नन्दलाल मराण्डी वो फुचा मराण्डी वो भुटका मराण्डी पिता स्वा लखन मराण्डी।
3	545	निजी (निजी)	धानी सेम	0.1412384	मुरली मरांडी आरटीए वंशजः- मोहरील टुडू पिता स्वा काली टुडू वो जितन मराण्डी पिता स्वा नन्दो वो फुचा मराण्डी वो भुटका मराण्डी पिता स्वा लखान मराण्डी। मुरली मरांडी आरटीए वंशजः- मोहरील टुडू पिता स्वा काली टुडू वो जितन मराण्डी पिता स्वा नन्दो वो फुचा मराण्डी वो भुटका मराण्डी पिता स्वा लखान मराण्डी।
			कुल	0.27155	

PR.NO.374835 District(25-26):D

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी जामताड़ा ।

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, बोकारो
बाई पास रोड़, चास, बोकारो 827013
कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन हेतु आवेदन तिथि का विस्तारीकरण

आवश्यक सूचना

सत्र 2026–27 में जिले के सभी प्रखण्डों के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन हेतु प्रक्रिया आरम्भ हो गयी है। नामांकन हेतु पंजीकरण ऑनलाईन माध्यम से http://transformingbokarokgbv.com पोर्टल पर किया जा सकता है, अथवा सरकारी मध्य विद्यालय/संबंधित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन हेतु निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर संबंधित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/ झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय में दिनांक 28.02.2026 तक जमा किया जाना था।

आवेदन हेतु अंतिम तिथि दिनांक 15.03.2026 तक विस्तारित की जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मुस्लिम एवं गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार के बालिकाओं के लिए सीटें आरक्षित है। नामांकन में छीजित, अनाथ, एकल माता–पिता, सुदूरवर्ती क्षेत्र, आदिम जनजाति समूह, बाल श्रम से प्रभावित एवं नक्सल प्रभावित परिवार/क्षेत्र के बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षण, आवासन (छात्रावास), भोजन एवं पोशाक की व्यवस्था है। विद्यालय में नामांकित सभी बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। विद्यालय में योग्य शिक्षिका, कम्प्यूटर शिक्षा, खेलकूद की सुविधा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा, कैरियर कॉउन्सेलिंग जैसी सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

जिले के सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि जरूरतनंद बालिकाओं के नामांकन हेतु उपर्युक्त अंकित पोर्टल के माध्यम से अथवा आवेदन पत्र के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराएँ।

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बोकारो

PR 374820 (Health Med Edu and Family Welfare)25-26*D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भ0नि0वि0, भवन प्रमण्डल जामताड़ा

निविदा आमंत्रण सूचना सं0–64/2025–26.

1. विज्ञापनदाता का नाम : कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, जामताड़ा
2. परिमाण विपत्र बिक्री की अंतिम तिथि : 07.04.2026 तक (1.00 अपराह्न तक)
3. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : 08.04.2026 को 3.00 बजे अप0 तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 08.04.2026 को 3.30 बजे अप0
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान : 1) अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, भवन अंचल, दुमका। 2) कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, भवन प्रमंडल, जामताड़ा। 3) सहायक अभियंता का कार्यालय, भवन अवर प्रमंडल, जामताड़ा।
6. निविदा प्राप्ति का स्थान :– तथैव– – तथैव–
7. कार्य का विवरण :–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Repair Work of "Male Ward (1 to 4)" at Mandal Kara, Jamtara district-Jamtara for the Year-2025-26.	37,36,300=00	75,000=00	5,000=00	03 Months
2	Repair Work of "Kitchen & Library Building" at Mandal Kara, Jamtara district-Jamtara for the Year-2025-26.	23,76,200=00	48,000=00	5,000=00	03 Months
3	Repair Work of Female Ward at Mandal Kara, Jamtara district-Jamtara for the Year-2025-26.	16,97,700=00	34,000=00	5,000=00	02 Months
4	Repair and Painting of P.D.J. Residence Building at Jamtara for the Year-2025-26.	8,10,900=00	16,500=00	1,250=00	02 Months

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, जामताड़ा

PR 374865 (Building) 25-26 (D)

सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की बैठक

पटना (एजेंसी): बिहार राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए की अहम बैठक गुरुवार को होगी. इसकी जानकारी बीजेपी प्रवक्ता ने दी. बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद पहली बार एनडीए विधानमंडल दल की अहम बैठक बुलाई गई है. यह बैठक उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित की जाएगी, जिसमें चुनाव पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे.

उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर कहा कि यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है. राज्यसभा के चुनाव होने हैं और इसे लेकर हमारे एनडीए के सभी घटक दलों के विधायक बैठक में हिस्सा ले रहे हैं. गठबंधन के अंदर किसी भी तरह के मतभेद नहीं है. एनडीए पूरी तरह से एकजुट और यूनाइटेड है. हमारे सभी पांचों उम्मीदवार १६ तारीख को विजयी होंगे. जिस प्रकार से एनडीए में एकजुटता रही है और हमने लगातार एक-दूसरे को सम्मान देने का काम किया है, आगे भी बिहार में एनडीए इसी मजबूती के साथ एकजुट रहेगा.

दरअसल, राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गई है. कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपमानित करने का गंभीर आरोप लगाया है. कांग्रेस के प्रवक्ता नदीम अंसारी ने एक बयान जारी कर कहा है कि बीजेपी जानबूझकर नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है.

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के इसी रवैये के कारण वोटिंग की नौबत आ गई है. चुनाव परिणामों को लेकर बड़ा दावा करते हुए अंसारी ने कहा कि यह निश्चित है कि इस चुनाव में एनडीए गठबंधन की हार होगी और इंडिया गठबंधन के एकमात्र उम्मीदवार की जीत होगी.राजद अपने बयान में कहा कि एनडीए के नेता चाहे जितनी भी बैठकें और कवायदें कर लें, राज्यसभा चुनाव में पांचवीं सीट पर उनकी हार पूरी तरह से सुनिश्चित है. उन्होंने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अंदर 'जूतमपैजार' जैसी स्थिति बनी हुई है. राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने दावा किया कि जिस दिन राज्यसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड समेत एनडीए के तमाम नेताओं के हाथ सिर्फ मायूसी ही लगेगी.

जदयू प्रवक्ता निहोरा सिंह ने कहा कि राज्य में होने वाले राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए गठबंधन की बैठक बुलाई गई है. उन्होंने कहा कि जिस तरह चुनाव के समय हर पार्टी अपने गठबंधन के साथियों के साथ बैठक करती है, उसी तर्ज पर आज एनडीए की भी यह अहम बैठक हो रही है. इस बैठक में एनडीए के सभी विधायक और विधानमंडल दल के नेता हिस्सा लेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा राज्यसभा की पांचों सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार करना है.

हॉस्टल मालिक को नहीं मिली जमानत

पटना (एजेंसी) पटना में गुरुवार को नीट छात्रा मौत मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। बता दें कि मनीष रंजन पटना के बेउर जेल में बंद हैं। सुनवाई में मनीष रंजन को कोर्ट में पेश किया गया। करीब चार घंटे तक चली इस सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। हालांकि लंबी बहस चलने के बाद भी कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आया है। कोर्ट ने फिलहाल जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जानकारी के मुताबिक चार घंटे चले इस सुनवाई में करीब दो घंटे तक बहस जज के चेंबर में चली। इससे पहले ओपन कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने दलीलें रखीं। पीड़ित पक्ष के वकील ने पटना हाईकोर्ट के फुल बेंच के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए मनीष रंजन को जमानत देने का विरोध किया। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने आपत्ति जताई।

बिहार में अंचल अधिकारियों की हड़ताल पर सख्त हुई सरकार

पटना (एजेंसी): बिहार में अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारियों की हड़ताल अब बड़ा प्रशासनिक मुद्दा बन गई है। बुधवार को हड़ताल के तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में अधिकारी अपने काम पर नहीं लौटे, जिससे राज्य के आधे से अधिक अंचल कार्यालयों में कामकाज लगभग ठप हो गया। जमीन से जुड़े मामलों और प्रमाणपत्र सेवाओं के प्रभावित होने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है।

विभाग ने बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, भू-अर्जन निदेशालय, चकबंदी निदेशालय के निदेशकों के साथ-साथ सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को आधिकारिक पत्र भेजा गया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि ९ मार्च से शुरू हुई हड़ताल के दौरान कितने अधिकारी अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहे और कितने हड़ताल में शामिल हुए, इसकी पूरी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भेजी जाए। साथ ही यह भी पूछा गया है कि २ फरवरी से अब तक किन-किन अंचलों में कामकाज प्रभावित रहा है।

इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की रणनीति तय करेगी और जरूरत पड़ने पर हड़ताल में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसी बीच प्रशासनिक सख्ती का संकेत तब भी मिला जब बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार राजस्व सेवा के पांच अधिकारियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। जिलाधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर इन अधिकारियों के त्यागपत्र को उनकी आवेदन तिथि से प्रभावी मानते हुए मंजूरी दी गई है। जिन अधिकारियों के इस्तीफे स्वीकार किए गए हैं उनमें वैशाली के गोरौल के तत्कालीन अंचलाधिकारी अंशु कुमार, रोहतास के बिक्रमगंज के राजस्व अधिकारी राजन कुमार, सारण जिले के परसा की राजस्व अधिकारी शिवांगी पांडेय, रोहतास के राजपुर की अंचलाधिकारी अंकिता वर्मा और हाजीपुर सदर की राजस्व अधिकारी स्मृति कुमारी शामिल हैं। इससे पहले विभाग के १०० दिन पूरे होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल पर गए अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि डयूटी से अनुपस्थित अधिकारियों के दिनों की गणना की जा रही है।

यदि कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो उसके खिलाफ सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार का साफ संदेश है कि यदि सरकारी सेवा में रहना है तो जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा, अन्यथा प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है।

6477 विद्यार्थियों ने दी अंग्रेजी की परीक्षा

बोकारो (ससे): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से गुरुवार को कक्षा १२वीं की अंग्रेजी विषय की बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई। सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर एवं डीपीएस बोकारो के प्राचार्य डॉ. ए. एस. गंगवार के अनुसार, बोकारो जिले के सभी २३ परीक्षा केंद्रों को मिलाकर कुल ६४७७ विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। ६४७६ विद्यार्थियों ने इंग्लिश कोर तथा केवल एक सेंटर जीजीपीएस, सेक्टर-५ पर सिर्फ ०१ परीक्षार्थी ने इंग्लिश इलेक्टिव विषय की परीक्षा दी। कुल पंजीकृत ६५४३ में ६६ परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं बिना किसी कदाचार के संपन्न हुईं। केंद्रबार जानकारी देते हुए डॉ. गंगवार ने बताया कि सरस्वती विद्या मंदिर- इसी में ३३६, डीएवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-४ में ८२४, चिन्मय विद्यालय सेक्टर- ५ में ३१०, होलीक्रॉस स्कूल बालीडीह में २०९, पिट्स मॉडर्न गोमिया में ३०६, डीएवी पब्लिक स्कूल ढोरी में ९३, जीजीपीएस- ५ में ३९९ (०१-इंग्लिश इलेक्टिव), दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर-४ में २७०, आदर्श विद्या मंदिर, दारकूनगर में १७३, एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर- ४ में ८७८, डीएवी स्वांग में २६१, बीआरएल डीएवी भंडारीदह में २५१, श्री अय्यप्पा पब्लिक स्कूल, सेक्टर-५ में ७९७, पेंटिकॉस्टल एसेंबली स्कूल सेक्टर-१२ में २०२, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल सेक्टर- ६ में २१०, जीजीपीएस चास में २२७, डीएवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर- ६ में ९०, होलीक्रॉस स्कूल चंदनकियारी में ३१, डीएवी पब्लिक स्कूल तेनुघाट में ११३, डीपीएस चास में ५७, केंद्रीय विद्यालय-१ सेक्टर-४ में २१७, केंद्रीय विद्यालय सीटीपीएस चंद्रपुरा में १९८ और केंद्रीय विद्यालय डीवीसी बोकारो थर्मल में २४ परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित हुए।

6 महीनों में वादे पूरे नहीं हुए तो सड़क पर उतरेगी जन सुराज

पटना (एजेंसी): बिहार नवनिर्माण यात्रा के दौरान जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बुधवार को पहली बार औरंगाबाद पहुंचे। वे समाहरणालय के पास एक निजी होटल में प्रेस वार्ता किए। मीडिया से बातचीत के दौरने प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कई सवाल उठाए और कहा कि बिहार के लोगों ने १० हजार के लालच में आकर उन्हें वोट दिया। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। चुनाव के दौरान सरकार ने विकास को लेकर जो भी वादे जनता से किए हैं, उसे ६ महिने के भीतर पूरा करे।

प्रशांत किशोर ने सरकार को बकायदा समय की याद दिलाई और कहा कि मई २०२६ में यह अवधि पूरी हो जाएगी। इसलिए सरकार को अपने वादों को जल्द पूरा करना चाहिए। अगर सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सरकार समय पर अपना वादा पूरा नहीं करती है तो जन सुराज पार्टी सड़क पर उतरने का काम करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी जनता के बीच जाएगी और सरकार से सवाल पूछेगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली और गुजरात के इशारों पर चलने वाला मुख्यमंत्री बिहार को देगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव में जदयू को मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया।

साथ ही कहा कि बिहार की जनता अब भाजपा का असली चेहरा देखेगी। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि सासाराम के चार बच्चों की गुजरात में टंकी साफ करते समय मौत हो गई, लेकिन इस मामले में अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

उन्होंने बताया कि जन सुराज संगठन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके तहत वे बिहार के प्रत्येक जिले में तीन-तीन दिन बिताकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और चुनाव के दौरान हुई गलतियों की समीक्षा कर सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही जन सुराज के नए संगठन की घोषणा की जाएगी और वार्ड स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि १५ अप्रैल तक पूरे बिहार का दौरा कर साथियों से चर्चा की जाएगी। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि जन सुराज पंचायत चुनाव में दल के आधार पर हिस्सा लेगी या नहीं।

गैस संकट का असर अस्पताल और छात्रावासों तक पहुंचा

लखनऊ,(ईएमएस): लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में गैस संकट का असर अब मरीजों की थाली तक पहुंच गया है। हालात ऐसे बन गए कि जहां सामान्य दिनों में मरीजों को दाल-सब्जी के साथ चार रोटियां मिलती थीं, वहीं अब सिर्फ दो रोटियां दी जा रही हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बाधित होने से किचन संचालकों ने मजबूरी में रोटियों की संख्या घटाकर चावल की मात्रा बढ़ा दी है। इस फैसले के बाद कुछ मरीजों ने शिकायत भी की है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गैस संकट का असर सिर्फ मरीजों तक सीमित नहीं रहा। केजीएमयू के कई छात्रावासों की मेस में भी रसोई ऐसी ही नौबत आ गई। कई मेस में जैसे-तैसे खाना बनाया गया, लेकिन आधा-अधूरा भोजन देखकर छात्रों को बाहर जाकर खाना पड़ा। मेस संचालकों का कहना है कि अगर गैस की आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में मेस चलाना मुश्किल होगा। चावल की मात्रा बढ़ाने का फैसला परेशानी बन गया है।

डॉक्टरों के मुताबिक कई बीमारियों में मरीजों को चावल खाने से मना किया जाता है, ऐसे में रोटियों की कटौती उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। मरीजों और परिजनों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पताल में इलाज के साथ सही भोजन भी उतना ही जरूरी है। स्थिति को संभालने के लिए केजीएमयू प्रशासन अब वैकल्पिक इंतजाम करने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली से चलने वाला रोटी मेकर लाने की तैयारी की जा रही है ताकि गैस पर निर्भरता कम की जा सके।

नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान लालू राज को याद कर हुए भावुक

पूर्णिया : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने से पहले समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के तहत नीतीश कुमार आज पूर्णिया दौरे पर हैं। पूर्णिया में नीतीश कुमार ने मंच से जनता को संबोधित किया। इस दौरान वो लालू राज को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने लालू राज के वो दिन लोगों को याद करवाया और कहा कि लालू राज एक ऐसा दौर था जब लोग डरे सहमे-से रहते थे। नीतीश कुमार ने इस दौरान लालू-राबड़ी पर हमलावर होते हुए कहा कि वो कुछ किया था जी... महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं किया। अपने ७ साल तक सता में रहा और खुद गया तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। महिलाओं को ना तो कोई आजादी थी और ना ही वो घर से बाहर निकल सकती थी। लेकिन अब देखिए महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं।

उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि याद है ना कि पहले क्या स्थिति थी। लोग शाम में घर से निकलने से डरते थे। सब को बोल दिया जाता था कि शाम के बाद घर से नहीं निकलना है। आगे उन्होंने कहा कि जब हम केंद्र में थे, उस दौरान जब भी अपने इलाके में आते थे और अगर किसी से मिलने जाते थे तो हमको उनके घर का दरवाजा खुद खटखटा के कहना पड़ता था कि हम आ गए हैं। उन्हें यह बताना पड़ता था कि डरो नहीं हम नीतीश कुमार हैं। तब लोग बाहर आते थे। सीएम नीतीश ने कहा कि, जब २४ नवंबर २००५ को पहली बार एनडीए की सरकार बनी तब से ही तो कानून का राज्य है और लगातार विकास हो रहा है। सीएम नीतीश ने कहा कि इसके पहले वाले जो भी थे वो लोग कोई काम नहीं करते थे। लेकिन आज देखिए आज ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले समाज में हिंदू- मुस्लिम में लड़ाई हमेशा होते रहता था। इलाज का हाल बदतर था। सड़कों की स्थिति दयनीय थी। लेकिन हम लोग जब सता में आए तो विकास का काम किए। एनडीए के राज्य में प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा मिला।

ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए सरकार ने बनाई 28 टीमें

पटना (एजेंसी): घरेलू गैस उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने एलपीजी की ब्लैकमार्केटिंग और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पटना के जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति और वितरण की निगरानी के लिए २८ धावा दलों का गठन किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि एलपीजी की ब्लैकमार्केटिंग या जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन के अनुसार, घरेलू एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करने तथा उसकी नियमित मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर एक हेल्पलाइन भी स्थापित की गई है। कोई भी उपभोक्ता या आम नागरिक सुबह ९ बजे से शाम ६ बजे तक दूरभाष संख्या ०६१२-२२१९८१० पर कॉल कर गैस से संबंधित शिकायत, सूचना या अन्य जानकारी दे सकते हैं।

रसोई गैस की किल्लत पर कहीं फिर से बर्तन न पिटवाने लगे सरकार : मुकेश सहनी

पटना (एजेंसी): विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बिहार में रसोई गैस की किल्लत को लेकर सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि सरकार भले ही रसोई गैस की कोई कमी नहीं होने की बात कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि आज गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक में रसोई गैस के लिए लोग परेशान हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गैस सिलेंडर की कमी पर सरकार कहीं कोरोना त्रासदी की तरह फिर से बर्तन नहीं पिटवाने लगे. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार को लोगों को खाली गैस सिलेंडर पिटवाना चाहिए, जिससे रसोई गैस की कमी दूर हो सके. वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि कुछ जिलों में रसोई गैस के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतार लगी हुई है, तो कई उपभोक्ताओं को ब्लैक में रसोई गैस खरीदनी पड़ रही है. कई कंपनियों द्वारा ई-वेबाईसी करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है. उन्होंने सरकार से इस समस्या को दूर करने को लेकर जल्द कदम उठाने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिति रही, तो घर में खाना पकाने पर संकट आ जाएगा. गैस की कमी की वजह से कालाबाजारी बढ़ने की पूरी संभावना है. वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि पहले से ही महंगी गैस की मार झेल रहे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह दोहरी मार हो गई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस पर स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और जमीनी सच्चाई की जांच करवाकर स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए,

तेजस्वी यादव जा सकते हैं बंगाल के दौरे पर

पटना (एजेंसी): बिहार में हालिया दिनों में पक्ष हो या विपक्ष दोनों ही खेमों के नेता सुर्खियां बटोर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार सहित पूरे देश में सियासी हलचल तेज है। इस बीच राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के दो दिवसीय बंगाल दौरे पर जाने की सूचना सामने आ रही है।

फिलहाल यह जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हुई है कि वह वहां किन नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव को लेकर भाजपा भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बिहार के कई भाजपा नेता लगातार बंगाल जाकर प्रचार-प्रसार में जुटे हुए हैं। राजद पार्टी कोशिश कर रही है कि इस बार अपनी सरकार बंगाल में बनाए। इसे लेकर तेजस्वी यादव का बंगाल दौरा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राहुल गांधी मानहानि केस में आवाज के नमूने की जांच की मांग, सुनवाई 23 को

सुलतानपुर (ईएमएस): कांग्रेस नेता एवं सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में गुरुवार को एमपी-एमएलए विशेष अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। परिवादी पक्ष ने अदालत में अर्जी दाखिल कर सीडी में उपलब्ध ऑडियो-वीडियो की सत्यता की जांच के लिए राहुल गांधी के वॉयस सैंपल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजने की मांग की है। अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए २३ मार्च की तारीख नियत की है।

परिवादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अदालत में दायर प्रार्थना पत्र में कहा कि प्रस्तुत सीडी में दर्ज ऑडियो-वीडियो में मौजूद आवाज की पुष्टि के लिए राहुल गांधी का वॉयस सैंपल लेकर उसकी वैज्ञानिक जांच कराई जानी आवश्यक है। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने बताया कि इस अर्जी पर नियत तिथि पर आपत्ति दाखिल की जाएगी।

यह मामला वर्ष २०१८ में बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़ा है। इस संबंध में पूर्व कोऑपरेटिव चेयरमैन एवं भाजपा नेता विजय मिश्र ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ४ अगस्त २०१८ को सुलतानपुर की अदालत में मानहानि वाद दाखिल किया था।

मामले में अदालत ने २७ नवंबर को राहुल गांधी को तलब किया था। इसके बाद उन्होंने २० फरवरी २०२४ को अदालत में उपस्थित होकर जमानत कराई। वहीं २५ जुलाई २०२४ को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर उनका बयान भी दर्ज किया गया।

बीते २० फरवरी को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होकर राहुल गांधी ने आरोपों से इंकार करते हुए कहा था कि यह मुकदमा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और उनकी व कांग्रेस पार्टी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से राजनीतिक दुर्भावना के तहत दायर किया गया है। अब परिवादी द्वारा दाखिल वॉयस सैंपल जांच की अर्जी पर अदालत के निर्णय के बाद ही मामले में आगे बहस होने की संभावना है।

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक नई चतुरंगिणी व्यवस्था बनाने का ऐलान किया

लखनऊ (ईएमएस): उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक नई 'चतुरंगिणी' व्यवस्था बनाने का ऐलान किया। यह घोषणा उन्होंने कांशीराम स्मृति उपवन में ४० दिन चली गौ प्रतिष्ठार्थ धर्मयुद्ध यात्रा के समापन के मौके पर की। शंकराचार्य ने कहा कि संत समाज गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगा और बताएगा कि जो लोग गाय की रक्षा के पक्ष में खड़े हैं, जनता को उनका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान किसी राजनीतिक दल के समर्थन के लिए नहीं होगा, बल्कि लोगों को तथ्यों और धर्म के आधार पर जागरूक करने का प्रयास होगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित 'चतुरंगिणी' व्यवस्था चार वर्गों से मिलकर बनेगी-सन्यासी, वैरागी, उदासीन और सामान्य अनुयायी। इस व्यवस्था का उद्देश्य गो-संरक्षण और धर्म-संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित रूप से कार्य करना है। साथ ही इसमें शामिल होने वाले हर व्यक्ति का पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की गलत गतिविधि या अवांछित तत्वों की भागीदारी न हो सके। शंकराचार्य ने बताया कि यात्रा के समापन के बाद अब ५२ दिन तक 'ज्ञान यज्ञ' आयोजित किया जाएगा। इसमें संत समाज गांव-गांव जाकर लोगों को धर्म, सत्य और संस्कृति का संदेश देगा। इसके बाद ८१ दिनों की 'गविष्ठि परिक्रमा यात्रा' निकाली जाएगी, जो ३ मई को गोरखपुर से शुरू होकर २३ जुलाई को वहीं समाप्त होगी। २४ जुलाई को संत और अनुयायी फिर से लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में एकत्र होने वाले है। कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य ने सरकार पर भी सवाल उठाकर कहा कि गो-संरक्षण के लिए बजट बढ़ा रखा गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा कि संत समाज राजनीति नहीं करता, लेकिन जब शासक गलत दिशा में जाता है तो उसे सही मार्ग दिखाना संतों का कर्तव्य होता है। इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक नेता भी पहुंचे, जिनमें अजय राय और रविदास मेहरोत्रा सहित अन्य नेता शामिल थे।

हालांकि बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद के बावजूद कार्यक्रम में अपेक्षाकृत कम भीड़ दिखाई दी और पंडाल में कई कुर्सियां खाली रहीं।

बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जारी होगा टोल फ्री नंबर, मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी

रांची (एजेंसी): बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए विभाग उपभोक्ताओं की सुविधा को लेकर टोल फ्री नंबर जारी करने जा रहा है। ताकि गर्मी के मौसम में उन्हें परेशानी न हो। राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री देवेंद्र प्रसाद ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को सदन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डिवीजन कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों पर संज्ञान लिया जाएगा।

डुमरी विधायक जयराम महतो ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर बात उठाई थी। कहा कि राज्य के कई इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने या

बिजली के तार खराब होने के बाद लंबे समय तक बिजली बहाल नहीं हो पाती। इस वजह से आम लोगों को काफी परेशानी होती है।

उन्होंने सरकार पूछा कि ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अपनी शिकायत आखिर कहां दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि ट्रांसफार्मर जलने, तार टूटने या अन्य तकनीकी खराबी होने पर शिकायत किस अधिकारी या कार्यालय में करनी चाहिए। उधर सरकार के जल संसाधन मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा कि जल उनके विभाग में जो ५० सालों में नहीं हुआ, उसे मैं ५ साल में करके दिखाऊंगा।

सुरेश पासवान ने कहा, बजट काबिले तारिफ

देवघर विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि आज सिंचाई विभाग ने जो डैम बनाया, उस पर विपक्ष के लोग कुछ नहीं कहते हैं। त्रिकुट जलाशय योजना को भी बनाया जाना चाहिए।

पतरातू, चांडिल, मैथन, मसानजोर, स्वर्णरेखा डैम बने हैं। वहां मछली पालन से लोगों को रोजगार भी मिला। विपक्ष को नकारात्मक चीजें अधिक दिखती हैं। आज किसानों को राहत मिल रही है, पानी मिल रहा है। सरकार ने जो बजट पेश किया है, वह काबिले तारिफ है।

भूमि और विस्थापन पर गंभीरता से सोचने की जरूरत : मरांडी

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में जमीन को लेकर दो एक्ट है। यहां के लोगों के हाथों से जमीन चली जाने पर उन्हें पलायन करना पड़ता है।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर लोगों की जमीन ली जा रही हैं तो उन्हें कहीं और जमीन ही मिले। सरकार को भूमि और विस्थापन को लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए।

जामताड़ा में आत्मनिर्भरता की नई उड़ान, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से संवरेगा वंचितों का भविष्य

जामताड़ा (एजेंसी): जामताड़ा जिले से समाज के वंचित वर्गों के लिए एक राहत भरी और उत्साहजनक खबर सामने आई है। अब जिले के हरिजन, आदिवासी, दिव्यांग और विधवा महिलाएं अपनी आर्थिक तंगी को पीछे छोड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर होंगी।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत जिले में पशुपालन को स्वरोजगार का मुख्य जरिया बनाया जा रहा है। पशुपालन विभाग ने एक सराहनीय पहल करते हुए लक्षित समूहों को ९० प्रतिशत के भारी अनुदान पर बत्तख पालन से जोड़ने की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वह किसी पर निर्भर ना रहकर अपना गुजर-बसर स्वयं कर सकें। योजना के पहले चरण में जामताड़ा प्रखंड के ३० पशुधन मित्रों को ३०-३० यूनिट बत्तख के चूजे वितरित किए गए हैं।

प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि यह योजना लोगों को अपने पैरों पर खड़े करने की एक ठोस कोशिश है। विभाग ना केवल चूजे वितरित कर रहा है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और रखरखाव की भी पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। पशुधन मित्रों को प्रशिक्षित किया गया है, ताकि किसी भी बीमारी या समस्या की स्थिति में वे तुरंत विभाग से संपर्क कर सकें। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शिता है। लाभुकों का चयन सीधे ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है, जहाँ से प्रस्ताव पारित होकर विभाग तक पहुँचता है।

इससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ वास्तव में जरूरतमंद व्यक्ति तक ही पहुँचे। वहीं प्रशासन का लक्ष्य है कि जल्द ही इस योजना को पूरे जिले में व्यापक स्तर पर लागू किया जाए। बत्तख पालन के माध्यम से अब जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ना केवल पोषण के स्तर में सुधार होगा, बल्कि कम लागत में अच्छी खासी कमाई कर गरीब परिवार खुशहाली की ओर कदम बढ़ाएंगे।

सीएम हेमंत सोरेन से असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई की मुलाकात, चुनाव और विकास पर चर्चा

रांची (एजेंसी): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष-सह-लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आगामी असम चुनाव, झारखंड में चल रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह तथा झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू भी मौजूद थे। नेताओं ने आपसी सहयोग और राजनीतिक समन्वय को लेकर विचार-विमर्श किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से असम जातीय परिषद (-गझ) के अध्यक्ष लूरिनज्योति गोगोई ने भी मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच भी आगामी असम चुनाव और विभिन्न विकासात्मक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान असम जातीय परिषद के अन्य सदस्य एवं पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस बैठक को क्षेत्रीय राजनीतिक संवाद और आपसी सहयोग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विधानसभा के बजट सत्र में हफीजुल हसन का दावा, 50 साल का काम 5 साल में पूरा करेंगे

रांची (एजेंसी): झारखंड विधान सभा में जल संसाधन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मंत्री हफीजुल हसन ने सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए आगामी परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो काम पिछले ५० वर्षों में नहीं हो सका, उसे राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में पूरा करने का प्रयास करेगी।

मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत वीर शहीदों और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को नमन करते हुए की। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन का आधार है और जहां पानी की उपलब्धता होती है, वहीं विकास और समृद्धि के रास्ते खुलते हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है।

कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि केवल भाषण देने से काम नहीं

चलता, योजनाओं के लिए औपचारिक अनुशंसा और प्रस्ताव भी जरूरी होते हैं। उन्होंने भाजपा विधायकों के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार लंबित योजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने बताया कि बाल पहाड़ी गढे मेगा सिंचाई योजना से गिरिडीह, धनबाद और जामताड़ा जिलों के करीब ३७ हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा खूंटी जिले के अड़की और मुरहू प्रखंड के लिए चारा उल्हा पाइपलाइन सिंचाई योजना पर भी कार्य किया जाएगा।

सिमडेगा में हैपाला मेगा सिंचाई योजना और पूर्वी सिंहभूम में पटमदा-बोड़ाम मेगा सिंचाई योजना को भी आगे बढ़ाने की तैयारी है। वहीं सिकिया और मसलिया सिंचाई योजनाओं के पहले चरण का लगभग ९५ प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

वित्तीय व्यवस्था के मुद्दे पर मंत्री ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी अधिक होती थी, लेकिन अब राज्य सरकार को अधिक आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।

मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की समृद्धि और राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जल बचेगा तो कल सजेगा और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

झारखंड में कई सचिव निजी भवनों में अस्पताल चला रहे, जयराम महतो का आरोप

रांची (ईएमएस): झारखंड विधानसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुपूरक बजट पर तीखी बहस हुई। बहस के दौरान विधायक जयराम महतो ने स्वास्थ्य व्यवस्था को यूरोपीय देशों के स्तर पर सुधारने की बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता से बहुत दूर हैं, जबकि निजी अस्पतालों का कारोबार राज्य की तुलना में बढ़ा है। महतो ने आरोप लगाया कि कई सचिव निजी भवनों में अस्पताल चला रहे हैं। उन्होंने एनुअल हेल्थ चेकअप कानून की मांगकर बताया कि झारखंड में एक डॉक्टर ७,५०० लोगों के लिए है, जबकि आवश्यकता १,००० लोगों पर एक डॉक्टर की है। नर्सिंग सीटों में भी भारी कमी है और स्वास्थ्य पर राज्य का खर्च जीडीपी का केवल १ प्रतिशत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमलाल मुर्मु ने अनुपूरक बजट का समर्थन कर कहा कि अबुआ दवाखाना गरीबों के लिए राहत देगा। उन्होंने रिम्स-२ और प्रत्येक जिले में ओल्ड एज होम की आवश्यकता पर जोर दिया। प्राइवेट अस्पतालों पर नियंत्रण के लिए रेगुलेटरी कमेटी बनाने की मांग भी उठाई। विधायक अरूप चटर्जी ने १०८ एंबुलेंस सेवा में खामियों का मुद्दा उठाया, जबकि लुइस मरांडी ने सरकार की मांगों को जायज माना। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स-२ को अन्य स्थान पर बनाने का समर्थन किया और कहा कि लोग इलाज के लिए बड़ी दूरी तय कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर और नर्स की कमी, एयर एंबुलेंस की खराब स्थिति और लामुकों को घोती-साड़ी, दाल, नमक और चीनी वितरण में समस्याओं पर चिंता जाहिर की। विधानसभा में स्वास्थ्य और खाद्य वितरण में गंभीर कमी, प्राइवेट अस्पतालों का बढ़ता प्रभुत्व, सरकारी सुविधाओं में पारदर्शिता और नर्सिंग व डॉक्टर की भारी कमी को लेकर जोरदार बहस हुई। विधायक सुधार, निगरानी और बजट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा मिल सके।

गुरुग्राम हादसे में मृत श्रमिकों के परिजनों को मिले 20-20 लाख के चेक

रांची (एजेंसी): गुरुग्राम के सिधरावली गांव में सिग्नेचर ग्लोबल की निर्माणाधीन साइट पर मिट्टी ढहने से ९ मार्च को जान गंवाने वाले सातों श्रमिकों के परिजनों को कंपनी की ओर से २०-२० लाख रुपये के चेक गुरुवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में दिए गए। चेक रांची से सांसद व केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने प्रदान किए। इसके साथ ही सभी मृतकों के परिजनों को यात्रा खर्च के लिए २०-२० हजार रुपये की वित्तीय सहायता भी दी गई। झारखंड के ६ मजदूरों की मौत हुई थी। इन्हें भी चेक दिया गया।

जल्द ही हरियाणा सरकार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (बीओसी) कल्याण पंड से ४ लाख रुपये एवं वर्कमेन कंमनसेशन एक्ट के तहत १५ लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि भी दी जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक परिवार को कुल मिलाकर लगभग ४० लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकेगी। सभी के परिवार से एक-एक व्यक्ति को कंमनी में नौकरी भी दी जाएगी। बताया जाता है कि इतनी सहायता राशि अब तक इस तरह के मामले में पहले कभी नहीं दी गई।

बता दें कि ९ मार्च की रात सिग्नेक ग्लोबल की निर्माणाधीन साइट पर कई श्रमिक काम कर रहे थे। अचानक मिट्टी ढहने से १० से अधिक श्रमिक दब गए थे। उनमें से झारखंड निवासी शिवशंकर, परमेश्वर महतो, मंगल महतो, भागीरथ गोप, संजीव गोप, धनंजय गोप एवं राजस्थान निवासी सतीश की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से न केवल बातचीत की, बल्कि श्रमिकों के परिजन से मिलने व उनकी सहायता करने के लिए जमशेदपुर से सांसद बिचूतू बरण महतो के साथ बुधवार शाम गुरुग्राम पहुंचे।

पृष्ठ एक का शेषांश

एलपीजी संकट पर---

के दौर का उदाहरण देकर कहा कि तब १४० करोड़ भारतीयों ने देश की मजबूती दिखाई थी और अब भी हम इस संकट से जल्द ही उबर जाने वाले है। उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करना है और किसी भी तरह के पैनिक की जरूरत नहीं है। जनता से अपील की गई है कि केवल सत्यापित सूचना को साझा करें और अफवाहों को आगे न बढ़ाएं। इस तरह, प्रशासन और केंद्र सरकार मिलकर एलपीजी संकट को नियंत्रित करने और लोगों को सही जानकारी देने में सक्रिय हैं।

सीईसी ज्ञानेश कुमार को---

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सात आरोप लगाए गए हैं। इनमें पद पर रहते हुए पक्षपाती और भेदभावपूर्ण आचरण से लेकर चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालने और बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने जैसे आरोप शामिल हैं। विपक्ष दल कई बार मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगा चुके हैं कि वह सत्तारूढ़ भाजपा की मदद करते हैं, खासकर जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में। इसके बारे में उनका आरोप है कि इसका मकसद भाजपा की मदद करना है।

बुजुर्ग बना हैवान---

इसके बाद गुस्से में आरोपी ने अपनी पत्नी और बहू पर हथौड़ा से हमला करके उन्हें मार डाला। फिर उसने अपनी ४ साल की पोती को भी मार डाला। तीनों की हत्या करने के बाद वह भाग गया। आरोपी का बेटा जब घर लौटा तो उसने कुंदेश्गोला पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आरोपी फरार है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लोकसभा में एलपीजी गैस---

करे कि भारत रूस से तेल या गैस खरीद सकता है या नहीं, तो यह स्थिति समझ से परे है। इसी दौरान उन्होंने एक अन्य विवादित मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि तेल मंत्री खुद किसी समय एपस्टीन को अपना दोस्त बता चुके हैं। इस टिप्पणी के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया।

हंगामा देख स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए राहुल गांधी से कहा कि वे केवल उसी विषय पर बोलें, जिसके लिए उन्होंने नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करनी है तो उसके लिए अलग से नोटिस देना होगा। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी।

हंगामे के बीच स्पीकर ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को जवाब देने के लिए आमंत्रित किया। पुरी ने कहा कि देश में एलपीजी, पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है और विपक्ष अनावश्यक रूप से माहौल बना रहा है। उन्होंने बताया कि भारत के पास पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार है और कई स्रोतों से ईंधन की आपूर्ति जारी है। पुरी ने कहा कि भारत को कनाडा, नॉर्वे और रूस से ईंधन मिल रहा है। इसके अलावा एलपीजी उत्पादन में करीब २८ प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि वैकल्पिक ईंधन चैनलों को सक्रिय कर दिया गया है और देशभर में सीएनजी की आपूर्ति भी सामान्य रूप से जारी है।

मंत्री ने कहा कि घबराहट के कारण लोगों ने ज्यादा बुकिंग कर दी है, जिससे मांग अचानक बढ़ गई है। सरकार ने स्थिति पर नजर रखने के लिए तीन मंत्रियों की एक समिति भी बनाई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

वहीं स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद नियमों के अनुसार ही चलेगी और बिना नोटिस के किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं है, सभी को नियमों का पालन करना होगा। हंगामे के बीच स्पीकर कुछ समय के लिए चेयर छोड़कर चले गए, जिसके बाद जगदंबिका पाल ने कार्यवाही संभाली। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे। पाल ने सांसदों से अपना स्थान ग्रहण करने की अपील की, लेकिन सदन का माहौल लंबे समय तक तनावपूर्ण बना रहा।

ग्रामीण इलाकों में अब---

उपभोक्ता अपने मोबाइल पर आए वन-टाइम कोड से इसकी पुष्टि करेगा। इससे गैस की गलत तरीके से सप्लाई या हेरफेर को रोकना आसान होगा। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बताया कि आज से तेल कंपनियां कमर्शियल एलपीजी की औसत मंथली डिमांड का २० प्रतिशत हिस्सा आवंटित करेंगी ताकि जमाखोरी और काला बाजारी न हो। पुरी ने कहा कि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को नियंत्रित करने का मकसद काला बाजारी को रोकना है, न कि होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को नुकसान पहुंचाना। कमर्शियल एलपीजी बिना सब्सिडी के बेची जाती है। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन या बुकिंग नहीं होती। अगर कमर्शियल एलपीजी की बिक्री खुली की छूट दी गई तो सिलेंडरों की अवैध बिक्री का खतरा होगा।

रांची नगर निगम की सख्ती, नियम उल्लंघन पर तीन दुकानें सील

रांची (एजेंसी): रांची में नियमों के पालन और नगर निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा को लेकर रांची नगर निगम ने सख्ती तेज कर दी है। इसे लेकर शहर में लगातार जांच अभियान चलाते हुए कई जगहों पर कार्रवाई की गई। इसी क्रम में स्वीकृत भवन प्लान के उल्लंघन के मामले में बरियातू रोड स्थित संत तुलसी अपार्टमेंट में संचालित तीन दुकानों को सील कर दिया गया। निगम प्रशासन के अनुसार इन दुकानों के ट्रेड लाइसेंस पहले ही रद्द कर दिए गए थे। इसके बावजूद संचालन जारी रहने पर १२ मार्च को कार्रवाई करते हुए केके मेगा मार्ट के संचालक कमल किंगर, टूंडी शू की संचालक स्नेहा कुमारी तथा टाइल्स मार्ट के संचालक आयुष भूषण की दुकानों को सील कर दिया गया। आरोप है कि ये दुकानें स्वीकृत भवन प्लान के विपरीत गैलरी क्षेत्र में संचालित की जा रही थीं।

निगम ने अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन को लेकर भी विशेष अभियान चलाया। भू-संपदा कोषांग के सहायक प्रशासक राहुल यादव के नेतृत्व में निगम की टीम ने वार्ड संख्या १८ से ३६ तक करीब १५ निगम स्वामित्व वाले भवनों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई स्थानों पर अवैध कब्जे पाए गए, जिन पर तत्काल कार्रवाई की गई। वहीं वार्ड २९ में खादगढ़ा शनि मंदिर के पास स्थित सामुदायिक भवन में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से डांस क्लास संचालित किया जा रहा था।

जामताड़ा के कटंगी गांव में पानी के लिए परेशान हैं ग्रामीण, 5 महीनों से बंद पड़ा सोलर वाटर प्लांट

जामताड़ा (एजेंसी): डिजिटल इंडिया के इस दौर में भी जामताड़ा प्रखंड का कटंगी गांव जल संकट की तस्वीर पेश कर रहा है। जिला समाहरणालय से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में करीब ४०० की आबादी आज भी दूषित पानी पीने को विवश है। विडंबना यह है कि जिस समाहरणालय में जिले के उपायुक्त उऊ समेत तमाम आला अधिकारी बैठते हैं, वहां से चंद कदमों की दूरी पर ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।

गांव की कुल आबादी के लिए कहने को तो आठ चापाकल हैं, लेकिन इनमें से पांच लंबे समय से खराब पड़े हैं। ग्रामीणों के लिए राहत की

एकमात्र उम्मीद यहां लगा 'सोलर वाटर प्लांट' था, जो पिछले ५ महीनों से बंद पड़ा है। ग्रामीणों के अनुसार, जब यह प्लांट चालू था, तब ५०-६० घरों को शुद्ध पेयजल मिल पा रहा था, लेकिन अब यह हाथी का दांत साबित हो रहा है।

पानी की किल्लत का सबसे ज्यादा असर गांव की महिलाओं पर पड़ रहा है, जिन्हें दैनिक कार्यों और पीने के पानी के लिए करीब १ किलोमीटर दूर नदी या तालाब तक जाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार विभाग से इसकी शिकायत की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। थक-हारकर ग्रामीण कभी-कभी चंदा इकट्ठा कर चापाकल की मरम्मत खुद करवाते हैं, पर वह बार-बार खराब हो जाते हैं।

भीषण गर्मी की आहट के साथ ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार और संबंधित विभाग जल्द समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस मामले में जब संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

व्हाइट ब्रेड और पास्ताड बना सकते हैं अवसाद का शिकार

अगर आप अधिकतर समय व्हाइट ब्रेड और पास्ताह खाते हैं तो इसे बंद कर दें यह आपको बीमार बना सकता है। खानपान का भी सेहत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ब्रेड और पास्ता कभी कभी-कभी खाने में कोई खतरा नहीं है पर अगर आप अक्स र नाश्तेल में ब्रेड या पास्ताय ही खाते हैं तो यह आपके लिए चिंता का कारण हो सकता है। एक हालिया अध्य यन में यह दावा किया गया है कि व्हा इट ब्रेड और पास्तार का सेवन अवसाद का शि ?कार बना सकता है।

अध्यदयन रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि व्हाइट ब्रेड और पास्ता में पाये जाने वाले कार्बोहाइड्रेट आपके भीतर चिड़चिड़ापन और चिंता बढ़ा सकते हैं।

एक अध्ययन के अनुसार सफेद ब्रेड, चावल और पास्ता जैसी खाने की चीजें आपको अवसाद का शिकार बना सकती हैं। वहीं इस खतरे को अनाज और हरी सब्जियां कम कर सकती हैं। सफेद ब्रेड और सफेद चावल खाने से शरीर में हार्मोनल प्रतिक्रिया होती है जो ब्लड शुगर लेवल को घटाती है जिसके कारण चिड़चिड़ापन, थकान और डिप्रेशन के कई लक्षण लोगों में आने लगते हैं।

शोध के मुताबिक ब्रिटेन में प्रति 100 में से 3 लोग अवसाद के शिकार हैं जो कि सफेद ब्रेड और पास्ता जैसे बुरे कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से भी होते हैं। इन बुरे कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से मोटापा, थकान और अनिद्रा जैसी बीमारियों के खतरे बढ़ सकते हैं।

कॉफी पीने से दिल की बिमारियों का खतरा होता है कम

अगर आप कॉफी पीते हैं तो आपको दिल की बिमारियों का खतरा कम होता है। एक अध्ययन रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि दिन में चार कप कॉफी पीने से दिल की बीमारियों की वजह से होने वाली मौत का खतरा दो तिहाई कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन 20,000 लोगों पर किया है.

शोधकताओं ने अध्ययन के दौरान पाया कि कॉफी पीने से शरीर की प्रतिरोधकत क्षमता बढ़ती है। यह दिल की सेहत के लिए अच्छा है और कैंसर से बचाव करती है।

शोधकर्ता ने कहा कि लोगों को खूब कॉफी पीनी चाहिए। इससे उनका दिल सेहतमंद रहेगा और कैंसर का खतरा भी कम होगा।

यह अध्ययन 20,000 लोगों पर 10 साल तक किया गया। इसके अलावा पिछले महीने 5,20,000 लोगों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि कॉफी लीवर की सेहत सुधारने में भी कारगर है।

कॉफी में दरअसल, कई तरह के यौगिक पाए जाते हैं, जो शरीर के संपर्क में आते ही एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करने लगते हैं हालांकि शोधकर्ताओं ने बहुत ज्यादा कॉफी पीने से भी मना किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार दिन में अध?कतम 4 कप कॉफी काफी है। इससे ज्यादा कॉफी पीने से नुकसान पहुंच सकता है।

यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी की सलाह मानें तो रोजाना किसी भी व्यक्तिय को 0.4 ग्राम से ज्यादा कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि आप अगर एस्प्रेस्सो कॉफी पीते हैं तो दिन में 5 कप और अगर इंस्टैंट कॉफी पीते हैं तो 4 कप से ज्यादा कॉफी ना पीयें।

हम अपने डाइट में पौष्टिक और फाइबर वाली चीजों की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो इससे न सिर्फ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। साथ ही कई बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेहत के लिए कौन सा आटा सबसे अच्छा माना जाता है।

कटहल का आटा है हेल्थ का खजाना

अच्छी सेहत के लिए सही खानपान और लाइफस्टाइल में सुधार सबसे जरूरी माना जाता है। क्योंकि जैसी लाइफस्टाइल है और जो भी हम खाते हैं, उसका हमारी सेहत पर सीधा असर होता है। यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट सभी लोगों को अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखने की सलाह देते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक आजकल लोग मैदा, प्रोसेस्ड फूड, नमक और चीनी वाली चीजों का अधिक सेवन करते हैं। जिस कारण डायबिटीज, हाई बीपी, मोटापा और हृदय रोगों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।

असंतुलित डाइट और फिजिकल एक्टिविटी की कमी दुनियाभर में होने वाली क्रॉनिक बीमारियों की वजह है। ऐसे में अगर हम अपने डाइट में पौष्टिक और फाइबर वाली चीजों की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो इससे न सिर्फ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। साथ ही कई बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेहत के लिए कौन सा आटा सबसे अच्छा माना जाता है।

सेहत के लिए कौन सा आटा अच्छा

भारत में गेहूं और इसका आटा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला अनाज है। इसमें फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साबुत गेंहू का आटा पाचन को बेहतर बनाता है और ऊर्जा देने में मदद करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में अन्य तरह के आटे की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। जिसको अध्ययनों में कई प्रकार से लाभकारी पाया गया है।

आजकल पारंपरिक गेहूं के आटे के साथ हरे कटहल के आटे और क्विनोआ के आटे का भी लोग काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। यह दोनों ऑप्शन पोषक तत्वों से भरपूर हैं। यह खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो ब्लड शुगर, पाचन या वजन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

सेहत के लिए लाभकारी क्विनोआ का आटा

क्विनोआ एक स्वास्थ्यवर्धन बीज है, जोकि कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इस कारण इसको सुपरफूड माना जाता है। क्विनोआ में फाइबर, आयरन, अमीनो एसिड, मैग्नीशियम, मैगनीज, प्रोटीन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, फोलेट और विटामिन-बी होता है।

क्विनोआ में मौजूद अमीनो एसिड मांसपेशियों की मरम्मत करता है और इसके विकास में अहम भूमिका निभाता है। क्विनोआ में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जोकि पेट को लंबे समय तक भरा महसूस कराता है। जिससे आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं।

हरे कटहल का आटा

मधुमेह रोगियों में प्लाज्मा शर्करा के लेवल को कम करने और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को कंट्रोल करने में कटहल का आटा काफी कारगर माना गया है। बता दें कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ना डायबिटीज का संकेत माना जाता है। साथ ही इसको फैटी लीवर और मोटापे को रोकने में भी कारगर बताया गया था।

जानिए ये फायदे

इसमें पोटैशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। जोकि बीपी को कंट्रोल करने के साथ बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है।

क्विनोआ में मौजूद मैग्नीशियम, विटामिन बी, आयरन और फॉस्फोरस एनीमिया को रोकने में मदद करते हैं। हालांकि क्विनोआ के अधिक सेवन से गैस, पेट दर्द, ब्लोटिंग या डायरिया हो सकती है। वहीं जिनको हाई बीपी, किडनी स्टोन या एलर्जी की समस्या है, उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

लिवर और शुगर दोनों के लिए फायदेमंद

चूहों पर किए गए शोध में पता चलता है कि सिर्फ तीन महीने हरे कटहल के आटे के सेवन से न सिर्फ शरीर के वजन में वृद्धि को काफी हद तक रोका जा सकता है। बल्कि यह लिवर में फैट जमने समस्या को भी कम करने में कारगर है।

महिलाओं के लिए काले या सफेद तिल, जानें हेल्थ के लिए क्या है बेहतर

सर्दियों के मौसम में महिलाओं के शरीर को पोषण, ज्यादा गर्माहट और खास देखभाल की जरूरत होती है। आयरन कैल्शियम की कमी, हार्मोनल बदलाव, जोड़ों की समस्या और थकान इस मौसम में महिलाओं को अधिक प्रभावित करती है। ऐसे में तिल जैसे छोटे-से दिखने वाले बीज सर्दियों में महिलाओं के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं होते हैं। लेकिन अक्सर महिलाओं के मन में यह सवाल रहता है कि काले तिल और सफेद दोनों तिलों में से ज्यादा फायदेमंद कौन है।

बता दें कि दोनों ही तिल महिलाओं की सेहत, सुंदरता और ऊर्जा के लिए फायदेमंद है। बस इन दोनों तिलों के फायदे अलग-अलग हैं। यह सही चुनाव, लाइफस्टाइल, शरीर की जरूरतों और उम्र पर निर्भर करता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको सफेद और काले दोनों तिलों के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं।

काले तिल के फायदे

काले तिल में मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से महिलाओं को कई तरह के फायदे हो सकते हैं।

काले तिल हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मददगार होते हैं।

यह बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करने के साथ हेयर फॉल को कम करते हैं।

काले तिल के सेवन से शरीर में एनर्जी और गर्माहट को बढ़ाते हैं।

थकान, आयरन की कमी या पीसीओ से जुड़ी समस्याएं में काले तिल खास लाभकारी होते हैं।

काले तिल बिना छिले होते हैं, इसलिए इनमें मिनरल्स की मात्रा थोड़ी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं।

सफेद तिल के फायदे

बता दें कि सफेद तिल में हेल्दी फैट्स, कैल्शियम और हड्डियों को मजबूत करने वाले मिनरल्स का का अच्छा स्त्रोत पाया जाता है। सफेद तिल को खाने से शरीर को इसके कई फायदे मिलते हैं।

सफेद तिल हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं।

महिलाओं की ओवलऑल हेल्थ के लिए सफेद तिल फायदेमंद होते हैं।

यह स्किन की नमी और जोड़ों की सेहत में भी सुधार करते हैं।

बच्चों, बुजुर्गों और कैल्शियम की कमी वाले लोगों को अपनी डाइट में सफेद तिल शामिल करना चाहिए।

आप सफेद तिल को लड्डू, चटनी और सलाद के रूप में आसानी से डाइट में शामिल कर सकते हैं।

कौन से तिल चुनें काले या सफेद

काले और सफेद दोनों ही तिल सेहत के लिए फायदेमंद हैं, तो डाइट में किसे शामिल करना चाहिए। ऐसे में आपके शरीर की जरूरतों और सेहत से जुड़ी समस्याओं पर यह निर्भर करता है कि आपको कौन से तिल अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। क्योंकि हर तिल का अपना अलग पोषण और फायदा होता है। इसलिए सही चुनाव करना जरूरी है।

शरीर में आयरन की कमी, लगातार थकान महसूस होना और बालों का झड़ना आदि की समस्या होने पर आपको अपनी डाइट में काले तिल शामिल करना चाहिए। काले तिल आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंस से भरपूर होते हैं। ऐसे में इनका सेवन करने से खून की कमी दूर होती है और एनर्जी बढ़ती है।

वहीं हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी और महिलाओं की सेहत के लिए सफेद तिल फायदेमंद होती है। इनमें कैल्शियम और हेल्दी फैट्स का अच्छा स्त्रोत पाया जाता है, जोकि हड्डियों को मजबूत बनाने और जोड़ों की सेहत को सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा संतुलित पोषण, स्वास्थ्य और सर्दियों में गर्माहट के लिए आपको अपनी डाइट में सफेद और काले दोनों तिल शामिल करना चाहिए।

नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास है अन्य मंदिरों से अलग

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से लगभग 11-13 किमी दूर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर को इच्छापूर्ति महादेव कहा जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला और इतिहास दोनों ही बाकी मंदिरों से काफी अलग हैं। ऐसा लगता है कि मंदिर का भार एक मेंढक ने अपनी पीठ पर ले रखा है और बीचोबीच महादेव का शिवलिंग स्थापित है। मेंढक की पीठ पर आठ कमल की पंखुड़ियों जैसा आकार भी देखा गया है। देखने पर ऐसा लगता है कि महादेव मेंढक की पीठ पर कमर की पंखुड़ियों के बीच स्थित है। मंदिर के चारों कोनों पर प्रावीन स्तंभ भी मौजूद हैं, जो शैव तंत्र का प्रमाण देते हैं।

माना जाता है कि नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के तार तंत्र से जुड़े हैं और यही कारण है कि भगवान शिव मेंढक की पीठ पर हैं। सामान्य भाषा में इसे मंडूक तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। धन और समृद्धि को आकर्षित करने, साधना और तंत्र कार्यों में सहायक और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मंडूक तंत्र का इस्तेमाल होता है और यह देश का पहला मंदिर है, जो मंडूक तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर का निर्माण ओयल स्टेट के राजा बख्श सिंह ने कराया था, जिसे शैव संप्रदाय का प्रमुख तंत्र का केंद्र माना गया। मंदिर को बनाने का उद्देश्य तंत्र के साथ-साथ राज्य को बाढ़ और सूखे से भी बचाना था। मंदिर की भीतरी वास्तुकला भी चौंका देती है, जहां मंदिर के भीतर बनी भूलभुलैया आज भी रहस्य बनी हुई है। किसी को नहीं पता कि भूलभुलैया का रास्ता कहां जाता है। मंदिर की स्थापना को लेकर कई किंवदंती मौजूद हैं। माना जाता है कि राज्य को सूखे की मार से बचाने के लिए ओयल स्टेट के राजा बख्श सिंह ने

एक तांत्रिक के कहने पर मंडूक तंत्र का सहारा लिया था और राज्य में भारी बारिश की कारवाई थी। तभी से ये मंदिर तंत्र सिद्धि के लिए मशहूर है। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग और नंदी महाराज की प्रतिमा भी चमत्कारी है। स्थानीय मान्यता की मानें तो शिवलिंग दिन में तीन बार रंग बदलता है और नंदी महाराज की प्रतिमा अपने चारों पैरों पर खड़ी है।

बीसीए के बाद अच्छी जॉब के लिए बेहतरीन करियर ऑप्शंस

बीसीए, एक पॉपुलर अंडरग्रेजुएट कोर्स है, जिसे कंप्यूटर साइंस और आईटी फील्ड में करियर बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, इस कोर्स को करने के बाद, आगे क्या करें सोच कर आप भी परेशान चल रहे हैं, तो चलिए हम आपको यहां बीसीए के बाद के कुछ बेहतरीन करियर ऑप्शंस के बारे में बताते हैं।

अगर आपने अंडरग्रेजुएट कोर्स बीसीए कर लिया है और अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले ही, अक्सर स्टूडेंट्स बीसीए के बाद क्या करें? इस सवाल को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको इतना सोचने की जरूरत अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बीसीए के बाद आपके पास करियर के कई बेहतरीन विकल्प होते है, जिनमे उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरिया और प्राइवेट सेक्टर मे हाई-सैलरी जॉब्स शामिल हैं। सही करियर ऑप्शन का चुनाव आप अपने स्किल्स, इंटरेस्ट और करियर गोल्स के आधार पर कर सकते हैं।

इसी क्रम में आइए हम आपकी दुविधा को दूर करते हैं। दरअसल, इस आर्टिकल में हम आपको बीसीए के बाद मिलने वाले टॉप करियर ऑप्शंस के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप अपने फ्यूचर के लिए सही फैसला ले सके और आगे जाकर आप एक अच्छी जॉब व हाई सैलरी पा सकें। बीसीए के बाद बेहतरीन करियर ऑप्शंस -

MCA (Master of Computer Applications)

अगर आप अपनी तकनीकी स्किल्स को और मजबूत करना चाहते हैं, तो MCA करना एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह कोर्स आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे एडवांस्ड टॉपिक्स सिखाता है। रही बात इस कोर्स के बाद जॉब ऑप्शंस की तो आप इससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, आईटी कंसल्टेंट आदि बन सकते हैं। इसमें आपको लगभग रू 5-12 लाख प्रति वर्ष का पैकेज भी मिल सकता है।

MBA (Master of Business Administration)

अगर आप मैनेजमेंट और लीडरशिप में करियर बनाना चाहते है, तो स्क्ष्ठ आपके लिए सही रहेगा। खासकर IT Management, Business Analytics और Digital Marketing में MBA करने से आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी जॉब मिल सकती है। इस जॉब में आपको शुरुआत में कम से कम रू 6-15 लाख प्रति वर्ष का पैकेज मिल सकता है।

डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में बनाएं करियर

बीसीए के बाद डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में करियर बनाना आज के समय में बहुत अच्छा विकल्प है। इस फील्ड में जॉब्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और सैलरी भी काफी अच्छी है। बीसीए करने के बाद, आप डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग डेवलपर आदि बन सकते हैं। बात अगर सैलरी पैकेज की करें तो आपको रू 8-20 लाख प्रति वर्ष का पैकेज मिल सकता है।

डिजिटल मार्केटिंग और SEO में हाथ आजमाएं

अगर आपको क्रिएटिविटी और मार्केटिंग में रुचि है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है, जो आप बीसीए करने के बाद आराम से कर सकते है। कंपनियां अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटर्स को हायर कर रही हैं। ऐसे में, आपको डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, SEO एक्सपर्ट, कंटेंट मार्केटर की पोस्ट मिल सकती है। साथ ही, रू 4-12 लाख प्रति वर्ष का पैकेज मिल सकता है।

ये हैं दुनिया की 5 सबसे कठिन डिग्रियां

अगर आप अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और शानदार कमाई करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल में बताए गई कठिन डिग्रियों में से किसी एक को चुन सकते हैं। हालांकि, इन डिग्रियों को हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और लगन से इन्हें पूरा करके आप अपने भविष्य को सुरक्षित और शानदार बना सकते हैं। अगर आप करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहते है और अच्छी कमाई का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए सही डिग्री चुनना बेहद जरूरी है। दुनिया में कई डिग्रियां ऐसी हैं, जिन्हे पूरा करना आसान नहीं होता है, लेकिन एक बार हासिल करने के बाद इनका स्कोप और सैलरी पैकेज जबरदस्त मिलता है। कठिनाई के बावजूद, इन डिग्रियों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो आइए दुनिया की 10 सबसे कठिन डिग्रियों के बारे में जानते हैं, जिन्हे पाकर आप लाखों की कमाई कर सकते हैं।

बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी

अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो MBBS दुनिया की सबसे कठिन डिग्रियों में से एक मानी जाती है। इसमें लंबे समय तक पढ़ाई, इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है। लेकिन इस फील्ड में करियर बना लिया, तो कमाई की कोई सीमा नहीं होती।

इंजीनियरिंग

इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स काफी कठिन होता है, खासकर तब जब आप टॉप ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हों। इसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप का कॉम्बिनेशन होता है, जो इसे और भी चैलेंजिंग बना देता है।

चार्टर्ड अकाउंटेंसी

CA कोर्स दुनिया के सबसे कठिन कोर्सों में से एक है। इसमें कई स्तर के एग्जाम होते हैं और पास करने की दर भी काफी कम होती है। लेकिन अगर आप इसे पूरा कर लेते हैं, तो बड़े कॉरपोरेट हाउस में लाखों-करोड़ों के पैकेज पर जॉब पा सकते है या खुद की फर्म शुरू कर सकते हैं।

एस्ट्रोनॉमी और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग

अगर आपको अंतरिक्ष और विमानन विज्ञान में रुचि है, तो यह डिग्री आपके लिए है। लेकिन यह बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि इसमें गणित, भौतिकी और तकनीकी ज्ञान की गहरी समझ जरूरी होती है। नासा, इसरो जैसी एजेंसियों में काम करने का सपना देखने वालों के लिए यह एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है।

लॉ के बाद जज बनने और वकालत करने के अलावा भी हैं ढेर सारे विकल्प

लॉ में करियर लंबे समय से युवाओं के बीच पॉपुलर रहा है और अब इसमें विकल्पों के बढ़ने आपके लिए मनमाफिक विकल्प चुनना भी आसान हो गया है। दरअसल कानूनी पेचिदगियों और समाज के विस्तार के चलते कानून के जानकार प्रोफेशनल्स की जरूरत हर जगह बढ़ गई है। आज के समय में आम लोगों अपने अधिकारों के प्रति काफी जागरूक है, वे कानूनी प्रक्रियाओं को समझना चाहते हैं, ऐसे में लॉ में करियर बनाने वालों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही हर दिन किसी नई खोज या तकनीकी विकास के चलते पुराने और प्रचलित कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होती है। और इस लिहाज से भी कानून के जानकारों की माग में में इजाफा हुआ है।

लॉ का ये है पाठ्यक्रम

लॉ से सम्बंधित 2 पाठ्यक्रम होते हैं पहला, 10+2 के बाद पांच वर्षीय इंटिग्रेटेड लॉ पाठ्यक्रम और ग्रेजुएशन के बाद तीन वर्षीय लॉ पाठ्यक्रम। पांच वर्षीय इंटिग्रेटेड लॉ पाठ्यक्रमों में भी अब पाँच प्रकार के पाठ्यक्रम हो गए है - आर्ट्स के छात्रों के लिए बीए एलएलबी, साइंस के छात्रों के लिए बीएससी एलएलबी, कॉमर्स के छात्रों के लिए बीकॉम एलएलबी, कंप्यूटर साइंस के छात्रों के लिए बीसीए एलएलबी और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए बीबीए एलएलबी। उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आपको क्लेट यानि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट से गुजरना होगा, जो वर्ष में एक बार होता है। आपकी रैंकिंग के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट किए जायेंगे। देश में कई ऐसे सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जहाँ केवल लॉ की ही पढ़ाई होती है। ग्रेजुएशन के बाद के लॉ पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए विश्वविद्यालय अपना-अपना एंट्रेंस टेस्ट संचालित करते हैं।

इस तरह बनें लायर

वह समय खत्म हो गया, जब आप लॉ की परीक्षा पास कर काला कोट पहन कर सीधे वकालत में सकते है। लॉ के बाद आपको बार काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित आल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानि एआईबीई देना होगा, जिसके बाद ही आप वकालत के लिए योग्य घोषित कर दी जाएंगी। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन बार काउन्सिल ऑफ इंडिया मे हो जायेगा और तब आप वकील के तौर पर काम करने की योग्यता प्राप्त कर लेगीं।

एकेडमिक्स में जाएं

यदि आपका ध्येय केवल एक वकील की तरह भारत के किसी भी न्यायलय मे वकालत को अपना करियर बनाना है, तो इसमें एलएलएम (लॉ में पोस्ट ग्रैजुएट) की कोई भूमिका नहीं है। इसके लिए आपको एलएलबी की डिग्री ही पर्याप्त है। एलएलएम और पीएचडी मुख्य रूप से वे महिलाएं करती हैं, जो लॉ के क्षेत्र में एकाडेमिक्स में जाना चाहती हैं और आगे चलकर किसी लॉ कॉलेज में एक लेक्चरर के रूप में अपना करियर बनाना चाहती हैं। अगर आप किसी कानून विशेष में स्पेशलाइजेशन करना चाहती है, तो पीजी और पीजी डिप्लोमा स्तर पर स्पेशलाइजेशन के लिए कई विकल्प उपलब्ध है।

एनवायरमेंटल लॉयर

अगर आप प्रकृति के संरक्षण के बारे में गंभीरता से सोचती हैं तो एन्वायरमेंटल लॉयर बनने के बारे मे सोच सकती हैं। इसके जरिए आप प्राकृतिक संपदा के नष्ट होने से जुड़ी चीजों को बचाने की बात कह सकती है। इसके तहत आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी डाल सकती है। इसके अलावा एन्वायरमेंटल लॉयर्स की जरूरत एनजीओज में भी होती है, जो प्रकृति को होने वाले नुकसान पर आवाज उठाते हैं।

साइबर लॉयर

टेक्निकल एडवांसमेंट के दौर में साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं और इन पर काबू पाने के लिए साइबर लॉयर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। खासतौर पर फर्जी ई-मेल भेजना, सोशल अकाउंट हैक करना, कंपनियों के साथ फ्रॉड, खातों से फर्जी तरीके से पैसे निकालना, एसएमएस हैकिंग, मोबाइल क्लोनिंग जैसे मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए कंप्यूटर और नेटवर्क सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसे देखते हुए आप कंप्यूटर एंड डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने के बारे में भी सोच सकती हैं।

पेटेंट एंड कॉपीराइट लॉयर

कई बार लोग अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति की खोज को अपना नाम दे देते है, इससे सुरक्षा देता है पेटेंट एंड कॉपीराइट लॉ। कानूनी तौर पर अगर कोई थर्ड पार्टी मूल प्रॉडक्ट को बनाना चाहती है, तो उसे इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत होती है और उस पर रॉयल्टी शुल्क देना पड़ता है। बौद्धिक संपदा यानी Intellectual Property बिजनेस के उभरते हुए क्षेत्रों में से एक है और इसमें यंग प्रोफेशनल्स की अच्छी खासी मांग है।

लेबर लॉयर

कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकार लेबर लॉ के तहत आते हैं। अक्सर कंपनियों में काम कर रहे इंप्लॉई अपने अधिकार और अन्य विवादों को लेकर अदालत में पहुंच जाते हैं। लेबर लॉ से जुड़े मामलों में इजाफा होने की वजह से इसमें भी आपके लिए आपके लिए अच्छी संभावनाएं हो सकती है।

इंटरनेशनल लॉयर

अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है और आपकी अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में रुचि है तो आप इंटरनेशनल लॉयर बनने के बारे में भी सोच सकती हैं। इसके तहत विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों से जुड़ी समस्याओं का कानूनी तरीके से हल निकाला जाता है।

कॉरपोरेट लॉयर

देश में कंपनियों के बढ़ते प्रसार के बीच आजकल कॉरपोरेट लॉ का स्कोप भी काफी अच्छा है। इसके तहत कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स अपने यहां रखती है, जो उन्हें अपनी कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सलाह दे सकें। कॉरपोरेट लॉयर्स के तौर पर अच्छा तजुर्बा हासिल होने पर अच्छा पे-पैकेज भी मिलता है।

ये हैं जरूरी गुण

- बेहतर संवाद क्षमता
- अच्छी मेमोरी
- हाजिरजवाब
- तार्किक और चीजों का विश्लेषण करने में निपुण
- धैर्यवान होने का गुण
- समस्याओं के अनूठे हल निकालने में सक्षम
- कानूनी पहलुओं की अच्छी जानकारी
- समर्पण और कड़ी मेहनत

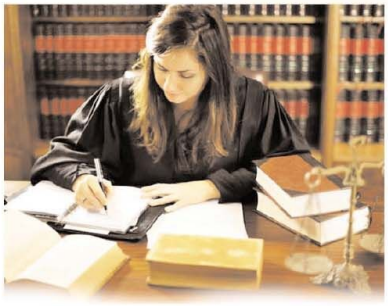

यदि आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से सामने वाले के सामने रख सकते हैं और जिसे भारत के कानून के बारे में नई-नई बात जानने की उत्सुकता बनी रहती है, आपके मन में अक्सर किसी व्यवस्था को लेकर उदगार पैदा होते हैं और आप समझते हैं कि यदि आपके हाथ में कानून होता तो इसे ठीक करने की कोशिश करते , तो फिर लॉ का क्षेत्र आपके लिए ही है। अगर आप लॉ के बाद इसमें करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि इसमें काफी अच्छी संभावनाएं हैं।

संक्षिप्त समाचार

ईरान को धमकी, कहा- अमेरिकी मांगों को नहीं माना तो नए सुप्रीम लीडर का होगा खात्मा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई

को लेकर बड़ा बयान दिया है। 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने कहा है कि अगर मुजतबा अमेरिकी मांगों को नहीं मानते, तो वह उनकी हत्या का समर्थन करेंगे। अमेरिका की मांग यह है कि ईरान अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर दे। अगर मुजतबा ने इससे इनकार किया, तो ट्रंप नए लीडर को खत्म करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस काम को इस्राइली सेना अंजाम दे सकती है। यह ठीक वैसा ही होगा जैसा 28 फरवरी को मुजतबा के पिता अली खामेनेई के साथ हुआ था। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह ईरान के इस चुनाव से बिल्कुल खुश नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मुजतबा खामेनेई अब शांति से नहीं रह पाएंगे। ट्रंप का मानना है कि ईरान के अगले नेता को चुनने में अमेरिका की भी राय होनी चाहिए। उन्होंने इसकी तुलना वेनेजुएला में अमेरिकी दखल से की। 'न्यूयॉर्क पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, दिवंगत नेता अली खामेनेई ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि उनका बेटा उनका उत्तराधिकारी न बने। इसके बावजूद, ईरान की ताकतवर सेना (आईआरजीसी) ने मुजतबा को इस पद पर बैठा दिया। जानकारों का कहना है कि खुद अली खामेनेई को अपने बेटे की काबिलियत पर शक था। 56 साल के मुजतबा ने इस पद से पहले कभी किसी सरकारी ओहदे पर काम नहीं किया। वह हमेशा अपने पिता के करीबी घेरे में रहकर पर्दे के पीछे से सत्ता चलाते थे। अमेरिकी दस्तावेजों में उन्हें पर्दे के पीछे की असली ताकत बताया गया है। उन पर पहले भी बुनावों में धांधली करने के आरोप लग चुके हैं। इस्राइली सेना ने भी साफ कर दिया है कि जो भी ईरानी नेता आतंकवाद को बढ़ावा देगा, वह उनके निशाने पर रहेगा।

ओमान के सबसे बड़े बंदरगाह के तेल भंडारण केंद्रों पर ईरानी ड्रोन हमला

मरकट, एजेंसी। ईरान ने ओमान के सबसे बड़े बंदरगाह सलालाह के तेल भंडारण केंद्रों पर ड्रोन हमला किया। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया

है। ओमान टीवी ने बताया कि ड्रोन ने बंदरगाह के अंदर बने ईंधन टैंकों को निशाना बनाया। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा कंपनी एम्ब्रे ने भी तेल भंडारण केंद्रों पर हुए हमले की पुष्टि की है। कंपनी ने कहा कि इस हमले में किसी व्यापारी जहाज को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है।

शरीर पर कपड़े, फिर भी नग्न कहलाते हैं सरकारी बाबू?

बीजिंग, एजेंसी। चीन में राष्टपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और जासूसी को रोकने के लिए नेकेड ऑफिशियल्स के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। यह शब्द उन रसूखदार अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो खुद तो चीन के ऊंचे पदों पर बैठे हैं लेकिन उनका पूरा परिवार (पत्नी और बच्चे) विदेश में सेटल है। चीनी भाषा में इन्हें लुओ गुआन कहा जाता है। सरल शब्दों में समझें तो अगर कोई बड़ा सरकारी अधिकारी चीन में अकेला रह रहा है और उसका परिवार विदेश में नौकरी कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है तो उसे नेकेड ऑफिशियल माना जाता है। इन्हें नग्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीन की धरती पर इनका कोई पारिवारिक बंधन या जड़ें शेष नहीं रह जातीं। इनका सारा पैसा और मोह विदेश में होता है। चीन सरकार का मानना है कि ऐसे अधिकारी देश की सुरक्षा के लिए टाइम बम की तरह हैं।

होर्मुज में ईरान की नौसेना पर अमेरिका का वार जारी', ट्रंप बोले- 58 जहाज और बारूदी नावों को किया नष्ट

वॉशिंगटन, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की नौसैनिक ताकत पर बड़ा हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई में ईरान के कई जहाज और बारूदी सुरंग बिछाने वाली नावों को नष्ट कर दिया गया है। उनका कहना है कि यह कदम वैश्विक समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत निर्णायक सैन्य कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के तहत की जा रही है। ट्रंप के मुताबिक इस अभियान का उद्देश्य ईरान से पैदा हो रहे खतरे को खत्म करना है। उनका दावा है कि अमेरिकी सेना ने कम समय में ही ईरान की कई सैन्य क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुंचाया है।

ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना को

जानकारी मिली थी कि ईरान समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा है। इन सुरंगों का मकसद जहाजों को नुकसान पहुंचाना और समुद्री रास्तों को बाधित करना था। उन्होंने कहा कि इसी खतरे को देखते हुए अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी हमलों में ईरान के कई माइन बिछाने वाले जहाज और नौसैनिक पोत नष्ट कर दिए गए हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज क्षेत्र में ईरान के कुल 58 नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा बारूदी सुरंग बिछाने वाली कम से कम 31 नावों को भी खत्म किया गया है। उनके मुताबिक यह कार्रवाई बेहद तेजी से की गई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने विशेष तकनीक और हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इन जहाजों को निशाना बनाया। ट्रंप ने दावा किया कि पिछले 11 दिनों की सैन्य कार्रवाई में ईरान की सैन्य ताकत को बड़ा झटका लगा है। उनके मुताबिक ईरान की वायुसेना लगभग खत्म हो चुकी है और उसके रडार सिस्टम भी नष्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता लगभग 90 प्रतिशत और ड्रोन क्षमता करीब 85 प्रतिशत तक कमजोर हो चुकी है। ट्रंप के अनुसार अमेरिकी सेना ईरान के हथियार बनाने वाले कारखानों को भी निशाना बना रही है। वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता आई है। इसे देखते हुए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दुनिया के विभिन्न देशों के रणनीतिक भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने पर सहमति जताई है। ट्रंप के मुताबिक इससे तेल की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखा जा सकेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस संघर्ष को अधूरा नहीं छोड़ेगा। उनका कहना है कि अगर खतरे को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया तो भविष्य में फिर से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाती रहेगी।

मंडराते संकट को दूर करने ट्रंप ने उठाया कदम

यूएस-ईरान युद्ध के बीच हांफने लगा अमेरिका

वॉशिंगटन , एजेंसी। ईरान के साथ जारी युद्ध के कारण बढ़ती पेट्रोल कीमतों के बीच मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला संकेतित किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भंडार से कुछ मात्रा में तेल निकाला जाएगा ताकि बाजार में राहत मिल सके। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि कुल कितने बैरल तेल जारी किए जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि बाद में इस भंडार को फिर से भर दिया जाएगा। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार एक आपातकालीन तेल भंडार है, जिसे ऊर्जा संकट या युद्ध जैसी स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। जब वैश्विक बाजार में तेल की कमी होती है या कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तब सरकार इस भंडार से तेल जारी करके बाजार में आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश करती है। इससे कीमतों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है।

ट्रंप ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि सरकार तेल के रणनीतिक भंडार का इस्तेमाल करेगी और इससे कीमतों में कमी लाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल भंडार से कुछ मात्रा में तेल निकाला जाएगा ताकि बाजार में राहत मिल सके। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि कुल कितने बैरल तेल जारी किए जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि बाद में इस भंडार को फिर से भर दिया जाएगा। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार एक आपातकालीन तेल भंडार है, जिसे ऊर्जा संकट या युद्ध जैसी स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। जब वैश्विक बाजार में तेल की कमी होती है या कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तब सरकार इस भंडार से तेल जारी करके बाजार में आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश करती है। इससे कीमतों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मोर्टार शेल फटने से पांच की मौत

इस्लामाबाद, एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ने बुधवार को बताया कि उनके देश की नीतियों की आलोचना को लेकर दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने अमेरिका के नए राजदूत को स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच जारी कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी राजदूत लियो ब्रेंट बोजेल तृतीय ने मंगलवार को कारोबारी नेताओं की एक बैठक में कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, जिन्होंने अफ्रीकी सरकार को नाराज कर दिया है। अमेरिकी राजदूत ने दक्षिण अफ्रीका सरकार के ईरान के साथ उनके कूटनीतिक संबंधों और अस्थेत समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए लागू सकारात्मक भेदभाव (अफर्मेटिव एक्शन) कानूनों पर सवाल उठाए। इन कानूनों का उद्देश्य अश्वेत लोगों को अन्य नस्लों की तुलना में अधिक अवसर प्रदान करना है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच मतभेद तब से बढ़ गए हैं जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में लौटे हैं। ट्रंप दक्षिण अफ्रीका की अश्वेत नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति अमेरिका विरोधी है, जबकि देश की घरेलू नीतियां श्वेत समुदाय के खिलाफ हैं। रूढ़िवादी कार्यकर्ता और ट्रंप द्वारा नियुक्त लियो ब्रेंट बोजेल तृतीय ने पिछले महीने प्रिटोरिया में अमेरिकी राजदूत के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। इस हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इस घटना के बाद देश के सभी तेल केंद्रों पर कामकाज रोक दिया गया है। इराक की सरकारी पोर्ट कंपनी के महानिदेशक फरहान अल-फरतौसी ने एक बयान में इसकी पुष्टि की।

अमेरिका ने पाकिस्तान में बंद किया अपना वाणिज्य दूतावास

हर साल 75 लाख डॉलर की होगी बचत

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर में स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया है। यह राजनयिक मिशन अफगानिस्तान सीमा के सबसे करीब था। साल 2001 में अफगानिस्तान पर हमले के समय और उसके बाद भी यह जगह अमेरिका के लिए ऑपरेशंस और रसद का मुख्य केंद्र रही है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस हफ्ते कांग्रेस को वाणिज्य दूतावास बंद करने की योजना के बारे में बताया। विभाग का कहना है कि इस कदम से हर साल लगभग 75 लाख डॉलर की बचत होगी। अमेरिका का मानना है कि इस फैसले से पाकिस्तान में उसके राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की क्षमता पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। 'द एसोसिएटेड प्रेस' को मिले एक नोटिस से यह जानकारी सामने आई है। यह फैसला पिछले एक साल से विचाराधीन था। ट्रंप प्रशासन ने लगभग सभी सरकारी ऐजेंसियों के खर्चों और आकार को छोटा करना शुरू किया है। विभाग ने साफ किया है

कि इस फैसले का ईरान के साथ चल रहे तनाव से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि, ईरान विवाद की वजह से कराची और पेशावर जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिस कारण वाणिज्य दूतावास ने कुछ समय के लिए अपना काम रोक दिया था। पिछले साल अमेरिकी प्रशासन ने विदेश विभाग के बजट में बड़ी कटौती की थी। इस दौरान हजारों राजनयिकों को हटाया गया और अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के स्टाफ में भी भारी कमी की गई। पेशावर वाणिज्य दूतावास पहला ऐसा विदेशी मिशन है, जिसे विभाग के पुनर्गठन की वजह से पूरी तरह बंद किया जा रहा है। नोटिस के अनुसार, पेशावर वाणिज्य दूतावास में 18 अमेरिकी राजनयिक और अन्य सरकारी अधिकारी काम करते हैं। इनके साथ ही 89 स्थानीय कर्मचारी भी वहां तैनात हैं। इस मिशन को पूरी तरह बंद करने में करीब 30 लाख डॉलर का खर्च आएगा। इस रकम का आधा हिस्सा यानी 18 लाख डॉलर उन बख्तरबंद ट्रेलरों को दूसरी जगह ले जाने में खर्च होगा, जो वहां ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे।

बाकी पैसा गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों और ऑफिस के फर्नीचर को इस्लामाबाद, कराची और लाहौर भेजने में इस्तेमाल होगा। अफगानिस्तान सीमा और काबुल के पास होने की वजह से पेशावर वाणिज्य दूतावास बहुत महत्वपूर्ण था। यह उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में अमेरिकी नागरिकों और मदद चाहने वाले अफगान लोगों के लिए संपर्क का बड़ा जरिया था।

यूएस में टैरिफ पर नए दांव-पेंच: क्या 52 साल पुराने कानून में हो सकते हैं बदलाव

ट्रंप प्रशासन ने शुरू की जांच

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व टैरिफ व्यवस्था को रद्द किए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने विदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर नई व्यापार जांच शुरू कर दी है। इस कदम को उन अरबों डॉलर के राजस्व की भरपाई की कोशिश माना जा रहा है जो अदालत के फैसले के बाद सरकार को खोना पड़ा। अमेरिकी प्रशासन ने बुधवार को ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत यह जांच शुरू की है। इस प्रक्रिया के तहत विदेशी कंपनियों और देशों की औद्योगिक नीतियों की जांच की जाएगी, जिसके बाद उन पर नए आयात शुल्क (टैरिफ) लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार की नीति में बदलाव नहीं हुआ है, केवल इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी उद्योग और नौकरियों की सुरक्षा करना है। नई जांच के दायरे में कई बड़े व्यापारिक साझेदार देश शामिल हैं। इनमें भारत, चीन, यूरोपीय संघ, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मेक्सिको और ताइवान जैसे देश शामिल

हैं। अमेरिकी सरकार इन देशों की उन नीतियों की जांच करेगी जिनसे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो सकता है। इसमें औद्योगिक सब्सिडी, मजदूरी दमन और अमेरिकी बाजार में लगातार व्यापार अधिशेष जैसे मुद्दों को देखा जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस जांच के बाद नए टैरिफ लागू होते हैं तो वैश्विक व्यापार में फिर तनाव बढ़ सकता है। इससे पहले लगाए गए टैरिफ के कारण अमेरिका और उसके कई व्यापारिक साझेदारों के बीच तीखी आर्थिक खींचतान देखने को मिली थी। हालांकि ग्रीर ने कहा कि पिछले साल घोषित व्यापार ढांचे अपने आप में अलग हैं और नई जांच उनसे सीधे जुड़ी नहीं है। फिर भी इन समझौतों को ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय लिया जा सकता है।

ट्रंप प्रशासन ने सेक्शन 301 के तहत एक और जांच शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य जबरन श्रम से बनाए गए उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की संभावनाओं का आकलन करना है। इसके अलावा डिजिटल सेवा कर, दवाओं की कीमत और समुद्री प्रदूषण जैसे मुद्दों पर भी भविष्य में नई जांच शुरू हो सकती है।

● सुरक्षा और तेल की कीमतों को लेकर चिंता

ईरान पर सैन्य कार्रवाई सही, घर में घिरे ट्रंप, सर्वे में अमेरिका के लोगों का चौंकाने वाला खुलासा

वॉशिंगटन, एजेंसी। ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिका में जनता की राय बंटी हुई है। नए सर्वे बताते हैं कि अधिकांश अमेरिकी इस कदम के पक्ष में नहीं हैं और उन्हें डर है कि इससे देश पहले से अधिक असुरक्षित हो सकता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण भी साफ दिख रहा है जहां रिपब्लिकन मतदाता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के साथ खड़े हैं, वहीं डेमोक्रेट और स्वतंत्र मतदाता चिंता और विरोध में हैं। क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी के सर्वे में लगभग 53% रजिस्टर्ड वोटर्स ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विरोध किया, जबकि 40% ने समर्थन किया और 10% ने स्पष्ट राय नहीं दी। इप्सोस, वाशिंगटन पोस्ट और इप्हह के सर्वे में भी यही रुझान दिखा कि अधिकांश अमेरिकी इस कदम के पक्ष में नहीं हैं। इसके विपरीत, फॉक्स न्यूज के सर्वे में मत लगभग बराबर बंटा हुआ दिखा, जहां आधे मतदाताओं ने समर्थन किया और आधे ने विरोध। क्विनिपियाक के सर्वे में 55% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान ने अमेरिका के लिए तत्काल कोई सैन्य खतरा

पैदा किया। वहीं, फॉक्स न्यूज के सर्वे में 60% मतदाताओं ने माना कि ईरान अमेरिका के लिए वास्तविक खतरा है। अमेरिकियों को तेल और गैस की कीमत बढ़ने का डर भी सताता है। इप्सोस के 6-9 मार्च सर्वे में लगभग दो-तिहाई लोगों ने कहा कि आने वाले एक साल में पेट्रोल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। रिपब्लिकन मतदाताओं में भी इस बात की चिंता देखी गई।

क्विनिपियाक और फॉक्स न्यूज के अनुसार लगभग आधे मतदाता मानते हैं कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई से अमेरिका कम सुरक्षित हो सकता है, जबकि लगभग 30% का मानना है कि इससे देश सुरक्षित हुआ। इप्हह के सर्वे में करीब 60% लोगों ने ट्रंप पर भरोसा कम या बिल्कुल नहीं होने की बात कही। शिकागो यूनिवर्सिटी के एनओआरसी सर्वे में भी 56% अमेरिकी विदेशों में सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप के फैसलों पर भरोसा कम दिखा रहे हैं। क्विनिपियाक के सर्वे में तीन-चौथाई मतदाता ईरान में अमेरिकी जमीनी सैनिक भेजने के खिलाफ हैं। केवल 20% लोग इस कदम के पक्ष में हैं। रिपब्लिकन मतदाताओं में भी 52% सैनिक भेजने के खिलाफ हैं।

यूएसएन ईरान के चक्कर में फंसा स्पेन, ट्रंप बोले- सैन्य ठिकाने इस्तेमाल नहीं करने दिए तो बंद कर सकते हैं व्यापार

वॉशिंगटन, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगी देश स्पेन को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर स्पेन ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता है तो अमेरिका उसके साथ व्यापारिक संबंधों को सीमित या बंद करने पर विचार कर सकता है। ट्रंप का यह बयान अमेरिका और स्पेन के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव को दिखाता है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वाशिंगटन इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को जारी रखेगा और सहयोगी देशों से समर्थन की उम्मीद करता है। ट्रंप ने संकेत दिया कि स्पेन का रुख बदलने के लिए अमेरिका आर्थिक कदम भी उठा सकता है।

स्पेन ने अमेरिका के प्रस्ताव को क्यों ठुकराया?

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने स्पष्ट कहा है कि उनकी सरकार युद्ध का समर्थन नहीं करती। उन्होंने दोहराया कि स्पेन की नीति स्पष्ट है और वह युद्ध के खिलाफ खड़ा है। सांचेज ने कहा कि उनकी सरकार अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ खड़ी है और किसी भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगी।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और उसने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। उनके मुताबिक अमेरिकी हमलों से ईरान की सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई समुद्री जहाजों को नष्ट कर दिया है, जिनका इस्तेमाल बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए किया जाता था। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। उनका दावा है कि अमेरिकी कार्रवाई के बाद वहां हालात धीरे-धीरे स्थिर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की कई माइन बिछाने वाली नौकाओं को नष्ट कर दिया है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

पश्चिम एशिया संकट: यूएनएससी में उठी पड़ोसियों पर हमले रोकने की मांग

दुबई, एजेंसी। ईरान ने बुधवार को दुनिया के सबसे व्यस्त दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया। यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिका और इस्राइल तेहरान पर हमले कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर संस्था, सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया है। इसमें ईरान से अपने पड़ोसी देशों पर हमले तुरंत रोकने की मांग की गई है। इन हमलों से दुनिया भर में तेल की सप्लाई को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ईरान इन हमलों के जरिए अमेरिका और इस्राइल पर दबाव बनाना चाहता है ताकि 12 दिन पहले शुरू हुआ युद्ध खत्म हो सके। पेंटागन के अनुसार, युद्ध के पहले हफ्ते में ही अमेरिका को 11.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। सेना ने बताया कि युद्ध के पहले वीकेंड में अकेले हथियारों पर पांच अरब डॉलर खर्च हो गए। ईरान ने खाड़ी देशों के तेल क्षेत्रों और रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। उसने होर्मुज की खाड़ी से होने वाले व्यापार को भी रोक दिया है, जहां से दुनिया का 20 प्रतिशत तेल गुजरता है। इस संकट से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपने बड़ा फैसला लिया है। वह बाजार में 40 करोड़ बैरल तेल उतारेगी। अमेरिका भी अगले हफ्ते अपने सुरक्षित भंडार से 17.2 करोड़ बैरल तेल जारी करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें ईरान से खाड़ी पड़ोसियों पर

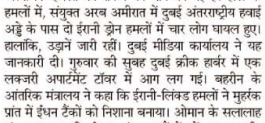

अत्यधिक हमलों को रोकने की मांग की गई है। हाल के हमलों में, संयुक्त अरब अमीरात में दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास दो ईरानी ड्रोन हमलों में चार लोग घायल हुए। हालांकि, उड़ानें जारी रहीं। दुबई मीडिया कार्यालय ने यह जानकारी दी। गुरुवार की सुबह दुबई क्रीक हार्बर में एक लक्जरी अपार्टमेंट टॉवर में आग लग गई। बहरीन के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि ईरानी-लिंक्ड हमलों ने मुहर्रक प्रांत में ईंधन टैंकों को निशाना बनाया। ओमान के सलालाह बंदरगाह पर भी ईंधन भंडारण टैंकों में आग लगी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन ईरानी हमलों को दृढ़ता से खारिज करता है। ये हमले संप्रभु देशों के खिलाफ हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थिरता को खतरे में डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली निकाय में 13-0 के वोट से ईरान की अलग-थलग स्थिति झलकती है। चीन और रूस ने मतदान से परहेज किया। उन्होंने प्रस्ताव को अत्यंत असंतुलित बताया। इस बीच, खाड़ी देशों में और हमलों की सूचना मिली। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में इरबिल और सुलेमानिया शहरों की ओर ड्रोन लॉन्च किए गए। इराक के दक्षिणी हिस्से में एक ऑस्ट्रेलियाई झंडे वाले तेल जहाज पर हमला हुआ। जहाज के 25 चालक दल को बचा लिया गया। गुरुवार को यरूशलम और इस्राअल के अन्य हिस्सों में सायरन बजे और जोरदार धमाके सुनाई दिए। इस्राअली सेना ने कहा कि वह तेहरान में बड़े पैमाने पर हमलों की एक और लहर के साथ जवाब दे रही थी। इस्राअल ने लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादियों से जुड़े ठिकानों पर भी हमला किया। बेरुत के रामलेट अल-बायदा में एक इस्राअली हमले में सात लोग मारे गए और 21 अन्य घायल हुए।

हर साल आईपीएल की शुरुआत देखना हमेशा रोमांचक होता है : हरभजन

नईदिल्ली (एजेंसी)। भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आईपीएल की शुरुआत हर बार क्रिकेट फैंस के लिए बेहद रोमांचक होती है और इस बार भी टूर्नामेंट में जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। हरभजन सिंह ने कहा कि आईपीएल में हर साल नए रोमांच और कड़ी टक्कर देखने को मिलती है, जो इसे दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग बनाती है। मीडिया से बातचीत करते हुए हरभजन सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी टूर्नामेंट में वही जुनून और उत्साह देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, आईपीएल की शुरुआत देखना हमेशा रोमांचक होता है। उम्मीद है कि इस साल भी हमें वही जोश, जुनून और मजा देखने को मिलेगा जो आईपीएल लेकर आता है। हम हर बार चाहते हैं कि कोई नई टीम ट्रॉफी जीते, लेकिन कुछ पुरानी टीमें काफी मजबूत हैं, इसलिए शानदार मुकाबले देखने को मिलेंगे।

टी20 वर्ल्ड कप

सूर्याकुमार यादव ने मानी गलती, एसए के खिलाफ इस अक्षर पटेल को ड्रॉप करना बड़ी गलती थी

मुंबई (एजेंसी)। भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2026 विजेता कप्तान सूर्याकुमार यादव ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में अक्षर पटेल को टीम से बाहर करने के फैसले के बाद उन्होंने उनसे माफी मांगी थी। सूर्याकुमार ने कहा कि अक्षर पटेल इस फैसले से नाराज थे, और उनका नाराज होना बिल्कुल जायज था। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जो अक्षर पटेल का होम ग्राउंड भी है।

अक्षर की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मिला मौका - साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मुकाबले में अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था। टीम मैनेजमेंट का मानना था कि सुंदर की गेंदबाजी लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के खिलाफ ज्यादा प्रभावी होगी। हालांकि यह फैसला भारत के लिए उल्टा साबित हुआ और टीम को 76 रन की बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार से भारत के नेट रन रेट पर भी असर पड़ा था।

सूर्याकुमार ने बताया क्या हुई थी बातचीत - सूर्याकुमार यादव ने एक इंटरव्यू में बताया कि अक्षर पटेल इस फैसले से काफी नाराज थे और उन्होंने खुद अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा- वह (अक्षर पटेल) बहुत गुस्से में थे और उन्हें गुस्सा होना भी चाहिए था। वह एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और फ्रेंचाइजी टीम की कप्तानी भी करते हैं। सूर्या ने आगे कहा- मैंने उनसे माफी मांगी। मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई और मुझे इसका अफसोस है। लेकिन यह फैसला टीम के लिए लिया गया था। यह बातचीत आसान नहीं थी, लेकिन अगले दिन हमने इसे अच्छे से सुलझा लिया।

टीम में वापसी के बाद अक्षर का प्रदर्शन - साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ अहम मुकाबले में अक्षर पटेल की टीम में वापसी हुई। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 35 रन देकर एक विकेट लिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में उन्होंने 4 ओवर में 35 रन दिए, हालांकि बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला क्योंकि संजू सैमसन की नाबाद 97 रन की पारी से भारत जीत गया। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में अक्षर ने टॉप बैटन का विकेट लिया और दो शानदार कैच भी पकड़े।

फाइनल में भी अक्षर ने निभाई अहम भूमिका - न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अक्षर पटेल का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने 3 ओवर में 27 रन देकर फिन एलन, ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल जैसे बड़े बल्लेबाजों को आउट किया। अक्षर की इस शानदार गेंदबाजी ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।

10वीं रैंक वाले बांग्लादेश से हारा पाकिस्तान

दिग्गजों ने उड़ाई टीम की धज्जियां

कराची (एजेंसी)। पाकिस्तान टीम के खराब प्रदर्शन के बाद पूर्व खिलाड़ी बासित अली और कामरान अकमल ने टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने पावरप्ले रणनीति, खराब बल्लेबाजी और एक साथ चार डेब्यू खिलाड़ियों को मौका देने के फैसले पर सवाल उठाए। टी20 विश्व कप 2026 में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी टीम बड़े बदलाव और बड़ी उम्मीदों के साथ बांग्लादेश दौरे पर गई। पाकिस्तान के नए वनडे कप्तान शाहीन अफरीदी के नेतृत्व में टीम को बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले वनडे में ही आठ विकेट से करारी शिकस्त मिली। पाकिस्तान टीम की इस हार के बाद वहां के दिग्गजों ने अपनी ही टीम की धज्जियां उड़ाई हैं। कामरान अकमल, बासित अली, फवाद आलम से लेकर फैंस तक ने टीम की खिल्ली उड़ाई और कहा कि जिस टैलेंट की बात पाकिस्तान क्रिकेट में इतने दिनों से की जा रही थी, क्या यही वो टैलेंट हैं?

- **चौथी रैंक पर है पाकिस्तान** - सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग चार है, जबकि बांग्लादेश की वनडे रैंकिंग 10 है। बांग्लादेश की टीम अब तक 2027 वनडे विश्वकप के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई है। उसे वनडे विश्वकप के लिए ऑटोमैटिक क्वालिफाई करने के लिए 31 मार्च, 2027 तक रैंकिंग में शीर्ष-आठ में आना जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो टीम को क्वालिफायर्स खेलना होगा। उस बांग्लादेशी टीम से पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। मैच के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने टीम का मजाक उड़ाया। पूर्व ऑलराउंडर फवाद आलम ने ट्विटर पर लिखा, क्या इन्हें ही हम टैलेंट कहते हैं?

बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आठ विकेट से हराया

दरअसल, रोड टू 2027 वर्ल्ड कप के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश ने तीन मैचों की वनडे सीरीज से अपनी तैयारी शुरू की है। दोनों के बीच 11 मार्च को ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में सीरीज का पहला वनडे खेला गया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हु 30.4 ओवर में 114 रन बनाए और सभी 10 विकेट गंवा दिए। इसके बाद बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान की पारी के आधे ओवर में सिर्फ दो विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। बांग्लादेश ने 15.1 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। अब दूसरा वनडे 13 मार्च को ढाका में ही खेला जाएगा।

अकमल का आईसीसी रैंकिंग पर भी तंज

अकमल ने पाकिस्तान की आईसीसी रैंकिंग पर भी तंज कसते हुए कहा कि घरेलू मैदान पर कमजोर टीमों को हराकर रैंकिंग में ऊपर रहना ज्यादा मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा, हम घर पर कमजोर टीमों को हराकर अंक जुटाते हैं, लेकिन जब विदेश जाते हैं तो असली तस्वीर सामने आ जाती है। मार्च 2026 में बांग्लादेश दौरे के लिए पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में 15-सदस्यीय वनडे टीम की घोषणा की थी। टीम में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम, फखर जमां, सैम अयूब, मोहम्मद नवाज और नसीम शाह को बाहर कर दिया गया।

- **पाकिस्तान टीम** - शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, माज सदाकत, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), साद मसूद, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा और शमील हुसैन।

रणनीति पर बासित अली का तीखा हमला

पाकिस्तान टीम के खराब प्रदर्शन के बाद पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बासित अली ने टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने खास तौर पर पावरप्ले में 10 ओवर में 60 रन बनाने की रणनीति पर सवाल उठाए। बासित अली ने कहा, सबसे पहले उस आदमी को हटाना चाहिए जिसने खिलाड़ियों से कहा कि पावरप्ले के 10 ओवर में कम से कम 60 रन बनाओ। उसने कभी मैदान पर क्रिकेट खेली ही नहीं होगी, बस कागज पकड़ाकर दे देता है। क्या उसे यहां की परिस्थितियों का अंदाजा नहीं था? क्या उसे नहीं पता कि यहां भारत जैसी टीम भी बांग्लादेश में हार चुकी है? बासित अली ने टीम में एक साथ चार डेब्यू खिलाड़ियों को मौका देने के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, एक या दो नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है, लेकिन चार को एक साथ उतारना सही फैसला नहीं है।

एक टीम इंटरनेशनल, दूसरी क्लब टीम जैसी

पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर कामरान अकमल भी टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश नजर आए। उन्होंने कहा कि मैच में दोनों टीमों के स्तर में साफ फर्क दिख रहा था। अकमल ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे एक टीम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है और दूसरी टीम वर्ल्ड कप से पहले कोई प्रैक्टिस मैच खेल रही क्लब टीम हो। मैंने बासित को फोन किया, लेकिन मेरे पास यह बताने के लिए शब्द नहीं थे कि हम कैसी क्रिकेट खेल रहे थे।

क्लब क्रिकेट में भी ऐसा नहीं होता

अकमल ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इतना खराब प्रदर्शन तो क्लब क्रिकेट में भी नहीं देखने को मिलता। उन्होंने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं कि इस तरह की बल्लेबाजी क्लब क्रिकेट में भी नहीं होती। क्लब के खिलाड़ी भी इतनी खराब बल्लेबाजी नहीं करते।

नाहिद राणा के खिलाफ बल्लेबाजी पर सवाल

अकमल ने खास तौर पर नाहिद राणा की गेंदबाजी के खिलाफ पाकिस्तान के बल्लेबाजों के रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमारे सभी बल्लेबाज बैकफुट पर खेल रहे थे। कोई भी आगे बढ़कर नहीं खेला। रिजवान सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्हें समझदारी दिखानी चाहिए थी और आगे निकलकर शॉट लगाना चाहिए था, लेकिन उन्हें दो बार कट लगा और वह आउट हो गए। अकमल ने यह भी कहा कि राणा ने विकेट लेने के बाद ज्यादा जश्न भी नहीं मनाया।

बीसीसीआई ने गिल को चुना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर?

सचिन-अश्विन की इस मामले में करेंगे बराबरी

मुंबई (एजेंसी)। बीसीसीआई के वार्षिक सम्मान समारोह में शुभमन गिल को 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर' चुने जाने की संभावना है। टेस्ट और वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाले गिल ने साल भर में 1,764 रन बनाए। वहीं राहुल द्रविड़ को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को सर्वश्रेष्ठ संघ का सम्मान मिल सकता है। भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल को साल 2025 के लिए बीसीसीआई के प्रतिष्ठित क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार को पॉली उमरीगर क्रिकेट ऑफ द ईयर अवॉर्ड भी कहा जाता है। वहीं, राहुल द्रविड़ भी लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजे जा सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का वार्षिक सम्मान समारोह नमन 15 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में कई खिलाड़ियों और क्रिकेट हस्तियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा।

सचिन-अश्विन की बराबरी करेंगे - शुभमन दूसरी बार यह पुरस्कार जीतेंगे। इससे पहले साल 2023 में भी उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरी बार यह अवॉर्ड जीतने के साथ ही शुभमन सचिन तेंदुलकर और रविचंद्रन अश्विन की बराबरी कर लेंगे। इन तीनों ने भी यह अवॉर्ड दो-दो बार जीता था। इन तीनों से ज्यादा बार इस अवॉर्ड से विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह ही सम्मानित हुए हैं।

टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन

26 वर्षीय शुभमन ने पिछले साल यानी 2025 टेस्ट और वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि, उन्हें हाल ही में टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी, लेकिन बाकी दो फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन बेहद दमदार रहा। शुभमन ने 2025 में टेस्ट क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 983 रन बनाए। इसमें इंग्लैंड के खिलाफ उसकी सरजमीं पर खेली गई सीरीज में 754 रन शामिल रहे, जो उनकी बेहतरीन फॉर्म को दर्शाता है। इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज में उनका औसत 70 से अधिक रहा और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पारियां खेलीं।

वनडे और आईपीएल में भी दमदार फॉर्म

वनडे क्रिकेट में भी गिल ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कुल 490 रन बनाए, जिसमें भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली मुहिम में बनाए गए 188 रन भी शामिल हैं। अगर सभी फॉर्मेट को मिलाकर देखा जाए तो गिल ने पिछले साल कुल 1,764 रन बनाए, जिनमें सात शतक और तीन अर्धशतक शामिल रहे। उनका औसत करीब 49 का रहा।

आईपीएल 2026- IPL का कार्यक्रम जारी

पहले चरण के 20 मुकाबलों में चार डबल-हेडर, आरसीबी और एसआरएच के बीच ओपनिंग मैच

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल 2026 के पहले चरण का कार्यक्रम जारी हो चुका है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को 19वें सीजन के शुरुआती मुकाबलों का कार्यक्रम घोषित किया। दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 फ्रेंचाइजी लीग का यह सीजन 28 मार्च से शुरू होगा और पहले चरण के मुकाबले 12 अप्रैल तक खेले जाएंगे।

बंगलूरू में होगा उद्घाटन मुकाबला - टूर्नामेंट का पहला मैच 28 मार्च को बंगलूरू के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) से होगा। आरसीबी की टीम इस बार अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। आरसीबी ने 2025 में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था। उद्घाटन मैच के अगले दिन रविवार को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।

आईपीएल 2026 के पहले चरण का कार्यक्रम

मैच	टीम 1	टीम 2	जगह	तारीख
1	रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु	सनराइजर्स हैदराबाद	बंगलूरू	28 मार्च
2	मुंबई इंडियंस	कोलकाता नाइट राइडर्स	मुंबई	29 मार्च
3	राजस्थान रॉयल्स	चेन्नई सुपर किंग्स	गुवाहाटी	30 मार्च
4	पंजाब किंग्स	गुजरात टाइटंस	न्यू चंडीगढ़	31 मार्च
5	लखनऊ सुपर जाएंट्स	दिल्ली कैपिटल्स	लखनऊ	1 अप्रैल
6	कोलकाता नाइट राइडर्स	सनराइजर्स हैदराबाद	कोलकाता	2 अप्रैल
7	चेन्नई सुपर किंग्स	पंजाब किंग्स	चेन्नई	3 अप्रैल
8	दिल्ली कैपिटल्स	मुंबई इंडियंस	दिल्ली	4 अप्रैल
9	गुजरात टाइटंस	राजस्थान रॉयल्स	अहमदाबाद	4 अप्रैल
10	सनराइजर्स हैदराबाद	लखनऊ सुपर जाएंट्स	हैदराबाद	5 अप्रैल
11	रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु	चेन्नई सुपर किंग्स	बंगलूरू	5 अप्रैल
12	कोलकाता नाइट राइडर्स	पंजाब किंग्स	कोलकाता	6 अप्रैल
13	राजस्थान रॉयल्स	मुंबई इंडियंस	गुवाहाटी	7 अप्रैल
14	दिल्ली कैपिटल्स	गुजरात टाइटंस	दिल्ली	8 अप्रैल
15	कोलकाता नाइट राइडर्स	लखनऊ सुपर जाएंट्स	कोलकाता	9 अप्रैल
16	राजस्थान रॉयल्स	रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु	गुवाहाटी	10 अप्रैल
17	पंजाब किंग्स	सनराइजर्स हैदराबाद	न्यू चंडीगढ़	11 अप्रैल
18	चेन्नई सुपर किंग्स	दिल्ली कैपिटल्स	चेन्नई	11 अप्रैल
19	लखनऊ सुपर जाएंट्स	गुजरात टाइटंस	लखनऊ	12 अप्रैल
20	मुंबई इंडियंस	रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु	मुंबई	12 अप्रैल

खिताब बचाने उतरेगी आरसीबी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने 2025 में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। आरसीबी की टीम इस बार खिताब का बचाव करने उतरेगी।

बंगलूरू के मैचों पर अंतिम फैसला बाकी

बंगलूरू में होने वाले मैच फिलहाल राज्य सरकार की विशेषज्ञ समिति की मंजूरी पर निर्भर करेंगे। कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी 13 मार्च 2026 को एम. चित्रास्वामी स्टेडियम का निरीक्षण करेगी। इस दौरान मैच डे की तैयारियों का पूरा मॉक डेमो किया जाएगा, जिसके बाद ही यह तय होगा कि स्टेडियम आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है या नहीं।

जैक ड्रेपर ने पांच बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराया, क्वार्टर फाइनल में पहुंचें

इंडियन वेल्स (अमेरिका) (एजेंसी)। मौजूदा चैंपियन जैक ड्रेपर ने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करके बीएनपी पारिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट के चौथे दौर में पांच बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को 4-6, 6-4, 7-6 (5) से हराया। हाथ की चोट के कारण आठ महीने तक बाहर रहने के बाद वापसी करने वाले 24 वर्षीय ड्रेपर इस जीत से क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं जहां उनका मुकाबला दानिल मेदवेदेव से होगा। मेदवेदेव ने एक अन्य मैच में एलेक्स मिशेलसन को 6-2, 6-4 से पराजित किया। तीसरे सेट में जोकोविच 6-5 से आगे थे, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाए और ड्रेपर ने वापसी करते हुए मैच को टाईब्रेकर तक पहुंचा दिया। ड्रेपर ने मैच के बाद कहा, मुझे अब भी ऐसा नहीं लगता कि मैं उस तरह से खेल रहा हूं जैसा मैं खेलना चाहता हूं। लेकिन मैं अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। रिकॉर्ड 24 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन 38 वर्षीय जोकोविच ने 2008, 2011, 2014, 2015 और 2016 में इंडियन वेल्स में खिताब जीता था। जोकोविच इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अपना 11वां खिताब जीतने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन फाइनल में कार्लोस अल्काराज़ से हार गए थे।

केकेआर के पूर्व तेज गेंदबाज पर लगा मैच फिक्सिंग का आरोप, जैवन सियरल्स समेत 3 पर कार्रवाई

बारबाडोस (एजेंसी)। बारबाडोस में खेले गए बिम टी-20 टूर्नामेंट 2023-24 से जुड़ा एक बड़ा मैच फिक्सिंग मामला सामने आया है। इस मामले में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जैवन सियरल्स को क्रिकेट की सभी गतिविधियों से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। सियरल्स के अलावा टाइटस टीम के मालिक चित्रंजन राठौड़ और टीम अधिकारी ट्रेवोन ग्रिफिथ को भी भ्रष्टाचार विरोधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया है।

आईपीएल में केकेआर के लिए खेल चुके हैं सियरल्स - जैवन सियरल्स इससे पहले आईपीएल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) टीम का हिस्सा रह चुके हैं। वेस्टइंडीज के इस तेज गेंदबाज ने घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कई टूर्नामेंट खेले हैं। हालांकि अब उन पर मैच के नतीजे या खेल की प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा है।

- **आईसीसी और सीडब्ल्यूआई के एंटी करप्शन कोड के तहत आरोप** - क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) और आईसीसी के एंटी-करप्शन कोड के तहत तीनों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चित्रंजन राठौड़ पर 3 उल्लंघनों के आरोप हैं। जैवन सियरल्स और ट्रेवोन ग्रिफिथ पर 4-4 उल्लंघनों के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में मैच फिक्सिंग की साजिश रचना, खिलाड़ियों या स्टाफ को भ्रष्ट गतिविधियों के लिए उकसाना और जांच में सहयोग न करना शामिल है।

टी20 विश्व कप विजेता जसप्रीत बुमराह ने कहा

दबाव वाली परिस्थितियों में जिम्मेदारी लेना पसंद है

अहमदाबाद (एजेंसी)। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टी20 विश्व कप में खिताब का बचाव करना अपने करियर के सबसे संतोषजनक अनुभवों में से एक करार देते हुए कहा कि उन्हें दबाव वाली परिस्थितियों में जिम्मेदारी लेना अच्छा लगता है। बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में चार विकेट लेकर भारत की 96 रन से जीत में अहम भूमिका निभाई। इससे भारत टी20 विश्व कप में अपने खिताब का बचाव करने और तीन बार यह ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें बुमराह ने कहा, मैं पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहता हूं। मैं हमेशा सक्रिय रूप से भाग लेना चाहता हूं। मुझे शुरू से ही चुनौतियां पसंद हैं। बुमराह को फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। उन्होंने कहा, मैंने क्रिकेट इसी मकसद से खेला है। मैंने क्रिकेट खेलना इसी मकसद से शुरू किया था। जब मैं कुछ बदलाव लाता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। इससे बेहतर कोई अहसास नहीं है।

गुजरात में जन्में इस तेज गेंदबाज के लिए यह जीत भावनात्मक रूप से और भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह जीत उसी स्थान पर मिली जहां से उनके क्रिकेट करियर की शुरुआत हुई थी। बुमराह ने कहा, मैंने यहीं से क्रिकेट खेलना शुरू किया। मैंने अपना अधिकतर क्रिकेट यहीं खेला है। मैं यहीं गुजरात के लिए खेलते हुए आगे बढ़ा। यहीं विश्व कप जीता और मैन ऑफ द मैच बना। पिछली बार (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे विश्व कप 2023 का फाइनल) हम बस थोड़ा सा चूक गए थे, लेकिन इस बार जीत हासिल करने में सफल रहे।